इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2018—आश्विन 6, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-(ए)108-1986-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 अगस्त से 15 सितम्बर 2018 तक सत्ताईस दिवस अर्जित अवकाश स्वीकृत करता है.

(2) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, का चालू कार्य श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, (पुलिस सुधार) पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मैथिलीशरण गुप्त, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2018

फा. क्र. 4184-2018-इक्कीस-ब (एक).—न्यायिक सेवा की सदस्य श्रीमती गरिमा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (ट्रेनी जज) जिला अशोकनगर के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा परिवीक्षा अवधि का निर्वहन संतोषजनक एवं सफलतापूर्वक नहीं कर पाने के कारण उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रशासनिक समिति की बैठक दिनांक 7 अगस्त 2018 एवं फुलकोर्ट मीटिंग में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में उक्त न्यायिक अधिकारी को सेवा से मुक्त (Discharge from Service) करने की अनुशंसा की गई है.

उक्त न्यायिक अधिकारी के संबंध में उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की अनुशंसा से सहमत होते हुए राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि श्रीमती गरिमा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (ट्रेनी जज) जिला अशोकनगर के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश को आदेश दिनांक से सेवामुक्त (Discharge from Service) किया जाए.

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील), नियम 1994 के नियम 11(सी) के अंतर्गत एतद्द्वारा, राज्य शासन श्रीमती गरिमा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (ट्रेनी जज) जिला अशोकनगर के न्यायालय की प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश को सेवामुक्त (Discharge from Service) करता है.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

फा. क्र. 4065-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, द्वारा जारी किये गये अपने समसंख्यक आदेश क्र. 3809-इक्कीस-ब (दो) दिनांक 12 सितम्बर 2017 द्वारा महाधिवक्ता के परामर्श से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त श्री एल. एन. सोनी, अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यकाल में दिनांक 11 सितम्बर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक की वृद्धि की जाती है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर यह संविदा समाप्त करने के लिये स्वतंत्र होंगे.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3 (ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 3514.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्रीमती पूजा गुप्ता (अग्रवाल) पुत्री श्री मोहन मधुर गुप्ता (मेरिट क्र. 39) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाए जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती पूजा गुप्ता (अग्रवाल) पुत्री श्री मोहन मधुर गुप्ता का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 39 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 3 (ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 3518.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री दीपनारायण तिवारी पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी (मेरिट क्र. 37) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दीपनारायण तिवारी पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 37 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

फा. क्र. 3 (ए) 2017-इक्कीस-ब (एक) 3522.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2017 की चयन सूची दिनांक 21 नवम्बर 2017 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा 2017, बार से सीधी भर्ती के पद पर चयनित अभ्यर्थी श्री लखन लाल तिवारी पुत्र श्री राज नारायण तिवारी (मेरिट क्र. 55) को नियुक्ति के लिये अपात्र पाये जाने के कारण, राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री लखन लाल तिवारी पुत्र श्री राज नारायण तिवारी का नाम चयनित जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) बार से सीधी भर्ती की मुख्य चयन सूची के मेरिट क्र. 55 से विलोपित कर उनका चयन का अधिकार समाप्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2018

फा. क्र. 1 (सी) 4041, 3681-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला मंडला के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) नियम, 1995 के नियम 4(1) के अंतर्गत श्री दीपक कछवाहा, अधिवक्ता (नामांकन क्र. एम. पी./1621/04, दिनांक 1 अगस्त 2004) को विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता नियुक्त करता है. श्री दीपक कछवाहा, अधिवक्ता की उक्त विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 12 अक्टूबर 1979 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री दीपक कछवाहा, अधिवक्ता, मंडला को ऐसे विशिष्ट ज्येष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

श्री दीपक कछवाहा, विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता मंडला को विशेष लोक अभियोजक की अनुपस्थिति के दिनांक पर विशेष न्यायालय में केवल उस दिन की कार्यवाही हेतु कार्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवंटित किया जायेगा.

फा. क्र. 4042, 3450-एट्रोसिटीज-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (क्र. 33 सन् 1989) की धारा 14 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय, जिला मंदसौर के लिये उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री भगवान सिंह चौहान, अधिवक्ता, (नामांकन क्र. एम. पी.-235-2000, दिनांक 2 जनवरी 2000) को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. श्री भगवानसिंह चौहान, अधिवक्ता की उक्त विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति आदेश दिनांक से 3 वर्ष की अवधि अथवा उनकी जन्म तिथि दिनांक 9 अक्टूबर 1972 के आधार पर उनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इनमें से जो पहले हो, के लिये होगी तथा यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी.

श्री भगवान सिंह चौहान, अधिवक्ता, मंदसौर को ऐसे विशेष लोक अभियोजक के रूप में कार्य के लिये देय शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी) एट्रोसिटी-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 3 नवम्बर 2014 के अनुरूप देय होंगे एवं इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा. जिसका भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल श्रीवास्तव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3060-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, नोटरी अधिनियम 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अंतर्गत एतद्द्वारा श्री हरिसिंह जाट, नोटरी, जिला श्योपुर को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण-पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 14 जुलाई 2021 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

फा. क्र. 3060-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, नोटरी अधिनियम 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अंतर्गत एतद्द्वारा श्री लक्ष्मण भैया चौहान, नोटरी, तहसील कराहल, जिला श्योपुर को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण-पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 3 मई 2022 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

फा. क्र. 3060-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, नोटरी अधिनियम 1952 (क्रमांक 53 सन् 1952) की धारा 10 के खण्ड (घ) सहपठित नोटरी नियम 1956 के नियम 13 के उपनियम (12) के खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) के अंतर्गत एतद्द्वारा श्री शंभूदयाल बंसल, नोटरी, जिला श्योपुर को तत्काल प्रभाव से उनके नोटरी व्यवसाय के वर्तमान प्रमाण-पत्र की विनिर्दिष्ट अवधि अर्थात् दिनांक 21 अगस्त 2023 तक की अवधि के लिये नोटरी व्यवसाय से निलंबित करता है.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2018

फा. क्र. 3976-इक्कीस-ब (दो).—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-3-1-3-08 दिनांक 11 अप्रैल 2006 द्वारा, राज्य शासन के सीधी भर्ती और पदोन्नति से भरे जाने वाले पद जिनका वेतनमान 6500—10500 है, को राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो घोषित किये जाने के फलस्वरूप, राज्य शासन, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत जिला विधिक सहायता अधिकारी के पद को राजपत्रित सेवा श्रेणी-दो घोषित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 अगस्त 2018

क्र. एफ-11-12-2018-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

2. अतएव मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्टस एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

3. किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक/स्थल अवशेष का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित होना है प्रतिवर्तित होना है.	क्षेत्रफल सीमांक	स्वामित्व	विशेष विवरण धार्मिक पूजा आदि.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	नीमच	सिंगौली	रतनगढ़	किला जंगलात	233	5.264 है.	म. प्र. शासन	—

क्र. एफ-11-12-2013-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-12-2013-तीस, दिनांक 22 जुलाई 2013 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गई थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

3. अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	अशोकनगर	चन्देरी	चन्देरी	ढोलिया दरवाजा कोट शहरपना.	ख. नं. 775, 776/1, 777, 778.	0.042, 0.095, 0.031, 0.010 है.	म. प्र. शासन	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्र. एफ 9-2-2008-बी-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-2-99-ब-16, दिनांक 11 अगस्त 2014 के अनुक्रम में मेसर्स इंडियन वर्क्स कॉ-आपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जबलपुर को उक्त अधिनियम के प्रावधान अन्तर्गत दिनांक 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 तक की अवधि के लिए इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को सोसायटी द्वारा दी जा रही सुविधायें कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी. सोसायटी द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहेबिलिटेशन अलाउन्स की सुविधा भी प्रदान की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रकान्त कश्यप, अवर सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

क्र. एफ-03-05-2018-तीन-जेल.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जेल मैन्युअल के नियम 815(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल के लिए श्री राजेन्द्र आगाल पुत्र स्व. श्री रामेश्वर आगाल, रायल वीला 211, सेक्टर 2, शक्ति नगर, भोपाल को आगामी तीन वर्षों के लिये अशासकीय संदर्शक नियुक्त करता है. राज्य शासन जनहित में इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय नथानियल, अवर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ-5-4-2012-अट्ठावन.—राज्य शासन, मधय्प्रदेश फल पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 8 (1) ख के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत बने मध्यप्रदेश फल-पौध रोपणी (विनियमन) नियम, 2011 के संदर्भ में पंजीकृत शासकीय/निजी क्षेत्र की रोपणियों से विक्रय किये जाने वाले निम्नांकित फल-पौधों की वर्ष 2018-19 के लिए अधिकतम दर कॉलम क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार घोषित करता है:—

क्रमांक	नाम फल-पौध	वर्ष 2018-19 में दर प्रति फल-पौध	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आम कलमी (सभी किस्में)	52/-	आरसीओ अनुसार
2	आम बीजू	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
3	अमरूद गूटी	34/-	आरसीओ अनुसार
4	अमरूद बडेड	34/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
5	अमरूद बीजू	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
6	अमरूद टिश्यूकल्चर	48/-	आरसीओ अनुसार
7	नींबू गूटी	48/-	आरसीओ अनुसार
8	नींबू बीजू	30/-	आरसीओ अनुसार
9	नींबू टिश्यूकल्चर	48/-	विगत वर्ष 2016-17
10	मौसम्बी बडेड	30/-	विगत वर्ष 2016-17
11	संतरा बडेड	30/-	आरसीओ अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)
12	कटहल बीजू	15/-	आरसीओ अनुसार
13	सीताफल बीजू	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
14	अनार गूटी	30/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
15	अनार ग्राफ्टेड	30/-	आरसीओ अनुसार
16	अनार टिश्यू कल्चर	30.90/-	आरसीओ अनुसार
17	जामुन बीजू	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
18	फालसा बीजू	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
19	शहतूत (रूटेट कटिंग)	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
20	ऑवला बडेड	30/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
21	ऑवला बीजू	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
22	चीकू (ग्राफ्टेड)	50/-	आरसीओ अनुसार
23	बेर बडेड	33/-	आरसीओ अनुसार
24	करौंदा बीजू	10/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
25	पपीता पौध बीजू (सभी उन्नत किस्में)	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
26	पपीता संकर किस्में बीजू	20/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
27	केला कन्द	10/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
28	केला टिश्यूकल्चर	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
29	लीची गूटी	50/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
30	अंगूर रूटेट कटिंग	15/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार
31	नाशपाती बडेड	25/-	विगत वर्ष 2016-17 अनुसार

उपरोक्त दरें आगामी अधिसूचना जारी/प्रकाशित होने तक प्रभावशील रहेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुप कुमार मुण्डा, अवर सचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2018

क्र. एफ-3-66-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1806-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 31 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित गंजबासौदा विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार गंजबासौदा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, भोपाल, संभाग भोपाल मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, विदिशा जिला विदिशा मध्यप्रदेश

3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, गंजबासौदा मध्यप्रदेश

4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, विदिशा, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	गंजबासौदा विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	6	सारणी 6-सा-11	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	सारणी 6-सा-11	07	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ-3-01-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक

2758-उपां-टीसी-जबलपुर-2017, दिनांक 18 मई 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण के ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	तिलहरी तह. जबलपुर जिला जबलपुर.	200/1	30.106 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेरयर.	कृषि	आवासीय (अटल आश्रय योजना हेतु).
2	ग्राम तिलहरी तह. जबलपुर, जिला जबलपुर.	230	14.119 हेक्टेयर में से 2.00 हेक्टेरयर	कृषि	आवासीय (अटल आश्रय योजना हेतु).
			कुल रकबा . . 4.0 हेक्टेयर		

1. किसी भी प्रकार की जल-मल निकासी तालाब की ओर प्रवाहित न की जावे.
2. स्थल पर पहुंच हेतु न्यूनतम 7.5 मीटर चौड़ा पहुंच मार्ग आवश्यक होगा.
3. उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-33-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 918-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 20 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित दमोह विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार दमोह निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, सागर, संभाग सागर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, दमोह जिला दमोह मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, दमोह मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, सागर मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका/ कॉलम क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	दमोह विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	4	सारणी 4-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कृषि	4	सारणी 4-सा-14	07	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-37-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1156-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 28 फरवरी 2018 द्वारा प्रकाशित रायसेन विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार रायसेन निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, रायसेन जिला रायसेन मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, रायसेन मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, रायसेन मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रायसेन विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	6	सारणी 6-सा-14	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कृषि	6	सारणी 6-सा-14	07	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-50-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1617-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 28 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित टीकमगढ़ विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार टीकमगढ़ नवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, टीकमगढ़ मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	टीकमगढ़ विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	4	सारणी 4-सा-9	4	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कृषि	4	सारणी 4-सा-9	08	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-69-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1813-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 31 मार्च 2018 द्वारा प्रकाशित शहडोल विकास योजना 2031 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार शहडोल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, शहडोल जिला शहडोल मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगरपालिक निगम, शहडोल मध्यप्रदेश
4. उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, शहडोल मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	शहडोल विकास योजना 2031.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	4	सारणी 4-सा-12	4	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कृषि	4	सारणी 4-सा-12	07	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-72-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2323-वि.यो. 496-2018, भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2018 द्वारा प्रकाशित छतरपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार छतरपुर नवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, सागर संभाग सागर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, छतरपुर जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, छतरपुर, मध्यप्रदेश
4. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय, छतरपुर, मध्यप्रदेश.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	छतरपुर विकास योजना 2021.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक.	6	सारणी 6-सा-11	4	सूचना प्रौद्योगिकी* गैर प्रदूषणकारी उद्योग**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		कृषि	6	सारणी 6-सा-11	07	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग** कृषि पर्यटन सुविधा *** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.

ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.

iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीप:—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंचमार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा.

क्र. एफ-3-78-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1412-उपां-टीसी-रतलाम-307-2018, दिनांक 12 मार्च 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित रतलाम विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण के ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	डोशीगांव	50,	3.040	यातायात (पार्किंग एवं मार्ग)	औद्योगिक एवं मार्ग.
		51,	6.150		
		52	1.230		
		64,	0.620		
		65,	0.020		
		66/1,	4.800		
		66/2,	0.98		
2	रतलाम	3 एवं 5	3.00	यातायात (पार्किंग एवं मार्ग)	औद्योगिक एवं मार्ग.
			कुल रकबा 19.84		

(1) उपरोक्त उपांतरण रतलाम विकास योजना, 2021 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-114-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23 "क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2796-644-उपां-टीसी-सीहोर-2017, दिनांक 18 मई 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित सीहोर विकास योजना, 2031 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम शैरपुर	81/3/3,	2.428	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु)
2	ग्राम शैरपुर	288/170/1/1	1.198	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु)
		कुल रकबा	3.626 हेक्टेयर		

(1) विद्यमान शासकीय मार्ग के मध्य से 6.00 मीटर भूमि दोनों और मार्ग विस्तार छोड़ना आवश्यक होगा.

(2) उपरोक्त उपांतरण सीहोर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-116-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 3488-36-उपां-टीसी-कटनी-2018, दिनांक 20 जून 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित कटनी विकास योजना, 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	मौजा झिंझरी तहसील कटनी, जिला कटनी.	1221/1	14.90 हेक्टेयर में से 6.00 हेक्टेयर.	सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक पहाड़ी एवं मार्ग.	आवासीय, पहाड़ी एवं मार्ग (प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु).
		कुल रकबा	6.00 हेक्टेयर		

(2) उपरोक्त उपांतरण कटनी विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल

राजभवन भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2018

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-2-18-रा.स.-यू.ए.1-1491.—डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 05 की कण्डिका 2.2 के प्रावधान के तहत् डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिये इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-18-

रा. स.-यू. ए. 1-1338 दिनांक 9 अगस्त 2018 के द्वारा प्रो. अवधेश कुमार सिंह, कुलपति, आरो विश्वविद्यालय, सूरत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है. इसमें प्रो. वी. के. मल्होत्रा, सदस्य सचिव, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली एवं प्रो. संगीता शुक्ला, कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर सदस्य है.

(2) समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना था परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में पैनल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो सकेगा.

(3) अतः डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम 05 की कण्डिका 2.5 के तहत् प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा समिति को पैनल प्रस्तुत करने के लिये पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 02 सप्ताह की ओर वृद्धि की गई है.

कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू जिला इन्दौर के आदेशानुसार,
डी. डी अग्रवाल, राज्यपाल के सचिव.

कार्यालय, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-2-17-रा.स.-यू.ए. 1-1519.—मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2017 जारी कर मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्र. 20 सन् 1991) की धारा 33-ख के प्रावधान प्रभावशील किये गये थे एवं राज्य शासन के परामर्श पर आदेश क्र. एफ-1-2-17-रा. स.-यू. ए. 1-259, दिनांक 18 मार्च 2017 के द्वारा प्रो. रवीन्द्र आर. कान्हेरे को कुलपति नियुक्त किया गया था.

(2) राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय में धारा 33-ख के प्रावधानों को दिनांक 18 मार्च 2018 से आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लिया गया है. अधिनियम की धारा 33-ख की उपधारा (3) के द्वितीय परन्तुक के प्रावधान अनुसार धारा 33-ख के प्रावधानों की प्रभावशीलता की अवधि में नियुक्त कुलपति प्रो. रवीन्द्र आर. कान्हेरे अधिकतम 06 माह अर्थात् दिनांक 17 सितम्बर 2018 तक कुलपति पद पर कार्यरत रह सकेंगे.

(3) अतः मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 की धारा 9 की उपधारा (1) सहपठित परिनियम क्रमांक 1 की कंडिका (11) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल एतद्द्वारा श्री डी. डी. अग्रवाल, राज्यपाल के सचिव को उनके वर्तमान कार्यभार के साथ आगामी आदेश तक अथवा विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 1 की कंडिका (1) के अन्तर्गत कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिये उक्त विश्वविद्यालय के कुलपति के पद का कार्य संपादित करने के लिये नाम-निर्देशित करती हूँ.

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-1-2018-रा. सा.-यू. ए.1-1521.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल एतद्द्वारा प्रो. आर. जे. राव, रेक्टर, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (मध्यप्रदेश) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त करती हूँ.

(2) इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 1 के अनुसार शासित होंगी.

आनंदीबेन पटेल, कुलाधिपति.

आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्र. 6458-नोअविप-विपप्र-2018-2019.—आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी, भोपाल में 01 जुलाई 2015 से प्रभावशील विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था अनुसार मध्यप्रदेश वित्त सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षणोपरांत विभागीय परीक्षा का आयोजन दिनांक 23 जून 2018 को किया गया. इस आयोजित विभागीय परीक्षा में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है:—

क्रमांक	नाम	पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव	सहायक संचालक वित्त

संशोधित अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2018

क्र. 3111-913-अका-विपप्र-2016.—राज्य शासन द्वारा भू-अभिलेख एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 19 जनवरी 2016 को प्रश्न पत्र-प्रथम ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया'' भाग-बी, सी एवं प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया द्वितीय विषय में सम्पन्न हुई. जिसका परिणाम मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 दिनांक 3 जून 2016 में प्रकाशित किया गया. इसमें श्री कृष्ण कुमार पटेल का पदनाम राजस्व निरीक्षक के स्थान पर लिपिकीय त्रुटिवश सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख अंकित हो गया है अतः त्रुटि सुधार के पश्चात् प्रश्न पत्र-प्रथम ''प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया'' भाग-बी, सी एवं ''प्रशासनिक राजस्व विधि एवं प्रक्रिया'' द्वितीय विषय में रीवा संभाग के क्रमांक 62 पर अंकित परीक्षार्थी का पदनाम सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख के स्थान पर राजस्व निरीक्षक पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत जाधव, प्रभारी अधिकारी विभागीय परीक्षा.

न्यायालय, उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी भूमिगत पाइप लाइन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012

शहडोल, दिनांक 12 जुलाई 2018

प्ररूप-घ

क्र. 14-बी-121-2015-16-शहडोल.—मध्यप्रदेश भूमिगत पॉइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **छाता,** पटवारी हल्का **65–छाता,** तहसील **सोहागपुर,** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला,** तहसील **बुढ़ार,** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	सोहागपुर	छाता / 65–छाता	55	0.035
			57	0.027

क्र. 15-बी-121-2015-16.— अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **जरवाही,** पटवारी हल्का **14–जरवाही,** तहसील **बुढ़ार,** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला,** तहसील **बुढ़ार,** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	बुढ़ार	जरवाही / 14–जरवाही	376/1/क, 376/1/ख	0.247
			379	0.160
			40	0.023
			46	0.267
			633	0.099
			645/1/क, 645/1/ख, 645/1/ग, 645/2	0.258
			649/3	0.065
			649/2	0.071
			649/1	0.075
			650	0.117
			651/2	0.039
			658/1, 658/2, 658/3	0.118

कमांक 16/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **कटकोना,** पटवारी हल्का 17–**कटकोना,** तहसील **बुढ़ार,** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	कटकोना / 17–कटकोना	565	0.130
			742	0.191
			743	0.102
			744	0.031
			745	0.239
			735	0.127
			648	0.013
			647	0.064
			649	0.030
			641	0.041

कमांक 18/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **पिपरतरा,** पटवारी हल्का **65–छाता,** तहसील **सोहागपुर,** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	पिपरतरा / 65–छाता	19	0.098
			20/2	0.205
			49	0.072

कमांक 19/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **साबो,** पटवारी हल्का **13–साबो,** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	साबो / 13–साबो	208	0.028
			207	0.181
			206	0.070
			205	0.013
			204	0.014
			203	0.017
			202	0.025
			190	0.192
			175/1, 175/2	0.188
			191	0.101
			215	0.045
			174	0.129
			156	0.040
			155	0.111

कमांक 20/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **समदाटोला,** पटवारी हल्का **15–पकरिया,** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	समदाटोला / 15–पकरिया	7/2	0.394
			7/8	0.120
			38/495	0.138
			38/1, 38/2	0.162
			55	0.104
			34/7	0.160
			34/16	0.260
			34/20	0.200
			151	0.110

कमांक 21/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **सेमरा,** पटवारी हल्का **16–सेमरा,** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	सेमरा / 16–सेमरा	221/1, 221/2	0.201
			224/2	0.199
			217	0.036
			219/2, 219/3	0.273
			335	0.112
			343	0.125
			268	0.094
			270	0.201

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
			271	0.028
			1137/2	0.022
			113/1, 113/2	0.025
			112	0.126
			108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6	0.115
			131	0.111
			130	0.004
			132	0.053
			133	0.105
			134	0.100
			628	0.029
			630	0.180
			633/1, 633/2	0.185
			615	0.102
			612	0.051
			609/1, 609/2	0.041
			608/1, 608/2	0.004
			610	0.208
			607	0.021
			604/1, 604/2	0.040
			603	0.008
			601	0.004
			600/2, 600/3	0.034
			599	0.022
			676	0.124
			648	0.004
			661/1, 661/2	0.021
			675	0.033
			674	0.028
			673	0.071

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
			664	0.023
			818	0.055
			600/2, 600/3	0.131
			599	0.072
			555	0.051
			559	0.016
			553	0.027
			552	0.092
			551	0.165
			500	0.011
			563	0.004
			564	0.022
			499/1, 499/2, 499/3, 499/4, 499/5	0.176
			491	0.010
			493/1, 493/2	0.180
			486	0.055
			485	0.040
			457	0.175
			458	0.020
			461/1, 461/2	0.129
			460	0.007
			461/1, 461/2	0.179
			450/1, 450/2	0.158
			448	0.173
			423	0.218
			425	0.046
			426	0.221
			433	0.007
			427	0.013
			429/1, 429/2, 429/3	0.039

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
			749	0.244
			944	0.015
			943	0.039
			941	0.054
			940	0.082
			939	0.008
			947	0.161
			973	0.043
			969	0.072
			948	0.024
			968	0.098
			967	0.027
			983	0.057
			966	0.048
			984/2, 984/3, 984/4, 984/5	0.177
			1001	0.058

कमांक 22/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **सोनवर्षा,** पटवारी हल्का **65–छाता,** तहसील **सोहागपुर** जिला **शहडोल** से ग्राम **जल्लीटोला** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	सोहागपुर	सोनवर्षा / 65–छाता	190/1, 190/2, 190/3	0.130
			188/2	0.291
			187	0.165
			184/1, 184/2	0.114
			182	0.082
			181	0.007
			236/1, 236/2	0.184
			235/1, 235/2	0.421
			229/1/1, 229/1/2, 229/1/3, 229/2	0.041
			97/1, 97/2, 97/3	0.011
			94	0.045
			96	0.075

कमांक 23/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **बिरूहली,** पटवारी हल्का **04–बिरूहली,** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	बिरूहली / 04–बिरूहली	811	0.147
			794/1/क/1	0.053
			808/1	0.148
			631	0.022
			622	0.033
			625	0.210
			626	0.092

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
			633/2	0.098
			637/1/ख	0.120
			635/2/ख	0.040
			643	0.032
			644/1, 644/2	0.238
			645/3	0.017
			646/2	0.009
			817/3/क	0.024
			818/3	0.105
			822/2, 822/3	0.013
			819/1/ख, 819/1/घ	0.103
			820/2/ख	0.248
			642/2/ख, 642/2/ग	0.100
			177/1	0.122
			220	0.006
			218/1	0.012
			207	0.011
			455	0.068
			544/2, 544/5	0.283

कमांक 24/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **छांटा उर्फ नवाटोला,** पटवारी हल्का **03–छांटा उर्फ लवाटोला,** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुड़ार	छांटा उर्फ नवाटोला / 03	8/1	0.025
			90/727/8, 90/727/9, 90/727/10, 90/727/11, 90/727/12	0.545
			591	0.009
			589	0.076
			621/1, 621/2	0.123
			622/1, 622/2	0.116
			686	0.061
			630/1	0.089
			629/1, 629/2	0.074
			576/1, 576/2, 576/4	0.185
			306/6	0.350
			167	0.069
			166	0.120
			67	0.075

कमांक 25/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **चाका**, पटवारी हल्का **05–चाका** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुड़ार	चाका / 05–चाका	393	0.248
			800	0.094
			801/4	0.404
			314/1, 314/2, 314/3	0.369
			887/2	0.100
			870/2	0.510
			790	0.210
			395	0.073

क्रमांक 26/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **नौगई,** पटवारी हल्का **01–नौगई** तहसील **बुढ़ार** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुड़ार	नौगई / 01–नौगई	46/2/2, 46/4, 46/5	0.514
			381/1, 381/2	0.089
			380	0.024
			308/1, 308/3/ग	0.115
			307/1/ख, 307/2/क, 307/3/क, 307/3/ख, 307/3/ग	0.033
			309/2	0.253
			319/2	0.116
			318	0.015
			317	0.155
			338/1, 338/2, 338/3	0.124
			339	0.270
			346/2	0.114
			344	0.173
			451	0.018
			452	0.150
			453	0.004
			454/5	0.004
			206	0.136

कमांक 28/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **चंगेरां,** पटवारी हल्का 02–**चंगेरा,** तहसील **बुढ़ार,** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	बुढ़ार	चंगेरा / 02–चंगेरा	456	0.035
			409/4, 409/5/ख, 409/15	0.735
			457	0.210
			443/1, 443/2	0.031
			289/4	0.405
			268/3	0.031
			243/1/क, 243/1/ग, 243/2/क/1, 243/2/क/3	0.263
			230	0.139

कमांक 29/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **धनगवां,** पटवारी हल्का 57–**धनगवों** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	गोहपारू	धनगवां / 57–धनगवां	1946	0.004
			1921	0.118
			1922	0.145
			1917	0.142
			1912	0.142
			1906	0.113
			1911	0.060
			1910	0.068
			104	0.038
			103/2	0.079

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
			102	0.056
			177/2	0.035
			180/1; 180/3	0.168
			228	0.069
			229	0.029
			226/1, 226/2	0.081
			230	0.040
			232	0.051
			1485	0.077
			1470/3	0.438
			1468	0.019
			1459/2	0.406
			1460	0.037
			1466	0.036
			1464	0.074
			1463	0.020
			1462	0.020
			1461/1869	0.239
			1428	0.058
			1429	0.225
			1433/1, 1433/2	0.032
			1432/1, 1432/2, 1432/3	0.076
			1099	0.036
			1146	0.016
			1147	0.047
			1145	0.066
			1142	0.064
			1138	0.045
			1137/1, 1137/2	0.097
			1136/2, 1136/3	0.162
			1132/2, 1132/4	0.040
			1133/1, 1133/2	0.132
			1080/2, 1080/3	0.183
			1518	0.097

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
			1519	0.004
			1521	0.042
			1520	0.087
			1529/1, 1529/2	0.181
			919	0.032
			900	0.163
			901	0.015
			845	0.066
			846	0.088
			855	0.067
			857/1, 857/2	0.093
			853	0.060
			859/1, 859/2	0.006
			860/1, 860/2	0.230
			1562/1	0.085
			1564	0.097
			1779	0.034
			1563/1	0.006
			1780	0.058
			1782/1	0.092
			1783	0.085
			1840	0.004
			1839	0.005
			1845	0.004
			1838	0.101
			533/1	0.066
			2001/2	0.334

कमांक 30/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **देवरी,** पटवारी हल्का 58–**देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	देवरी / 58–देवरी	323	0.129
			332	0.112
			333	0.097
			334	0.110
			337	0.124
			338	0.050
			339	0.053
			340	0.052
			341	0.045
			346	0.050
			350/1, 350/2	0.048
			351/1, 351/2	0.136

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	गोहपारू	देवरी / 58–देवरी	352/1/क, 352/1/ख	0.053
			353/1, 353/2	0.004
			372	0.100
			366	0.032
			361	0.045
			362	0.005
			363	0.153
			357	0.068

कमांक 31/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **घोरवे,** पटवारी हल्का **63–घोरवे** तहसील **जैतपुर** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	घोरवे /63–घोरवे	933/2	0.056
			935/2	0.325
			936/2	0.214
			937	0.211

कमांक 32/बी–121/2015–16, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 13.07.2016 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **भोगड़ाटोला** पटवारी हल्का **62–भमला** तहसील **जैतपुर** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22.07.2016 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमाक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हैक्टयर में)
1	2	3	4	5
शहडोल	जैतपुर	भोगड़ाटोला / 62–भमला	3	0.087
			4/1, 4/2	0.162
			5	0.011
			342	0.037
			343	0.066
			344	0.012
			345	0.119
			353	0.034

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 19 जुलाई 2018

अंतर्गत आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कंडिका-11(1)

पत्र क्र. भू-अर्जन-36(अ-82)2017-18-161.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – टिकरा खम्हरिया, प.ह.नं. 48, रा.नि.म. शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
टिकरा खम्हरिया	1	कुंवर पिता परसाद	16	0.79	0.02	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	संतराबाई पिता नरबद	13 15	1.39 0.60	0.07 0.07	
	3	इदलो पति नवलू सेमलाल, चूरामन, मिहीलाल, छोटू पिता लखनू, कमलसिंह, आशाराम, चैनसिंह पिता शिवराज, ननिया पति शिवराज, मैकू, सुमिया पिता वलमा	14	0.24	0.04	
योग :– 03 कृषक				3.02	0.20	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-37(अ-82)2017-18-159.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम -- समनपुरा रैयत, प.ह.नं. 47, रा.नि.म. शहपुरा, विकासखण्ड शहपुरा, जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:--

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
समनपुरा रैयत	1	सुदर्शन पिता लालू, रयत्ती	160	1.41	0.03	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
योग :- 01 कृषक				**1.41**	**0.03**	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-38(अ-82)2017-18-160.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड मे स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – जिमरा प.ह.नं. 31 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू-धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:-

ग्राम का नाम	सं. क्र.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
जिमरा	1	रघुनाथ धनुषधारी नारायण सुनील जवाहर पिता संतोषी गुड्डू रनिया पुत्री संतोषी सियाबाई पति संतोषी	124 127	0.62 0.50	0.01 0.01	
	2	धनुषधारी पिता संतोषी	128/1/1	0.33	0.01	
	3	गौरीशंकर पिता रूपलाल मुनीम आशीष रिखियाबाई अभिलाषा पिता जमुना प्रसाद	43 51	1.62 1.10	0.04 0.05	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	4	चमेलीबाई पति रूपलाल गौरीशंकर जमुना पिता रूपलाल	49	3.76	0.23	
	5	दम्मूलाल पिता रामनाथ	50	0.79	0.06	
	6	तीरथ पिता सम्मत	52/1	0.59	0.02	
	7	इन्द्रमणी पिता कमला	52/2	0.20	0.02	
	8	तीरथ दिलीप मुकेश भूरी ललिता शशि पिता सम्मत सुहागबाई पति सम्मत	53	0.79	0.03	
	9	सावित्री पति भूरेलाल	54	1.00	0.08	
	10	कृष्णकुमार पिता सुखदेव	55/1	0.86	0.03	
	11	राजेन्द्र प्रसाद पिता कृष्णकुमार	55/2 55/3	0.28 0.29	0.03	
	12	घनश्याम प्रसाद पिता कृष्णलाल	55/4 55/6	0.29 0.28	0.03	
	13	रामकिशोर पिता कृष्णलाल	55/5 55/7	0.29 0.29	0.03	
	14	नन्हा पिता बराती	120/2	0.31	0.01	
योग :– 14 कृषक				14.19	0.69	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बाबत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-39(अ-82)2017-18-162.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – राछो माल प.ह.नं. 31 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
राछो माल	1	सेमवति पति ललसैया	2/1	0.22	0.04	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	श्यामकुमार पिता सुखैया	8	0.27	0.03	
	4	भूरा पिता लामू नानबाई पति लामू	9/1	0.69	0.02	
	5	लक्ष्मण पिता लामू नानबाई पति लामू	9/2	0.69	0.02	
योग :– 04 कृषक				1.87	0.11	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-40(अ-82)2017-18-169.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – सूरजपुरा प.ह.नं. 42 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
सूरजपुरा	1	केमसिंह पिता बहादुर	134/2	1.00	0.02	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
योग :– 01 कृषक				1.44	0.02	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-41(अ-82)2017-18-157.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – मरवारी प.ह.नं. 26 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
मरवारी	1	बिन्नी बाई पिता घनश्याम	531/2 548/2	0.57 0.04	0.05 0.02	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	लीलाबाई पति घनश्याम पुईयाबाई पति हरवंश पुरषोत्तम गुरुप्रसाद गुडडीबाई बंदीबाई नानबाई संतोबाई सुनिता पिता हरवंश कंघी पंचम ललन पिता घनश्याम चन्दाबाई बीवीबाई सोनाबाई पिता घनश्याम	586 548/1 531/1	0.13 0.38 4.36	0.02 0.03 0.05	
	3	सुदीना पिता झेला	538/1	0.92	0.10	
	4	गरीबा प्रसाद पिता पीतमलाल	538/2	0.40	0.04	
	5	नन्हू पिता सेवाराम	529/1	0.64	0.01	
	6	बुद्धू पिता सेवाराम	529/2	0.64	0.01	
	7	केशवप्रसाद पिता शिवचरण	539 393	0.60 0.13	0.06 0.06	
	8	बसंतलाल पिता रामप्रमोद	540 596/2	0.57 0.19	0.10 0.01	
	9	सोनूलाल पिता उजियार	541/1/1	0.22	0.01	
	10	नन्दलाल सरमन कलाबाई नानबाई पिता कालूराम	541/2	0.65	0.01	
	11	बद्रीविशाल पिता उजियार	541/3	0.21	0.01	
	12	जवाहर पिता उजियार	541/4	0.21	0.01	
	13	पंचम ललन पिता घनश्याम	547	0.55	0.05	
	14	उमाशंकर पिता रामप्रमोद	550/1	0.33	0.01	
	15	जगदीश पिता रामप्रमोद	550/2	0.34	0.02	
	16	जगतलाल पिता छुन्नूलाल	551/1	0.40	0.01	
	17	मुन्नूलाल पिता छुन्नूलाल	551/2	0.41	0.02	
	18	लीलाबाई पिता घनश्याम	552 620	0.30 0.30	0.03 0.03	
	19	बुद्धू पिता सेवाराम	553	0.25	0.05	

20	सिलोचना बाई पति अशोक कुमार यादव	554	0.27	0.03
21	नारायण मुकेश राजकुमार पिता मदनलाल रनिया पिता बाबूलाल	556	1.99	0.13
22	प्रदीप अतुल पिता गणेश	627/1	0.44	0.06
23	पप्पू कुमार सिंह आराम ईकवाल सिंह	627/2	0.45	0.06
24	कपूरा पिता बाबूलाल	622	0.55	0.11
25	डुमारीलाल पिता छोटेलाल	623/1	0.24	0.05
26	लखनलाल उर्फ लेखीराम पिता पाण्डू	549 607	0.30 0.66	0.03 0.11
27	शिवकुमार पिता छोटेलाल	623/2 623/5	0.33 0.06	0.02 0.02
28	भंगीलाल पिता छोटेलाल	623/3	0.32	0.02
29	दादूराम पिता पाण्डू	606	0.66	0.08
30	शंकर पिता पाण्डू	605	0.88	0.08
31	कुन्तीबाई पिता गोकल	604	0.31	0.06
32	रामकुमार पिता सुन्दरलाल	603/1	0.15	0.03
33	रामचरण पिता सुन्दर	603/2	0.16	0.03
34	महेश प्रसाद मदनलाल पिता भजनलाल	601 608	2.10 0.30	0.16 0.01
35	तुलसीबाई पति शिवराम सुदर्शन मुकेश अर्मतलाल पिता शिवराम सुक्को पिता शिवराम	621 600	0.61 0.70	0.05 0.01
36	राजेश पिता गयादीन	595/1/1	0.23	0.03
37	तम्मालाल पिता मोहनलाल	595/2	0.29	0.03
38	बसन्ता राजू पिता कपूरालाल	595/3	0.15	0.03
39	राजेन्द्र उर्फ राजू पिता कपूरालाल	595/4	0.14	0.03
40	राजकुमार पिता बाबूलाल	595/6	0.03	0.01
41	रामविशाल पिता गयादीन	591/1	0.30	0.05
42	लक्ष्मीबाई पति बद्रीप्रसाद	591/2	0.58	0.06
43	शंकरलाल पिता फागूराम	588	0.44	0.05
44	मोहवति पति गुलाब	584	0.41	0.07
45	रामविशाल राजेन्द्र पिता शिवचरण	583	0.17	0.03
46	नारायण पिता सुखराम	392/1 392/2	0.05 0.04	0.01 0.01
47	विश्नूप्रसाद पिता सुखराम	392/3	0.04	0.01
48	सोनकीबाई पति पूरनलाल गनेश गोवर्धन गौराबाई पिता पूरनलाल	390	0.09	0.03
49	मिठ्ठू पिता चेतराम	389	0.03	0.01
50	डुमारीलाल पिता नान्हू	388	0.02	0.01
51	डुमारीलाल पिता नान्हू नान्हू पिता जवाहर	387/1	0.05	0.01
52	ननकिया पति वृन्दा विश्राम पिता लल्ला	383 381/1	0.06 0.16	0.01 0.01
53	सम्पत पिता समरू बगै. विश्नूप्रसाद	382	0.08	0.01
54	रामकुमार पिता धनीराम	378/2 786/3	0.03 0.19	0.01 0.01
55	कल्लूबाई पति शम्भूलाल श्यामशरण अनेकलाल पिता शम्भूलाल अनेकलाल	378/1 786/1/1	0.03 0.19	0.01 0.01
56	बुद्धसेन पिता परसदवा	377/2	0.01	0.01
57	दशरथ पिता कालूराम	363/1	0.03	0.02
58	शिवप्रसाद पिता कालूराम	363/2	0.02	0.01

	59	उन्नतराम फकीरेलाल दुलीचंद पिता माधोप्रसाद	364 365	0.04 0.04	0.01 0.02	
	60	सविताबाई पिता मुन्ना	357/1	0.07	0.01	
	61	अजय पिता मुन्ना	357/2	0.08	0.02	
	62	गरीबदास बुधनिया सुम्मोबाई पिता दद्दी	366	0.11	0.02	
	63	भगवतप्रसाद पिता भजनलाल	358	0.38	0.03	
	64	मुन्नीबाई पति श्रीशिवप्रसाद	624/1	0.47	0.07	
	65	पंचमलाल पिता लालमन	624/2	0.46	0.05	
	66	सरमन पिता धनीराम	786/4	0.18	0.02	
	67	सुखदेव शिवरतन पिता भद्देलाल बिसरती पिता भद्देलाल	786/2	0.07	0.02	
	68	रमेश महेश सुरेश गनेश काशीराम गनपत रामबाई राजकुमारी पिता कृष्णलाल	794	0.43	0.09	
	69	रामकली पति पन्नालाल फत्तूलाल शंकरलाल अविनाश आशीषकुमार गीताबाई सरोजबाई पिता पन्नालाल	795	0.84	0.02	
	70	सोहनलाल पिता चैतू	796	0.84	0.05	
योग :– 70 कृषक				33.09	2.99	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-43(अ-82)2017-18-158.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – बरगॉव प.ह.नं. 40 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बरगॉव	1	भूपत पिता रामकिशोर	1671/2 1581/2	0.17 0.30	0.08 0.03	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	दादूराम रोहणीप्रसाद पिता छोटेलाल	1597/1	1.11	0.04	
	3	शीलाबाई पति सुन्दरलाल, सोहन, दिनेश, गंगोत्रीबाई, मायाबाई, रामकुमारी पिता सुन्दरलाल	1627	0.48	0.04	
	4	हीरालाल पिता शंकरलाल	1578	0.84	0.08	
	5	महासिंह पिता रामचरण	1758	0.71	0.20	
	6	हीरालाल पिता मोहनलाल, शंकुतंला पति कमल, पवन, दीपक, ज्योति पिता कमल, टीकाराम पिता मोहन, रमोतिया पति मोहन	1683 216 198/1	5.15 1.32 0.48	0.08 0.11 0.07	
	7	जुगलकिशोर पिता बल्देव	506	0.59	0.03	
	8	प्रेमलाल खेलन पिता नन्तू	547/2	0.02	0.01	
	9	कौशलप्रसाद, सूरजप्रसाद पिता ददुवा, गन्नीबाई पति रामप्रसाद, शुभम, श्रद्वा, श्यामबाई, मुन्नीबाई पिता ददुवा	902	3.25	0.13	
	10	मायाराम पिता बुद्धू	765	0.54	0.06	
	11	ज्ञानी, हरिया पिता मोले, बौरीबाई पिता मोले	549	0.05	0.01	
	12	ताराबाई पति गुरूप्रसाद	296	0.40	0.15	
	13	भुवनेश्वर पिता राजेन्द्र	121	1.32	0.04	
	14	सुरेश पिता गणेश	217/6 159/5	0.12 0.07	0.01 0.02	
	15	केशवप्रसाद पिता लक्ष्मणप्रसाद	217/4 159/2	0.25 0.30	0.04 0.02	
	16	लखन पिता गणेश	159/4	0.08	0.02	
	17	संजयकुमार पिता भगवानदास	204	0.80	0.08	
	18	बसोरी पिता मातादीन	214/2/क	0.52	0.15	
	19	प्रेमनारायण पिता क्रोधनलाल	214/4	0.06	0.06	
	20	विजयकुमार सिंह, राधाबाई, लीलाबाई, भूपतकुमार सिंह पिता घनश्याम	215	0.65	0.13	
	21	शंकर, सोनू, मुरली पिता शोभाराम	915	0.97	0.06	

	22	लेखराम पिता आत्माराम	1824/1	0.25	0.05	
	23	राजेश कुमार पिता आत्माराम	1824/2 1825	0.25 0.62	0.02 0.07	
	24	मरतू पिता टीडू	1809/1	0.86	0.04	
	25	समारू पिता टीडू	1809/2	0.86	0.87	
योग :– 25 कृषक				**23.39**	**1.97**	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-42(अ-82)2017-18-166.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – भीमपार प.ह.नं. 25 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि क्रय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	क्रय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
भीमपार	1	लक्ष्मीबाई पति बेबू	845/1 845/2 845/3	0.41 0.41 0.41	0.06 0.06 0.06	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	छिंगनसिंह पिता गोकलसिंह, चन्द्रभान पिता शिप्रसाद	842	1.83	0.02	
	3	पुन्नूसिंह, मंगलसिंह, लामूसिंह पिता चंदनसिंह, गनपत, सम्पत पिता फूलसिंह, हरीदीन, रामदीन, विशाल, दुपतसिंह पिता सम्हरसिंह	841	2.02	009	
	4	प्रेमसिंह पिता देवसिंह	840	1.15	0.10	
	5	मुनीमसिंह पिता झुन्नेलाल, कोता वेवा झुन्नेलाल	839 928	0.55 0.93	0.02 0.02	
	6	मानसिंह पिता चमरूसिंह	1021/1	0.29	0.16	
	7	लालसिंह पिता चमरू	1021/2	0.30	0.16	
	8	फागूसिंह पिता चमरू	1021/3	0.30	0.16	
	9	रामसिंह पिता नानदाउ	847	1.50	0.11	
	10	बैसखिया बाई पति पड्सू, सम्भू पिता पड्सू	848	1.50	0.23	
	11	अजीत पिता चैनसिंह	1022/1	0.44	0.16	
	12	गनेशा पिता नानसिंह	1020	0.44	0.04	
	13	जयसिंह पिता हन्शू	1000	1.59	0.08	
	14	भद्देलाल पिता हन्शू	898	1.58	0.41	
	15	केहरसिंह, रघुवीर पिता रूपसिंह, भागवती पति यतनसिंह, रवीन्द्र, अरविन्द्र पिता यतनसिंह, भगवनिया पिता रूपसिंह	899	1.79	0.35	
	16	गया पिता लम्मा, भगवन्ता पिता लम्मा	998	2.87	0.17	
	17	संध्या पति महेश बरकडे	959 670 672/2	1.97 2.00 0.97	0.28 0.10 0.14	
	18	उग्रसेन पिता नरसिंह	902/1	1.40	0.07	

	19	भागवत पिता सुखदेव	902/2	1.15	0.07	
	20	शंकर पिता नरसिंह	902/3	1.65	0.07	
	21	बसौरी करनसिंह, करनसिंह पिता रूपसिंह	914	2.13	0.28	
	22	हरि सिंह पिता मूलचंद	957/1	0.46	0.10	
	23	कपूरसिंह पिता मूलचंद	957/2	0.47	0.03	
	24	नानसिंह पिता रामलाल	958	1.28	0.10	
	25	गोपाल पिता काशीराम	931	0.80	0.11	
	26	मानिकलाल, अनूपसिंह, कम्मूसिंह, जनियाबाई ,तिजोबाई पिता मंगलसिंह	933	1.54	0.20	
	27	नीरज विजेन्द्र पिता उत्तमलाल	934/1	0.37	0.02	
	28	डुमारी, शिवकुमार, भंगी, सम्पत, गोराबाई पिता छोटेलाल	929 927	0.90 1.53	0.05 0.02	
	29	दादूराम पिता मल्ती	935	1.34	0.06	
	30	उत्तम, सत्तम पिता पुसौवा, इन्दोबाई पिता पुसौवा	915/1	0.26	0.07	
	31	कलाबाई पति कंधीलाल	915/2	1.00	0.18	
	32	सुदामा, नन्हेलाल पिता रामप्रसाद, अनूपा पिता रामप्रसाद, चमेलिया पति रामप्रसाद	917 673	1.15 0.27	0.16 0.03	
	33	कुन्था पति मनसैया, गनेशिया, छिगनी, ललिता पिता मनसैया	672/1	0.97	0.04	
	34	पवन कुमार पिता रामफल, आ.पा. रामफल पिता मोहवत	671/1	0.74	0.10	
	35	चरनसिंह पिता सुकाली, मुलिया पति सुकाली	669	1.67	0.07	
	36	डुमारी पिता पदमसिंह	919/1/1	0.80	0.08	
	37	फूलबाई पति भागचंद	919/1/2	0.93	0.08	
	38	अतरसिंह पिता लल्लासिंह	919/2	1.20	0.15	
योग :– 38 कृषक				**49.26**	**5.12**	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-44(अ-82)2017-18-156.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – भीमडोंगरी प.ह.नं. 24 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
भीमडोंगरी	1	लखन पिता मूलसिंह	559	1.16	0.12	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	छोटीबाई पति भोला	558	3.40	0.08	
	3	जयसिंह पिता कमलसिंह	549 557	1.61 1.15	0.05 0.10	
	4	चूरामन, तितरा	530 535	1.39 2.67	0.10 0.04	
	5	क्षानवति पिता रतिया	532	0.73	0.10	
	6	नन्हू, मत्थू पिता मन्धारी	533	0.73	0.01	
	7	भददेसिंह, तीजो, छीता पिता चन्द्रावली	524	1.57	0.06	
	8	मूलसिंह, मानू	512	1.20	0.05	
	9	दलपत पिता जोरावल, नन्हेलाल, लिखारी	534	0.63	0.04	
	10	सम्हरसिंह, अमरसिंह, पिता दसरू, बैसखिया पिता दसरू	511	1.87	0.13	
योग :– 10 कृषक				**18.11**	**0.88**	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-45(अ-82)2017-18-168.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – करौंदी प.ह. नं. 41 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
करौंदी	1	काशीबाई पति लक्ष्मन, ईश्वरप्रसाद, शिवप्रसाद, कमलेश, राजकुमार पिता लक्ष्मन	11/1	0.47	0.03	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	लक्ष्मीप्रसाद पिता गयाप्रसाद	10/1	0.20	0.02	
	3	शिवकुमार पिता अयोध्या प्रसाद	4/3	0.72	0.03	
	4	चैतन्य पिता अयोध्या प्रसाद	4/2	0.95	0.03	
	5	प्रेमिला पति रूपेश दीपेन्द्र पिता रूपेश	4/4	0.87	0.03	
	6	विश्नूप्रसाद पिता बाबूलाल	5/1	0.88	0.04	
	7	अशोक, राजेन्द्र, राजेश पिता द्रुपतलाल	5/2 7	0.41 0.40	0.06 0.08	
	8	कंधीलाल पिता प्रेमलाल	8/1	0.27	0.02	
	9	प्रकाशकुमार, सरस्वती, गंगा, जमुना पिता श्यामलाल	8/2	0.27	0.02	
	10	फुन्दीलाल पिता समनू	24	0.12	0.02	
	11	रामकली बाई पति मूलचंद साहू	25/2 29	0.20 0.42	0.03 0.03	
	12	हरप्रसाद पिता गोरेलाल	31	0.58	0.10	
	13	विवेककुमार पिता घनश्याम	30	0.33	0.05	
	14	हर्षमणि पिता नाथूराम	48	0.36	0.02	
	15	तीर्थमणि पिता नाथूराम	49	0.37	0.02	
	16	मोहन, ईश्वरी, नोखे पिता तोलमन	51 147	1.21 2.39	0.12 0.12	
	17	भीमशंकर, मुरली, मनोहर पिता भूरेमल	52	0.35	0.02	
	18	रामकुमार पिता रामगरीब	53	0.26	0.03	
	19	भालचंद साहू पिता फूलचन्द साहू	55/1	0.43	0.06	
	20	संतोष कुमार साहू पिता फूलचन्द साहू	55/2	0.42	0.06	
	21	रूद्रशरण पिता कमलाप्रसाद	86	0.22	0.02	
	22	भीमशंकर पिता भूरेमल	87/1	0.27	0.01	
	23	मुरलीमनोहर पिता भूरेमल	87/2	0.27	0.01	
	24	जमुनाप्रसाद पिता गयाप्रसाद	96	0.93	0.06	
	25	गुरूप्रसाद, अनीश पिता तीरथ प्रसाद	94	0.35	0.06	

	26	रामप्रसाद, सोनलाल, सुमंत्राबाई पिता शीतलप्रसाद, मुन्नीबाई पति भोलाप्रसाद, चंद्रभान, लक्ष्मीबाई, उर्मिलाबाई पिता भोलाप्रसाद	93	0.38	0.04	
	27	धनेश प्रसाद पिता तुलाराम	100	2.83	0.08	
	28	राजेन्द्र, राकेश, रमेश पिता रूद्रशरण	171	0.76	0.09	
	29	मीराबाई पति रामकिशोर	172	0.27	0.02	
	30	कृष्णकुमार पिता अयोध्याप्रसाद	166/1	0.99	0.05	
	31	राजेश पिता अयोध्या प्रसाद	166/2	1.00	0.05	
	32	मुलियाबाई पति भानीराम, रामकिशोर पिता भानीराम	165	0.08	0.04	
	33	जगदीश, लक्ष्मीनारायण पिता नीलकण्ठ, कुशमाबाई, राधाबाई, पिता नीलकण्ठ, मीराबाई पति लखन, यशवंत पिता लखन, द्रोपतीबाई पति तुलसीराम, संतोषीबाई पुत्री तुलसीराम	163	1.27	0.16	
	34	गनेशप्रसाद, महेशप्रसाद, खूबलाल पिता झुगरू	162	0.24	0.04	
	35	भागबती पिता लल्लूराम	167/1	0.10	0.02	
	36	पुरूशोसत्तम पिता मूलचंद	167/2	0.80	0.18	
	37	माहू पिता निरपत	152	2.03	0.18	
	38	द्रोपती बाई पति अमतलाल, मुकेशकुमार, रविकुमार, प्रहलाद पिता अमतलाल	151	0.47	0.08	
	39	बसंत कुमार पिता मनोहर साहू	143/1	0.87	0.02	
	40	हेमंतकुमार पिता मनोहर	143/2	0.88	0.02	
	41	दुर्गेश कुमार पिता पीताम्बर	142	1.90	0.08	
	42	दिलीपकुमार उमाशंकर पिता लक्ष्मणप्रसाद	111	1.11	0.14	
योग :– 42 कृषक				**30.90**	**2.49**	

उपरोक्तानुसार क्रय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/ आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-46(अ-82)2017-18-167.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – बरौदा प.ह.नं. 27 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
बरौदा	1	भगवतलाल पिता लालू, कुवरमन, जगदेव पिता दारकप्रसाद, तुलसाबाई पति श्री दोहर, सहदेव, सविताबाई पिता दोहर, बैसाखू पिता दारकाप्रसाद	227	0.36	0.03	बिलगॉव जलाशय नहर कार्य हेतु
	2	धानू – चमरा	228	3.43	0.09	
योग :– 02 कृषक				3.79	0.12	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

पत्र क्र. भू-अर्जन-47(अ-82)2017-18-170.—

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र दिनॉक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी आपसी सहमति से भूमि कय नीति अनुसार शहपुरा विकासखण्ड में स्थित बिलगॉव मध्यम परियोजना के नहर क्षेत्र से प्रभावित ग्राम – संग्रामपुर रैयत प.ह.नं. 31 रा.नि.म. शहपुरा विकासखण्ड शहपुरा जिला डिण्डौरी के कृषकों की निजी भूमि अनुसूचि अनुसार भू–धारको की सहमति से भूमि कय करने का विचार किया जा रहा है:–

ग्राम का नाम	सं. क.	खातेदार का नाम	सर्वे नं.	कुल रकवा	कय हेतु प्रस्तावित रकवा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6	7
	1	नरवदिया पिता मातादीन	198	1.32	0.06	
	2	समनू पिता हीरालाल	200	1.04	0.16	
	3	फागूसिंह पिता हीरालाल, रानाबाई पति हीरालाल	199	0.63	0.10	
	4	महेश, लालसिंह, बलसिंह पिता रामकुमार	215/1 196/1	0.82 0.48	0.06 0.01	
	5	श्यामकुमार पिता सुखैया	215/2 196/2	0.88 0.49	0.06 0.01	
	6	श्यामसिंह पिता सुखैया	215/3 196/3	0.66 0.79	0.06 0.01	
	7	तीरथसिंह पिता मुनीमसिंह	209	1.10	0.08	
	8	माहू पिता ढोली	210	0.31	0.04	
	9	सुहानाबाई पति चम्मर, प्रेमबाई, मुन्नी पिता चम्मर, संतोष, राजकुमार पिता बुद्धसेन, दद्दू व. जमना, सेमवती, लमिया पिता जमना, मंगलसिंह, मंगली, बिसरती पिता गंगाराम, फागूसिंह, कमलसिंह पिता गोरेलाल	211/1	0.99	0.05	
	10	हीरालाल भरिया पिता जेठू, रामबाई पति जेठू	177	1.10	0.13	
	11	बिश्नू पिता अयतू	176	1.10	0.08	
योग :– 11 कृषक				**11.71**	**0.91**	

उपरोक्तानुसार कय की जा रही भूमियों के भूमि स्वामियों को हित व उस पर स्थित मकान/कूप/वृक्ष आदि बावत् दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो, तो वह मय अभिलेख के सूचना प्रकाशन के (पन्द्रह) दिवस के अंदर तक इस कार्यालय में अपना दावा प्रस्तुत करें । नियम समयावधि के बाद प्राप्त दावे/आपत्तियों मान्य नही की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहित बुंदस, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 84-2018-एलए-रा.प्र.क्र. 10-अ-82-2017-18-जामली राजगढ़.—

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिये समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्र. 12.02.2014/सात/ए, दिनांक 12(11)2014 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू धारकों की "आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति" जारी की गई है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग खण्डवा को अर्दला तालाब योजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम जामली राजगढ़ की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र-ख में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका-11(1) के अन्तर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत निजी भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को निजी भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय किये जाने वाली निजी भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील पंधाना, पटवारी हल्का नं. 34, ग्राम जामली राजगढ़, राजस्व निरीक्षक मण्डल पंधाना

स. क्रं.	भूमि स्वामी का नाम, पिता का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा (हे. में)	प्रभावित रकबा (हे. में)	सिंचित रकबा (हे. में)	असिंचित रकबा (हे. में)	अन्य सम्पत्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राहूल पिता प्रेमलाल, रितेश पिता प्रेमलाल निवासी इन्दौर	252/1	3.21	1.20	1.20	निरंक	निरंक

विशेष गढ़पाले, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 7 सितम्बर 2018

क्र. 19अ-82-2017-18-मौजा खम्बारा-10962

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की, कालम नम्बर (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची –2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:–

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा (हे. में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	खम्बारा	13.870	खम्बारा लघु जलाशय

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा (हे0 में)	अर्जन की भूमि का रकबा (हे0 में)	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	278/1	3.640	1.740	भागरती रम्फूला पिता चैतू बुल्लो बेवा चैतू चैती पिता अमरसिंग गोंड सा.देह भूमि स्वामी
2	278/2	3.641	1.990	पंचतराव वल्द झुम्मक झनुरा पिता झुम्मक हिरोती बेवा झुम्मक गोंड सा. देह भूमि स्वामी
3	277	4.994	2.100	अमरलाल, अमृतलाल वल्द रावजी झमोता पिता रावजी गंगासिंग गंगाराम वल्द बापूलाल अनीता मन्तो पिता बापूलाल सा.देह भूमि स्वामी
4	276	1.538	0.730	भूता वल्द श्यामजी सा.देह भूमि स्वामी
5	274	1.283	0.320	श्यामजी वल्द मानू रसिया, रमिया पिता मानू गोंड सा. देह भूमि स्वामी
6	273	3.326	0.450	कौशल जौ. हरि प्रमिला जौ. भूरा पंवार सा.देह भूमिस्वामी

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	अर्जन की भूमि का रकबा हे0 में	धारक का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	214/1	9.009	0.070	इनलेक्ट इन्फ्रास्टेकचर्स आफिस फलेट न.201 सप्तश्रर्गी अपाटेमेंट छत्रपति नगर रिंग रोड नागपुर महाराष्ट्र भूमिस्वामी
8	206/2	1.214	0.130	संतोष अंकुश वल्द लखन पंवार सा.देह भूमिस्वामी
9	204	5.500	0.200	तुलसीराम, राजेराम, परसराम पिता घासीराम, कौशल निर्मला, सुमित्रा प्रमिला पिता घासीराम भोयर सा.देह भूमि स्वामी
	205	0.162	0.162	
	2	**5.662**	**0.362**	**योग**
10	282/5	0.179	0.179	मधु वल्द बाबु मेंहरा सा.देह भूमि स्वामी
	280/5	0.487	0.090	
	2	**0.666**	**0.269**	**योग**
11	282/4	0.179	0.179	कृष्णा वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
	280/4	0.487	0.120	
	2	**0.666**	**0.299**	**योग**
12	282/3	0.178	0.178	शिवनाथ वल्द बाबू मेहरा सा.देह भूमिस्वामी
	280/3	0.489	0.125	
	2	**0.665**	**0.303**	**योग**
13	282/1	0.178	0.178	श्री वल्द बाबू मेहरा सा.देह भूमि स्वामी
	280/1	0.487	0.125	
	2	**0.665**	**0.303**	**योग**
14	280/2	1.949	1.480	कचराबाई पिता बाबू बेला बेवा बातू मूसिया पति तुकाराम श्शांती बेवा भादू सुशिला पति बिरजलाल सुनिता पति श्री मेहरा सा. देह भूमि स्वामी
	282/2	0.714	0.714	
	2	**2.663**	**2.194**	**योग**
15	284	5.204	2.560	रमोती बेवा हिराजी भागरती पिता हिराजी झनको बेवा राखी रमनी, राजाराम वल्द राखी रन्तू रत्ना पिता राखी गोंड सा. देह भूमि स्वामी
16	203/2	1.800	0.050	भाऊराव वल्द दसरू गोंड सा.देह भूमि स्वामी
महा योग		**46.638**	**13.870**	

(2)– चूंकि खम्बारा लघु जलाशय योजना के बांध, हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है।

(3)– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

(4)– समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 20 अगस्त 2018

क्र. 4834-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः "भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—बालाघाट
(ख) तहसील—बालाघाट
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-भण्डारखोह तथा ग्राम कंटगी, प. ह. नं.-17, रा.नि.म.-बालाघाट.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र—0.271, हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नंबर	प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118/1/ख/1 एवं 118/5/1	0.069
136	0.202
योग . .	0.271

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—भण्डारखोह लघु जलाशय योजना अंतर्गत भूमि अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dm balaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in पर देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील बालाघाट जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग बालाघाट के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 30 अगस्त 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2017-18-4495.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है. अतः "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—हरदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.143 हेक्टयर भूमि.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
241/1/ख	0.321
926/1	0.712
269/2	0.263
270/2	0.028
271/2	0.037
269/3	0.263
270/3	0.029
271/1	0.038
269/1	0.263

(1)	(2)
270/1	0.028
271/1	0.038
288/3	0.041
288/4	0.041
288/5	0.041
योग . .	2.143

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हरदी जलाशय योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, शहडोल मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुभा श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्र. 441-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—मनकहरी
(घ) क्षेत्रफल—1.114 हेक्टयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
54/998/1/4ख/2	0.004
54/998/1/5	0.004
54/998/1/6	0.004
54/998/1/7	0.004
54/998/1/8	0.004
54/998/1/9	0.004
54/998/1/10	0.004
54/998/1/3	0.004
54/998/1/4क	0.004
54/998/1/4ख/1	0.004
55/1	0.018
56/1	0.032
58/2	0.028
58/3	0.014
58/4	0.015
102/1	0.015
103/1	0.112
105/3	0.12
105/4	0.02
113/2	0.02
114	0.026
240/1	0.002
240/2	0.012
240/3	0.012
240/4	0.02
240/5	0.012
241/1/1	0.006
249	0.032
250/1/ख	0.029
250/2/ख	0.03
251/2/ख/1	0.08
284/1	0.085
285	0.026
286	0.03
290/2क/1क	0.002
290/2क/1ख	0.002
290/2क/1ग/1	0.002
290/2क/1ग/2	0.002
290/2क/1ग/3	0.002
290/2क/1ग/4	0.002

(1)	(2)
290/2क/1घ	0.002
290/2क/2क	0.008
290/2क/2ख	0.008
290/2ख/1	0.004
290/2ख/2क	0.004
290/2ख/2ख	0.004
290/2ख/2ख/3	0.003
290/2ख/4	0.003
292/3	0.016
292/5	0.008
292/6	0.008
292/8	0.012
292/9	0.004
305	0.016
306/1	0.014
306/2	0.02
306/3	0.02
307/1	0.012
307/2/1	0.016
307/2/02	0.012
307/2/3	0.012
308/1/ख	0.005
308/1/ग	0.005
308/1/घ	0.005
308/2	0.015
308/3	0.015
308/4	0.015
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	1.114

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 442-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है. उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—खारी
(घ) क्षेत्रफल—0.726 हेक्टयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.006
1/2	0.013
1/4	0.01
1/3	0.013
1/5	0.004
1/6	0.004
1/7	0.004
1/8	0.004
1/9	0.004
1/10	0.004
1/11	0.004
1/12	0.004
1/13	0.004
4/1	0.048
4/2	0.084
6/720/ख	0.061
7/2/ख/2	0.002
7/2/ख/3	0.002
7/2/ख/4	0.001
7/2/ख/5	0.001
7/2/ख/6	0.001
7/2/ख/7	0.001
7/2/ख/8	0.001
7/2/ख/9	0.001
7/2/ख/10	0.001
7/2/ख/11	0.001
7/2/ख/12	0.001
7/2/ख/13	0.001
7/2/ख/14	0.001

(1)	(2)	(1)	(2)
7/2/ख/15	0.001	55/1/ख/6	0.007
7/2/ख/16	0.001	55/1/ख/7	0.007
7/2/ख/17	0.001	55/1/ख/8	0.007
7/2/ख/18	0.001	55/1/ख/9	0.001
7/2/ख/19	0.001	55/1/ख/10	0.001
7/2/ख/20	0.001	55/1/ख/11	0.001
7/2/ख/21	0.001	55/1/ख/12	0.001
7/2/ख/22	0.001	55/1/ख/13	0.001
45/2	0.13	55/1/ख/14	0.001
50	0.108	55/1/ख/15	0.001
55/2/क	0.001	55/1/ख/16	0.001
55/2/ज	0.002	55/1/ख/17	0.001
55/2/ड	0.002	55/1/ख/18	0.001
55/2/ट	0.001	60/1/क	0.02
55/2/ठ	0.001	60/2/क	0.02
55/2/झ	0.001	60/1/ग	0.004
55/2/	0.001	60/1/घ	0.004
55/2/छ	0.002	60/1/ङ	0.004
55/2/च	0.002	60/5	0.004
55/2/ग/1	0.001	60/4	0.004
55/2/ग/2	0.001	60/3	0.004
55/2/घ/1	0.001	60/6	0.004
55/2/घ/2	0.001	60/7	0.004
55/2/ङ/1	0.001	60/8	0.004
55/2/ङ/2	0.001	60/2/ग	0.004
55/2/ख/7	0.002	60/2/घ	0.002
55/2/ख/8	0.002	60/2/ङ	0.002
55/2/ख/4	0.002	61/21	0.001
55/2/ख/9	0.002	61/22	0.001
55/2/ख/3	0.002	61/14	0.001
55/2/ख/2	0.002	61/24	0.001
55/2/ख/6	0.002	61/23	0.001
55/2/ख/5	0.002	61/12	0.001
55/1/ख/1	0.003	61/17	0.001
55/1/ख/2	0.002	61/18	0.002
55/1/ख/3	0.002	61/19	0.001
55/1/ख/4	0.002	61/13	0.001
55/1/ख/5	0.001	61/16	0.001

(1)	(2)
61/15	0.001
61/20	0.001
61/3	0.002
61/4	0.003
61/5	0.003
61/9	0.002
61/10	0.002
61/8	0.002
61/11	0.002
61/6	0.002
61/7	0.002
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 443-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—बम्हौरी
(घ) क्षेत्रफल—0.264 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
316/1	0.009
316/2	0.009
316/3	0.009
316/4	0.009
316/5	0.003
344/1/क	0.01
344/1/ख	0.008
344/2/क	0.008
344/2/ख	0.004
344/2/ग	0.004
344/2/घ	0.004
344/2/ङ	0.004
344/2/च	0.004
344/2/छ	0.004
344/2/ज	0.004
344/2/झ	0.004
344/2/ञ	0.004
344/2/ट	0.004
345	0.031
405/1	0.012
405/2	0.011
407/1	0.01
407/2	0.01
418/1	0.006
419/1/क	0.007
419/1/ख	0.007
419/1/ग	0.007
419/1/घ	0.007
611	0.051
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 444-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान

(ग) नगर/ग्राम—हिनौता
(घ) क्षेत्रफल—0.210 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
194/1क/1क/1क	0.150
194/1क/1ख	0.008
194/1क/1ग	0.008
194/1क/1घ	0.008
194/1क/1ङ	0.010
211/1क	0.002
211/1ख	0.008
211/1घ	0.004
211/1ङ	0.004
212/1क	0.008
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 445-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—सतरी
(घ) क्षेत्रफल—0.063 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
103/2	0.016
171/2	0.005
172/1	0.002
172/2	0.002
172/3	0.002
1007/1	0.036
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.063

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 446-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामपुर बाघेलान
(ग) नगर/ग्राम—बठिया
(घ) क्षेत्रफल—0.249 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
13	0.010
17/1	0.075
39	0.060
40/1	0.007
40/2	0.023
40/3	0.004
40/4	0.003
40/5	0.003
40/6	0.003
40/7	0.003
40/8	0.003
40/9	0.003
44/1	0.030

(1)	(2)
44/2	0.002
44/3	0.008
45/1	0.004
45/2	0.008
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	0.249

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 447-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—बिरहुली
(घ) क्षेत्रफल—2.374 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
145/2	0.101
145/3/1/1/1	0.004
145/3/1/1/2	0.006
145/3/1/1/3	0.006
145/3/1/1/4	0.006
145/3/1/1/5	0.006
145/3/1/1/6	0.006
145/3/1/1/7	0.006
145/3/1/1/8	0.006
145/3/1/1/9	0.003
145/3/1/1/10	0.006
145/3/1/1/11	0.006
145/3/1/1/12	0.006
145/3/1/1/13	0.006
145/3/1/1/14	0.006
145/3/1/2/1	0.02
145/3/1/2/2	0.005
7/2/ख/3	0.002
7/2/ख/4	0.001
7/2/ख/5	0.001
7/2/ख/6	0.001
7/2/ख/7	0.001
7/2/ख/8	0.001
7/2/ख/9	0.001
7/2/ख/10	0.001
7/2/ख/11	0.001
7/2/ख/12	0.001
7/2/ख/13	0.001
7/2/ख/14	0.001
7/2/ख/15	0.001
7/2/ख/16	0.001
7/2/ख/17	0.001
7/2/ख/18	0.001
7/2/ख/19	0.001
7/2/ख/20	0.001
7/2/ख/21	0.001
7/2/ख/22	0.001
45/2	0.13
50	0.108
55/2/क	0.001
55/2/ज	0.002
55/2/ड	0.002
55/2/ट	0.001
55/2/ठ	0.001
55/2/झ	0.001
55/2/	0.001
55/2/छ	0.002
55/2/च	0.002
55/2/ग/1	0.001
55/2/ग/2	0.001
55/2/घ/1	0.001

(1)	(2)
55/2/घ/2	0.001
55/2/ङ/1	0.001
55/2/ङ/2	0.001
55/2/ख/7	0.002
55/2/ख/8	0.002
55/2/ख/4	0.002
55/2/ख/9	0.002
55/2/ख/3	0.002
55/2/ख/2	0.002
55/2/ख/6	0.002
55/2/ख/5	0.002
55/1/ख/1	0.003
55/1/ख/2	0.002
55/1/ख/3	0.002
55/1/ख/4	0.002
55/1/ख/5	0.001
55/1/ख/6	0.007
55/1/ख/7	0.007
55/1/ख/8	0.007
55/1/ख/9	0.001
55/1/ख/10	0.001
55/1/ख/11	0.001
55/1/ख/12	0.001
55/1/ख/13	0.001
55/1/ख/14	0.001
55/1/ख/15	0.001
55/1/ख/16	0.001
55/1/ख/17	0.001
55/1/ख/18	0.001
60/1/क	0.02
60/2/क	0.02
60/1/ग	0.004
60/1/घ	0.004
60/1/ङ	0.004
254/1/3	0.008
254/1/4	0.012
254/2	0.005
256/1/1/1	0.03
256/1/1/2	0.005
256/1/1/3	0.005
256/1/2/1	0.034
256/1/2/2/1	0.003
256/1/2/2/2	0.003
256/1/2/3	0.004
256/1/2/4	0.004
257/1/1	0.001
257/1/2	0.004
257/1/3	0.004
257/1/4	0.002
257/1/5	0.002
257/1/6	0.004
257/1/7	0.004
257/1/8	0.004
257/1/9	0.004
257/1/10	0.004
257/1/11	0.004
257/1/12	0.004
257/1/13	0.004
258/1	0.008
258/2	0.002
258/3	0.002
258/4	0.004
259/1	0.004
259/2	0.002
259/3	0.004
259/4	0.004
259/5	0.003
259/6	0.003
259/7	0.002
259/8	0.002
260/1/2	0.002
260/1/4	0.004
260/1/5	0.003
260/1/6	0.003
260/1/7	0.002
260/1/8	0.002
263/1/1/1/1	0.040

(1)	(2)
263/1/1/1/2	0.006
263/1/1/1/3	0.006
263/1/1/1/4	0.009
263/1/1/1/5	0.022
263/1/1/1/6	0.006
263/1/1/1/7	0.022
263/1/1/2	0.009
266/1	0.16
267/1	0.019
273/1/2/1	0.012
273/3	0.02
274/1/2, 275/1/2	0.13
274/3/1/1	0.028
274/3/2	0.009
274/3/3	0.009
274/3/4	0.009
274/3/5	0.004
274/3/6	0.004
274/3/7	0.006
274/3/8	0.006
274/3/9	0.006
274/3/10	0.006
274/3/11/1	0.003
274/3/11/2	0.003
274/3/12	0.003
274/3/13	0.003
274/3/14	0.003
274/3/15	0.003
274/3/16	0.003
274/3/17/1	0.003
274/3/17/2	0.003
274/3/18	0.004
274/3/19	0.004
274/3/20	0.006
274/3/1/2	0.004
274/3/1/3	0.004
274/3/1/4	0.004
274/3/1/5	0.004
274/3/1/6	0.004
274/3/1/7	0.004
274/3/1/8	0.004
274/3/1/9	0.004
274/3/1/10	0.004
276/1/1क/1	0.022
276/1/1क/2	0.031
276/1/1क/1/1	0.008
276/1/1क/1/2	0.008
276/1/1क/1/3	0.008
276/1/1क/2/1	0.005
276/1/1क/2/2	0.005
276/1/1क/2/3	0.005
276/1/1क/3/1	0.039
276/1/1क/3/2	0.007
276/2/1/क/1	0.004
276/2/1/क/2	0.012
276/2/1/क/3/1	0.046
276/2/1/क/3/2	0.004
276/2/1/क/3/3	0.004
276/2/1/क/4	0.048
277/1/1/क/1	0.006
277/1/1/क/2	0.006
277/1/1/क/3	0.006
278/1/1	0.144
278/1/1/1	0.007
278/1/1/2	0.007
278/1/1/3	0.007
278/1/1/4	0.007
278/1/1/5	0.007
278/1/1/6	0.007
278/1/1/7	0.006
278/1/1/8	0.006
278/1/1/9	0.006
279	0.008
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	2.374

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर

(भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

क्र. 448-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—सकरिया
(घ) क्षेत्रफल—1.097 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
112/1क	0.072
113/1053/2/1	0.120
113/1053/2/2	0.008
113/1053/2/3	0.008
113/1053/2/4	0.008
113/1053/2/5	0.008
113/1053/2/6	0.008
113/1053/2/7	0.008
113/1053/2/8	0.008
181/2क/1	0.130
181/2क/3	0.050
194/1/1	0.013
194/1/2	0.003
194/1/3	0.004
194/1/4	0.003
194/1/5	0.003
194/1/6	0.004
194/1/7	0.002
194/1/8	0.004
194/1/9	0.004
194/1/10	0.004
194/1/11	0.004
195/1	0.010
195/2	0.010
195/3	0.010
195/4	0.010
195/5	0.010
195/6	0.010
195/7	0.010
198/2/1	0.005
198/2/2	0.010
198/2/3	0.010
198/2/4	0.010
199	0.038
210/1	0.003
210/2	0.001
210/3	0.002
210/4	0.001
210/5	0.001
210/6	0.001
210/7	0.001
210/8	0.002
210/9	0.002
211/1/1	0.025
211/1/1/2	0.002
211/1/1/3	0.002
211/1/1/4	0.002
211/1/1/5	0.001
211/1/1/6	0.003
211/1/1/7	0.018
211/1/2/1	0.016
211/1/2/4	0.006
211/1/2/5	0.006
211/1/2/2/1	0.006
211/1/2/2/2	0.006
211/1/2/2/3	0.006
211/1/2/2/4	0.006
211/1/2/3/1	0.012
211/1/2/3/2	0.006
211/1/2/3/3	0.006
211/1/3/1	0.004

(1)	(2)
211/1/3/2	0.003
211/1/3/3	0.006
211/1/3/4	0.003
211/1/3/5	0.003
211/1/3/6	0.006
211/1/3/7	0.006
211/1/3/8	0.003
211/1/3/9	0.005
214/1	0.052
214/3	0.004
214/4	0.004
214/5	0.004
214/6	0.004
214/7	0.004
214/8	0.004
214/9	0.004
214/10	0.006
214/11	0.006
214/12/1	0.003
214/12/2	0.003
214/12/3	0.003
214/13/1	0.006
214/13/2	0.003
214/14	0.006
214/15	0.004
214/16	0.005
214/17	0.005
214/18	0.003
214/19	0.004
214/20	0.003
214/21	0.003
214/22	0.003
214/23	0.006
214/24	0.003
214/25	0.006
214/26	0.004
214/27	0.006
214/28	0.003
214/29	0.005
214/30	0.003
214/31	0.002
214/32	0.002
214/33	0.003
214/34	0.003
323/1	0.004
323/3/1	0.004
323/3/2	0.004
323/3/3	0.004
323/3/4	0.004
323/4	0.016
323/5	0.008
323/6	0.008
323/7	0.016
323/8	0.006
323/9	0.006
323/10/1	0.003
323/10/2	0.006
323/10/3	0.003
323/11	0.012
निजी खाता भूमि योग रकबा . .	1.097

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना-रीवा (50 कि.मी.) बड़ी रेल लाईन दोहरीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 13 सितम्बर 2018

क्र. 4663-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-बंड़ोल.
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बीसावाड़ी, ब.नं.-526, प. ह. नं.—29.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—1.64 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
324	0.06
372	0.40
364	0.02
365	0.16
347	0.04
50	0.02
108	0.28
118	0.10
114	0.07
119	0.04
117	0.14
363/3	0.03
363/2	0.07
363/1	0.08
367	0.09
238	0.04
योग . .	1.64

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4664-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-भोमा.
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पौड़ी, ब.नं.-368, प. ह. नं.—43.
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—3.38 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253	0.56
248	0.15
249	0.02
260	0.14
261	0.10
262	0.22
238	0.04
237	0.10
108/4	0.04
254	0.22

(1)	(2)
274/2	0.12
274/1	0.06
314	0.20
315/1	0.20
61	0.32
51	0.21
49/1	0.29
50/1	0.01
47	0.08
49/2	0.07
46	0.07
45	0.14
43	0.02
योग . .	3.38

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4665-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-देवरी, ब.नं.-281, प. ह. नं.—99.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—3.290 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
364/1, 364/3	0.020
364/2	0.090
389	0.830
382	0.150
383	0.210
381/2	0.050
384	0.330
275/1	0.310
275/2	0.200
276/1	0.150
276/2	0.140
276/3	0.090
274/1	0.060
234/2	0.230
234/1	0.200
244/4	0.080
236	0.010
237	0.140
योग . .	3.290

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4666-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2.

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बलपुरा, ब.नं.-315, प. ह. नं.—96.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—1.500 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.150
11	0.100
21	0.010
14	0.130
15/1	0.030
17/1	0.070
17/2	0.180
20/2	0.120
27	0.010
23	0.470
26	0.030
25	0.190
98	0.010
योग निजी भूमि . .	1.500

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4667-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-भोमा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-जेवनारा, ब.नं.-216, प. ह. नं.—45.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—1.47 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
171	0.12
183/2	0.25
184	0.14
186/1	0.15
188	0.22
189	0.04
191	0.07
190	0.08

(1)	(2)
187/2	0.30
187/1	0.10
योग . .	1.47

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिगे भूमि की आवश्गकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 उपवितरक नहर की माईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4668-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-नगझर, ब.नं.-301, प. ह. नं.—96.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—4.600 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
166	0.230
167	0.200
155/2	0.450
149/5	0.150
149/1	0.210
97/4	0.250
97/2	0.120
97/3	0.320
143	0.360
144/1	0.400
145	0.010
133/5	0.060
133/4	0.180
133/2	0.140
133/3	0.240
133/1	0.170
132	0.220
130	0.290
131	0.270
126/2	0.200
124/3	0.130
योग . .	4.600

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है:—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-4 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

क्र. 4670-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. पेंच व्यपवर्तन परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 (2) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी, रा.नि.मं.-सिवनी भाग-2

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सिमरिया, ब.नं.-567, प. ह. नं.—99.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा—1.530 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

निजी भूमि का रकबा

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
258	0.050
261	0.300
263	0.150
264	0.170
265/2	0.190
260	0.010
255/1	0.540
252/2	0.120
योग . .	1.530

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना की डी-2 वितरक नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला छिंदवाड़ा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उमरिया, दिनांक 11 सितम्बर 2018

क्र. दस-भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2017-18-4476.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. ''अत: भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013'' (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—उमरिया

(ख) तहसील—पाली

(ग) ग्राम—महरोई

(घ) लगभग क्षेत्रफल (निजी भूमि)—2.232 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
441/2/1/1	0.405
137	0.162
136/1	0.120
144	0.280
138	0.105
135/2क/1/क	0.114
234/2	0.278
207/1	0.120
201	0.160
199	0.080
182/1	0.300
202	0.016
203/1	0.092
कुल रकबा . .	2.232

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बसाड़ व्यपवर्तन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, मध्यप्रदेश के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
माल सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्र. 07-अ-82-2016-17 टीकमगढ़, दिनांक 24 सितम्बर 2018

चूँकि शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः अनुसूची में अंकित भूमि धारकों की अंकित भूमि राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग टीकमगढ़ जिला–टीकमगढ़ के पक्ष में बहादुरगढ़ तालाब की नहर निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्र. 12–2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 (आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति) के तहत क्रय करने पर विचार किया जा रहा है।

अतः मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्र. 12–2/2014/सात/2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाता है कि यदि उक्त सम्बंध में किसी व्यक्ति को भूमि आदि के स्वत्व के सम्बंध में कोई आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर (सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) कार्यालयीन समय में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद म्याद गुजरे जाने पर किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति क्र. 12–2/2014/सात/2ए भोपाल दिनांक 12.11 2014 की कंडिका 11(1) एवं (2) के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

1. **परियोजना का नाम** – **बहादुरगढ़ तालाब योजना नहर निर्माण**
2. **भूमि का विवरण** – **ग्राम–स्याग, तहसील–टीकमगढ जिला–टीकमगढ़**
   अर्जित भूमि का क्षेत्रफल– 0.141 हेक्टेयर

अनुसूची

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं..	कुल रकवा हे में	अर्जित रकवा हे.में
1	भागचन्द्र, शोभाराम, मनीराम, आशाराम, गंगाराम तनय गुलाब साहू 1/4, श्रीमती भागवती पत्नी गुलाबचन्द्र, गुलाब तनय टूड़ा, हरीराम, विलेद तनय पूरन ना.बा. संर. माता हीराबाई, हीराबाई बेबा पूरन हि. 1/2 जाति साहू पता. नि.ग्रामी भूस्वामी	496	0.101	0.029
	योग–	**1 किता**	**0.101**	**0.029**
2	रामरतन, रामनजर हरदयाल तनय गोकुल मु.शिम्बू बेबा गोकुल यादव (फोत दिनांक 29.09.2017) नि.ग्राम भमिस्वामी, बालकृष्ण तनय भगवानदास 1/4 जाति यादव नि.ग्राम भूमिस्वामी	714/944	0.745	0.112
	योग–	**1 किता**	**0.745**	**0.112**

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है– बहादुरगढ़ तालाब योजना के नहर निर्माण करने हेतु।

(3) भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू–अर्जन अधिकारी अनुविभाग टीकमगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिजीत अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 20 सितम्बर 2018

क्रमांक 7283 /भू–अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण कमांक 22ए/359/2018/एमपीएस/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सांका जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील :– नरसिंहगढ जिला–राजगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम सांका जागीर

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सांका जागीर	297.588	264.942
	कुलयोग :–	297.588	264.942

क्रमांक 7282/भू–अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 22ए/359/2018/**एमपीएस**/31/859/भोपाल दिनांक 14.05.2018 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम नाईहेडी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि अनुसूची 1 में अंकित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है इस कारण सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

–: अनुसूची (1) :–

तहसील :– नरसिंहगढ जिला–राजगढ

पार्वती परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू–अर्जन प्रस्ताव,
ग्राम नाईहेडी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	अर्जित किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नाईहेडी	5.918	2.588
	कुलयोग :–	**5.918**	**2.588**

प्रकरण क्र. 7107-अ-82-2017-18 राजगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2018

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम संजयग्राम के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम संजयग्राम

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
1	कलाबाई पत्नि नवलसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	2	0.759	0.759
	योगः–	1	0.759	0.759
2	आसमानबाई बेवा रामगोपाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3	1.404	1.404
	योगः–	1	1.404	1.404
3	शिवनारायण,गीताबाई पिता पून्या राजू, बलराम, कृष्णाबाई, हेमलताबाई पिता जगदीश, जसोदी बेवा जगदीश जाति कलाल निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	4	0.316	0.316
		6/1	0.103	0.103
	योगः–	2	0.419	0.419
4	लक्ष्मीनारायण, जवाहरलाल, भूलीबाई धापूबाई, कमलाबाई, रतनबाई, भवंरीबाई पिता उमैद जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	8	0.127	0.127
		10	0.683	0.683
	योगः–	2	0.810	0.810
5	देवा पिता धन्ना जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1	0.532	0.532
		48	0.759	0.759
		298/1	0.214	0.214
		326/2	0.070	0.070
	योगः–	4	1.575	1.575
6	धमेन्द्र, नौसिंह, सोनू अमन पिता बलवतासिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1	0.244	0.244
		18/1	0.246	0.246
	योगः–	2	0.490	0.490
7	रामचंद्र पिता मांगीलाल जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	14/1	0.113	0.113
	योगः–	1	0.113	0.113

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
8	चंदूबाई बेवा महेलाद जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	15	0.139	0.139
		17	0.089	0.089
	योगः—	2	0.228	0.228
9	राधेश्याम पिता अजबसिह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	16	0.480	0.480
		50	0.437	0.437
		66	0.051	0.051
		68	0.039	0.039
		69	0.075	0.075
		72	0.422	0.422
		73	0.253	0.253
	योगः—	7	1.757	1.757
10	नन्द कुंवर बेवा भंवरसिंह, तंवरलाल, बेबी, पिंकी पिता भंवरसिंह, हरिसिंह, प्रेमसिंह, रघुवीरसिंह पिता कुमेरसिंह मु. नानीबाई बेवा कुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	19/1	0.567	0.567
	योगः—	1	0.567	0.567
11	कोमलबाई पति औतारसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	22/1	0.060	0.060
		24	0.217	0.217
	योगः—	2	0.277	0.277
12	कालूराम पिता बेगमलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	25	0.566	0.566
		29	0.600	0.600
		32	0.621	0.621
		34/1	0.214	0.214
		42	0.316	0.316
	योगः—	5	2.317	2.317
13	भूरा उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह, पप्पू पिता लाखनसिंह, अमरतोबाई पिता लाखनसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26	0.376	0.376
		49	0.466	0.466
		65	0.026	0.026
		67	0.221	0.221
		71	0.455	0.455
		74	0.253	0.253
		6	1.797	1.797
14	त्रिपालसिंह, जगलसिंह, राजूसिंह पिता प्रेमसिंह, सोरमबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27	1.122	1.122
	योगः—	1	1.122	1.122
15	रामेश्वर, शिवनारायण, ओमप्रकाश, रामचन्दर, प्रेमनारायण, प्रेमबाई, पिता मांगीलाल, उमराबाई बेवा मांगीलाल नरसंग पिता चेना जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	28	0.089	0.089
		46	2.266	2.266
	योगः—	2	2.355	2.355
16	शिवसिंह, कृष्णाबाई पिता नरभेसिंह, सजनबाई बेवा नरभेसिंह जाति राजपूत निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	31	0.945	0.945
		35/1	0.170	0.170
	योगः—	2	1.115	1.115

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
17	गुलाबसिंह, कालूराम, सीताराम, कृष्णा पिता बेगमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53	1.000	1.000
		54	0.632	0.632
		55	2.162	2.162
		58/1	0.073	0.073
		85	0.188	0.188
	योग:—	5	4.055	4.055
18	मलखानसिंह, सतनाम पिता बृजेश, हेमाबाई, बेवा बृजेश, रामवतीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण त्रिपालसिंह, जंगलसिंह, राजूसिंह पिता प्रेमसिह, सोरमबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	43	0.569	0.569
		44	0.400	0.400
		51	0.043	0.043
	योग:—	3	1.012	1.012
19	बलवंतसिंह पिता अजबसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	45	0.737	0.737
		70	0.476	0.476
		75	0.253	0.253
		76	0.432	0.432
	योग:—	4	1.898	1.898
20	रामगोपाल पिता भोला जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	47	1.985	1.985
	योग:—	1	1.985	1.985
21	सीताराम पिता बेगमलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30	0.708	0.708
		52	0.126	0.126
	योग:—	2	0.834	0.834
22	भगवानसिंह, मनोहर पिता बलगिया हि. 66 पैसे, संतोष, बालकराम, अमितकुमार, अक्षयकुमार, विनोदकुमार, पिता लक्ष्मण, पिंकारोबाई बेवा लक्ष्मण हि. 34पैसे जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89	0.051	0.051
	योग:—	1	0.051	0.051
23	अनारोबाई बेवा धारासिंह, उर्मिलाबाई बेवा बदनसिंह, मुकेश पिता केशरसिंह, फराराबाई बेवा केशरसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90	0.190	0.190
		94/1	0.332	0.332
	योग:—	2	0.522	0.522
24	भंवरिया पिता अलपतिया जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91	0.278	0.278
	योग:—	1	0.278	0.278
25	लज्जाराम पिता फूलसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92/1	0.118	0.118
	योग:—	1	0.118	0.118
26	सुशीलाबाई बेवा प्रयागसिंह भगवानसिंह पिता रामसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	93/1	0.500	0.500
	योग:—	1	0.500	0.500

स.क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
27	ओमप्रकाश दत्तक पुत्र तोरणसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	125	0.030	0.030
		312	0.860	0.500
		137/1	0.401	0.401
	योगः—	3	1.291	0.931
28	शिवनारायण पिता उकांर जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97	0.210	0.210
		126	0.030	0.030
		135/1	0.945	0.945
		300	0.019	0.019
	योगः—	4	1.204	1.204
29	कैलाशनारायण पिता उकांर जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	98	0.211	0.211
		127	0.030	0.030
		134/1	0.254	0.254
		136/1	0.199	0.199
		301	0.089	0.089
		302	0.443	0.443
	योगः—	6	1.226	1.226
30	नवलसिंह, पप्पू पिता कश्मीरसिंह जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	99	0.379	0.379
	योगः—	1	0.379	0.379
31	गोरीशंकर पिता लखतराज जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	100	0.316	0.316
	योगः—	1	0.316	0.316
32	गंगाराम, शम्भूलाल, मदनलाल, रामप्रसाद, पिता सालगराम जाति दांगी निवासी परसुलिया ग्राम भूमि स्वामी	101/1	0.295	0.295
	योगः—	1	0.295	0.295
33	रूपसिंह, जीवनसिंह, बलराम, नैनासिंह, हजारीलाल, धीरसिंह पिता नंदलाल, सुखदेव पिता भगवतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2	0.303	0.303
	योगः—	1	0.303	0.303
34	गुलाब, गोरीशंकर, बनवारी, मगल पिता तखतराम, रघुवीर पिता जागिरिया जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	104	0.021	0.021
	योगः—	1	0.021	0.021
35	अंगूरसिंह, लहरिया पिता गुलाबसिंह सुनील पिता रोशनलाल जाति भानमता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	303	1.156	1.040
	योगः—	1	1.156	1.040
36	मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	317/1	0.011	0.011
		320/1	0.007	0.007
	योगः—	2	0.018	0.018

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
37	गुलाब पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	318	0.007	0.007
		321	0.073	0.073
	योगः—	2	0.080	0.080
38	रघुवीरसिंह पिता जागिरिया जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	319/1	0.007	0.007
		322	0.072	0.072
	योगः—	2	0.079	0.079
39	बनवारी, गोरीशंकर,मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	343/1	0.063	0.063
	योगः—	1	0.063	0.063
40	बनवारी पिता तखतसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	331	0.040	0.040
	योगः—	1	0.040	0.040
41	बलराम पिता जगन्नाथ जाति रूहला निवासी शाहपुरा ग्राम भूमि स्वामी	356	0.025	0.025
		358/1	0.003	0.003
		373/659	0.063	0.063
		422/3	0.099	0.099
		604/3	0.287	0.287
		630/2	0.266	0.266
	योगः—	6	0.743	0.743
42	रवाराम पिता जगन्नाथ जाति रूहला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/2	0.096	0.096
		604/2	0.287	0.287
		630/3	0.265	0.133
	योगः—	3	0.648	0.516
43	देवीराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	422/1	0.096	0.096
		604/1	0.134	0.134
		630/1	0.266	0.266
	योगः—	3	0.496	0.496
44	लीलाबाई पुत्री नंदराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	364	0.607	0.607
	योगः—	1	0.607	0.607
45	भारतसिंह पिता प्रभूलाल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	405	0.197	0.197
	योगः—	1	0.197	0.197
46	द्रोपदीबाई पति भागमल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	371	0.091	0.091
		406	0.379	0.379
	योगः—	2	0.470	0.470
47	बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रूहैला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373/1	0.899	0.899
		383/1	0.101	0.101
		604/4	0.152	0.152
		629/1	0.012	0.012
	योगः—	4	1.164	1.164

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
48	लक्ष्मीनारायण पिता बट्टूलाल जाति रूहैला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	373/2	0.847	0.847
		383/2	0.101	0.101
		628/2	0.050	0.050
		629/2	0.013	0.013
	योगः—	4	1.011	1.011
49	सेवाबाई पति मनोज जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	375	0.278	0.278
	योगः—	1	0.278	0.278
50	बापूलाल, गंगाराम, पिता भागमल मु. अमरीबाई बेवा भागमल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	382/1	0.394	0.236
		384	0.214	0.214
		385	0.708	0.566
		386	0.063	0.063
		387	0.177	0.177
		389	0.051	0.051
	योगः—	6	1.607	1.307
51	देवकरण पिता बापूलाल जाति रूहेला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	388	1.670	1.670
	योगः—	1	1.670	1.670
52	मांगीलाल, तुलसीबाई, धनुबाई, सुजानबाई, पिता नानजी जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	603	0.371	0.371
		605	0.046	0.046
		606	0.144	0.144
		609	0.198	0.198
		610	0.413	0.413
		618	0.047	0.047
		621	0.021	0.021
	योगः—	7	1.240	1.240
53	राधेश्याम पिता शिवनारायण जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	602	0.371	0.371
	योगः—	1	0.371	0.371
54	लाडबाई पति सुरेशचन्द कौशल्याबाई पति रमेशचन्द जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	419	0.333	0.333
		420	0.253	0.253
		421	0.544	0.544
	योगः—	3	1.130	1.130
55	प्रमोदकुमार पिता वदामसिंह जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	401	0.506	0.506
		402	0.329	0.329
		413	0.026	0.026
		414	0.025	0.025
		415	0.225	0.225
		417	0.150	0.150
		418	0.139	0.139
	योगः—	7	1.400	1.400

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
56	संगीताबाई पति प्रमोदकुमार जाति कंजर निवासी ग्राम भूमि स्वामी	403	0.481	0.481
	योगः—	1	0.481	0.481
57	लीलाबाई बेवा नारायण, अमृत, पप्पू पिता नारायण जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	431/1	0.297	0.297
	योगः—	1	0.297	0.297
58	कालूराम पिता मोती जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	432	0.300	0.300
	योगः—	1	0.300	0.300
59	देवबाई पति सालगराम जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	423	0.898	0.898
		631	0.367	0.055
	योगः—	2	1.265	0.953
60	प्रहलाद पिता किशनलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	425	0.100	0.100
		427	0.031	0.031
		431/2	0.097	0.097
	योगः—	3	0.228	0.228
61	मोती पिता रामा जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	429	0.078	0.078
	योगः—	1	0.078	0.078
62	बट्टलाल पिता देवीराम जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	434	0.102	0.102
		439	0.076	0.076
		440	0.052	0.052
		447	0.085	0.085
		449	0.066	0.066
		472	0.085	0.085
		473	0.283	0.283
		476	0.051	0.020
	योगः—	8	0.800	0.769
63	घीसीबाई पुत्री किशनलाल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	601	0.371	0.371
		608	0.143	0.143
		613	0.197	0.197
		614	0.047	0.047
		616	0.046	0.046
		619	0.021	0.021
		622	0.414	0.062
		623	0.203	0.081
	योगः—	8	1.442	0.968
64	विजयसिंह पिता करणसिंह जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	627	0.569	0.170
	योगः -	1	0.569	0.170

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
65	शिवनारायण पिता गोपीलाल जाति रूवाला निवासी ग्राम भूमि स्वामी	607	0.143	0.143
		611	0.413	0.372
		612	0.198	0.198
		615	0.046	0.046
		617	0.047	0.047
		620	0.021	0.021
		624	0.203	0.006
	योगः—	7	1.071	0.833
66	सजनबाई बेचा किशन, प्रहलाद, रोड़ीबाई पिता किशन जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	426	0.100	0.100
		428	0.032	0.032
		430	0.314	0.314
		433	0.079	0.079
	योगः—	4	0.525	0.525
67	राधास्वामी सत्संग व्यास प्रतिनिधि श्री घनश्याम रामानी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	139	2.276	0.683
		435	0.101	0.101
		436	0.101	0.101
		437	0.076	0.076
		438	0.076	0.076
		441	0.050	0.050
		442	0.050	0.050
		445	0.084	0.084
		446	0.084	0.084
		451	0.068	0.068
		454	0.068	0.068
		470	0.084	0.084
		471	0.086	0.086
		474	0.283	0.283
		475	0.282	0.282
		392	0.683	0.478
		590	1.012	0.202
		594	0.411	0.206
		598	0.423	0.296
		599	0.421	0.336
		194	2.024	0.304
		150/1	0.206	0.206
	योगः—	22	8.949	4.204

68	दौलतराम पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	160/1	0.226	0.226
		160/7/1	0.200	0.200
	योगः–	2	0.426	0.426
69	चम्पालाल पिता गोपीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	160/2	0.225	0.225
		160/6/1	0.199	0.199
	योगः–	2	0.424	0.424

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
70	रामबगस पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	160/3	0.451	0.451
	योगः–	1	0.451	0.451
71	शिवनारायण पिता श्रीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	160/4	0.506	0.406
		160/8	0.451	0.361
	योगः–	2	0.957	0.767
72	नरसंगलाल पिता चैनाजी जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	160/5	0.506	0.416
	योगः–	1	0.506	0.416
कुल योगः–		**206**	**66.630**	**59.243**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018

क्रमांक/ 7058 /भू–अर्जन/2018 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक/ /अ–82/2017–18 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में **मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना** तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम **रोज्या** के लिए रोज्या पम्प हाउस मार्ग में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा–11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि **मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना** का निर्माण पूर्व से चल रहा है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा–11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

–: अनुसूची (1) :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्रभावित भूमि

स.क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर
		कुल प्रभावित रकबा (हे.में.)
(1)	(2)	(3)
1	रोज्या	**0.355**
	कुलयोग :–	**0.355**

–: अनुसूची (2) :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रोज्या पम्प हाउस से करेड़ी के रास्ता तक की भूमि का भू–अर्जन प्रस्तावित, ग्राम –रोज्या

तहसील :– राजगढ़ जिला :– राजगढ़

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	जगदीश पिता जगन्नाथ जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	153	0.582	0.110
	किता	1	**0.582**	**0.110**
2	बंशीलाल पिता शंकरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	152/3/2	0.143	0.024
	किता	1	**0.143**	**0.024**

3	घनश्याम पिता भंवरलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	152/3/1	0.143	0.024
किता		1	**0.143**	**0.024**
4	नरबदीबाई बेवा रामनारायण, रक्षाबाई, गुड्डीबाई पिता रामनारायण जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	152/2	0.287	0.048
किता		1	**0.287**	**0.048**

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	रकबा (हे.में.)	प्रभावित रकबा (हे.में.)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5	कमलसिंह पिता देवीलाल जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	152/1	0.287	0.048
किता		1	**0.287**	**0.048**
6	देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब, मु. पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/3 कालू पिता उँकार हि. 1/3, बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन मु. केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कँवरलाल मु. भंवरीबाई बेवा कँवरलाल हि. 1/3 जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	185	0.038	0.038
किता		1	**0.038**	**0.038**
7	देवीलाल, कैलाश पिता मेहताब, पाचुबाई बेवा मेहताब हि. 1/4 कालू, गंगाधर पिता उँकार हि. 1/2, बापू, रामचन्दर पिता राधाकिशन, केशरबाई बेवा राधाकिशन, गोवर्धन पिता कँवरलाल, भंवरीबाई बेवा कँवरलाल हि. 1/2 जाति दांगी नि.ग्राम भू–स्वामी	186	0.013	0.013
किता		1	**0.013**	**0.013**
8	दरियाव सिंह, सुरेश पिता हरीसिंह, रतनबाई बेवा हरीसिंह जाति सौंधिया नि.ग्राम भू–स्वामी	197	0.177	0.050
किता		1	**0.177**	**0.050**
किता		**8**	**1.670**	**0.355**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण कमांक 7053/अ–82/2017–2018 राजगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018

(अंतर्गत धारा–19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ की ग्राम शाहपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा–19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

–: अनुसूची :–

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :– ग्राम शाहपुरा

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	देवीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति रूवाला नि. ग्राम	114	0.253	0.253
		121	0.316	0.316
		123	0.139	0.139
	योग :–	3	0.708	0.708
2	मोती पिता रामा जाति बेलदार	124/1	0.050	0.050
	योग :–	1	0.050	0.050
3	बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रूहैला पता नि. ग्राम	109/1/1	0.528	0.528
	योग :–	1	0.528	0.528
4	लक्ष्मीनारायण पिता बट्टूलाल जाति रूहैला पता नि. ग्राम	109/1/2	0.528	0.528
		235/2	0.158	0.158
	योग :–	2	0.686	0.686
5	देवीराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला	110/1	0.337	0.337
		116/1	0.046	0.046
		117/1	0.021	0.021
		118/2/1	0.085	0.085
	योग :–	4	0.489	0.489
6	रेवाराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला	110/2	0.337	0.337
		116/2	0.047	0.047
		117/2	0.021	0.021
		118/2/2	0.084	0.084
	योग :–	4	0.489	0.489
7	बलराम पिता जगन्नाथ जाति रूवाला	110/3	0.338	0.338
		116/3	0.046	0.046
		117/3	0.021	0.021
		118/2/3	0.084	0.084
	योग :–	4	0.489	0.489
8	रामप्रसाद हरि पिता धूलजी उमरावबाई बैवा धूलजी जाति बेलदार	111	0.114	0.114
		112	0.038	0.038
		182/2	0.253	0.253
		184/1	1.024	1.024
		191/2	0.841	0.841
	योग :–	5	2.270	2.270

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
9	दिनेश पिता करणसिह जाति रूवाला नि.ग्राम	115	1.733	1.733
	योग :–	1	1.733	1.733
10	करणसिह पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	118/3/1	0.031	0.031
	योग :–	1	0.031	0.031
11	फूलसिह पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	118/3/2	0.032	0.032
		118/349/2/3	0.256	0.256
		181/1/4	0.236	0.236
	योग :–	3	0.524	0.524
12	सीताराम पिता बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	118/3/3	0.032	0.032
		118/4/2	0.104	0.104
		118/349/2/4	0.153	0.153
		181/1/5	0.237	0.237
	योग :–	4	0.526	0.526
13	राजूबाई पिता गोपीलाल कालूराम पिता प्रभुलाल जाति बेलदार नि. ग्राम	118/3/4	0.047	0.047
		181/1/1	0.354	0.354
	योग :–	2	0.401	0.401
14	राजूबाई पिता गोपीलाल, सतीश ना.बा. पिता रमेश सर. पर. माता दलीबाई बैवा रमेश जाति बेलदार नि. ग्राम	118/3/5	0.048	0.048
		181/1/2	0.354	0.354
	योग :–	2	0.402	0.402
15	रामप्रसाद, चंदरसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि. ग्राम	118/4/1	0.200	0.200
	योग :–	1	0.200	0.200
16	शिवनारायण, भावसिंह, गोरीलाल, किशनलाल पिता जसा जाति बंजारा नि. ग्राम	118/347	0.468	0.468
		204	0.316	0.316
	योग :–	2	0.784	0.784
17	विजयसिंह पिता करण सिंह जाति रूवाला नि.ग्राम	119	0.506	0.506
		120	0.531	0.531
		122	0.379	0.379
	योग :–	3	1.416	1.416
18	प्रहलाद रोडीबाई आ किशन जाति बेलदार नि.ग्राम	124/2	0.025	0.025
	योग :–	1	0.025	0.025
19	लीलाबाई बेवा नारायण अमृत, पप्पू आ. नारायण जाति बेलदार नि.ग्राम	124/3	0.026	0.026
	योग :–	1	0.026	0.026
20	जितेन्द्र पिता रामबाबू जाति कंजर नि. ग्राम	181/1/3	0.236	0.236
	योग :–	1	0.236	0.236
21	रामप्रसाद पिता धुलिया जाति बेलदार नि.ग्राम	181/2	0.632	0.632
		250	0.164	0.164
		253	0.063	0.063
		266	0.101	0.101
	योग :–	4	0.960	0.960

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
22	रमेश पिता रामप्रसाद जाति बेलदार नि.ग्राम	182/1	0.291	0.291
		183	0.253	0.253
	योग :–	2	0.544	0.544
23	अयोध्याबाई पति भारतसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम	184/2/1	0.283	0.283
	योग :–	1	0.283	0.283
24	चंदर पिता धूलजी नि.ग्राम	184/2/2	0.741	0.741
	योग :–	1	0.741	0.741
25	धर्मेन्द्र, संतोष, चतरबाई, जमनाबाई ना.बा. पिता भारतसिंह सर. माता अयोध्याबाई पत्नि भारसिंह मु0 अयोध्याबाई पत्नि स्व. भारतसिंह, बापूलाल पिता नवल जाति बेलदार नि. ग्राम	185	0.481	0.481
	योग :–	1	0.481	0.481
26	मु. नानीबाई बैवा जगदीश, देवीलाल ना.बा. पि. जगदीश सरपस्त माता नानीबाई बैवा जगदीश जाति बेलदार नि. ग्राम	186/1	1.075	1.075
		186/2	0.051	0.051
	योग :–	2	1.126	1.126
27	काशीराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि. ग्राम	187	0.316	0.316
		188	1.770	1.770
		274	0.620	0.130
	योग :–	3	2.706	2.216
28	कल्याणसिंह पिता कशमीर जाति बेलदार नि. ग्राम	189/1	0.354	0.354
		190/1	0.095	0.095
	योग :–	2	0.449	0.449
29	हीरालाल पि भंवरलाल हि. 24 पैसे, करणसिंह, फूलसिंह, सीताराम पिता बापूलाल हि. 76 पैसे जाति बेलदार नि.ग्राम	189/2/1	0.080	0.080
		190/2	0.048	0.048
		206/2	0.256	0.256
	योग :–	3	0.384	0.384
30	सुगनबाई पत्नि नानजी जाति बेलदार नि.ग्राम	189/2/2	0.097	0.097
		206/3/1	0.152	0.152
		206/3/2	0.104	0.104
	योग :–	3	0.353	0.353
31	सरदारबाई पत्नि प्यारजी जाति रूवाला नि. ग्राम	189/3	0.177	0.177
		190/3	0.047	0.047
	योग :–	2	0.224	0.224
32	रघुनाथ पिता किशनलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	191/1	0.841	0.841
	योग :–	1	0.841	0.841
33	मेहरबान पिता बद्रीलाल, प्रेमबाई बेवा बद्रीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	194/1	0.240	0.240
		195/3/1	0.040	0.040
		205/2	0.233	0.233
		205/12	0.039	0.039
	योग :–	4	0.552	0.552
34	शंकरलाल, भगवानसिंह पिता जगन्नाथ सावन ना.बा. पिता रामप्रसाद सर. माता भानुबाई बैवा रामप्रसाद, छमाबाई सम्पतबाई पिता जगन्नाथ जाति बेलदार नि.ग्राम (अहस्तांतरित)	194/2	0.240	0.240
		195/2	0.080	0.080
		200/1	0.316	0.316
	योग :–	3	0.636	0.636

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
35	शम्भूलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	194/3	0.240	0.240
		195/3/2	0.040	0.040
		205/3	0.233	0.233
		205/10	0.039	0.039
	योग :–	4	0.552	0.552
36	भागमल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	195/1	0.080	0.080
		200/2/2	0.120	0.120
		205/4	0.233	0.233
		205/11	0.039	0.039
	योग :–	4	0.472	0.472
37	मेहरबान सिंह पिता भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम	196/1	0.259	0.259
		197/1/1	0.082	0.082
		203/1/1	0.168	0.168
	योग :–	3	0.509	0.509
38	कमलाबाई बैवा रामसिह जाति बेलदार नि.ग्राम	196/2	0.260	0.260
		197/2	0.095	0.095
		198/2	0.354	0.354
		199/2	0.051	0.051
		236/2	0.139	0.139
	योग :–	5	0.899	0.899
39	सिद्धूलाल, हुकुमसिहं, मेहरबानसिंह पिता भेरू, कलाबाई बैवा भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम	197/1/2	0.013	0.013
	योग :–	1	0.013	0.013
40	हुकुमसिंह पिता भेरू जाति बेलदार नि.ग्राम	198/1/1	0.253	0.253
		199/1	0.050	0.050
		203/1/2	0.142	0.142
	योग :–	3	0.445	0.445
41	रामप्रसाद, चंदरसिंह, हरिसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि.ग्राम	198/1/2	0.100	0.100
		201/1/2	0.014	0.014
	योग :–	2	0.114	0.114
42	रंगलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	200/2/1	0.120	0.120
		205/1	0.233	0.233
		205/8	0.039	0.039
	योग :–	3	0.392	0.392
43	मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	201/1/1	0.044	0.044
		202/1	0.209	0.209
	योग :–	2	0.253	0.253
44	मदन पिता नंदराम जाति बेलदार नि.ग्राम	202/2	0.208	0.208
		203/2	0.310	0.310
	योग :–	2	0.518	0.518
45	हिंदुसिह पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	205/5	0.233	0.233
		205/9	0.038	0.038
		245/1	0.051	0.051
	योग :–	3	0.322	0.322
46	रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल मु0 हरकूबाई बैवा बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	205/6	0.233	0.233
		205/13	0.039	0.039
		245/2	0.050	0.050
	योग :–	3	0.322	0.322

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
47	शम्भूलाल, भागमल, बद्रीलाल, रंगलाल, हिंदुसिंह पिता गोरीलाल, भंवरीबाई बैवा गोरीलाल, रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल, हरकूबाई बेवा बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम	205/7	0.013	0.013
	योग :–	1	0.013	0.013
48	गंगाराम, मानसिंह, फतेहसिंह, नानजी पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/1	0.013	0.013
	योग :–	1	0.013	0.013
49	मानसिंह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/2	0.125	0.125
	योग :–	1	0.125	0.125
50	नानजी पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/4	0.162	0.162
	योग :–	1	0.162	0.162
51	कैलाश, इंदरसिंह, बलराम, दयालसिह पिता गंगाराम, हिम्मतबाइ बैवा गंगाराम जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/3	0.101	0.101
	योग :–	1	0.101	0.101
52	फतेहसिंह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्राम	206/1/5	0.125	0.125
	योग :–	1	0.125	0.125
53	देव्या, गणपत पिता प्रेम, सुंदरबाई बैवा प्रेम जाति नट नि.ग्राम	207/1	0.246	0.246
		208/1/2	0.442	0.442
		221/1/1	0.512	0.512
		226/1/2	0.538	0.538
		228/1	0.310	0.310
	योग :–	5	2.048	2.048
54	रामसिंह पिता मदन जाति नट नि.ग्राम	207/2/1	0.082	0.082
		208/1/3/1	0.295	0.295
		221/1/2/1	0.171	0.171
		229/2/1	0.457	0.457
	योग :–	4	1.005	1.005
55	मांगीलाल पिता मदन जाति नट नि.ग्राम	207/2/2	0.082	0.082
		208/1/3/2/2	0.042	0.042
		221/1/2/2/1	0.110	0.110
	योग :–	3	0.234	0.234
56	अमृत पिता मदन जाति नट नि.ग्राम	207/2/3	0.083	0.083
		208/1/3/3/2	0.042	0.042
		221/1/2/3	0.171	0.171
		226/1/1/1	0.445	0.445
		227/2	0.013	0.013
	योग :–	5	0.754	0.754
57	कालूराम पिता प्रेमा जाति नट नि.ग्राम	208/1/1	0.443	0.443
		227/1	0.012	0.012
		229/1	0.499	0.499
	योग :–	3	0.954	0.954

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
58	रामसिहं, रामचरण, सुरेश, ओमप्रकाश नेनसिंह पिता बद्रीलाल, गंगाबाई बेवा बद्रीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम	208/2	0.721	0.721
		220	0.164	0.164
		222	1.720	1.700
		221/2	0.822	0.822
		223	0.557	0.557
		224	0.215	0.215
		225	0.164	0.164
		259/1	0.442	0.442
		260/1	0.119	0.119
		261/1	0.355	0.355
		262/1	0.570	0.570
		270/1/1	0.095	0.095
		281	0.759	0.720
	योग :–	13	6.703	5.924
59	गुलाबबाई पत्नि शिवनारायण जाति रूहेला नि.ग्राम	221/1/2/2/2	0.061	0.061
		226/1/1/2	0.092	0.092
		228/2	0.310	0.310
		229/2/2	0.043	0.043
	योग :–	4	0.506	0.506
60	बाबूलाल, कमलसिंह, रामप्रसाद श्याम पिता जगन्नाथ गुजर नि.ग्राम	226/2	0.316	0.316
		252/1/1	0.164	0.164
		252/1/2	0.164	0.164
		252/2/2	0.254	0.254
		261/2	0.632	0.632
		262/2	0.632	0.632
		280	0.822	0.040
	योग :–	7	2.984	2.202
61	देवबाई पिता सालगराम जाति रूवाला नि.ग्राम	230	0.190	0.190
		231	2.086	2.086
	योग :–	2	2.276	2.276
62	मांगीलाल दत्तक पुत्र गोरीलाल हि. 0.50 पैसे नंदराम पि. हरलाल 0.50 पैसे जाति बेलदार नि.ग्राम	234	0.468	0.468
		243	0.759	0.759
		247	0.848	0.848
		192	0.721	0.721
		193	0.329	0.329
	योग :–	5	3.125	3.125
63	बद्रीलाल पिता बट्टूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम	235/1	0.158	0.158
	योग :–	1	0.158	0.158
64	रामप्रसाद, चंदरसिंह हरिसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार नि.ग्राम	236/1	0.139	0.139
	योग :–	1	0.139	0.139
65	शिवचरण, भारतसिंह, इंदरसिंह पिता शम्भूलाल जाति रूहाला नि.ग्राम	351/282	0.468	0.468
		240	0.683	0.683
		267	0.921	0.921
		268	0.974	0.974
		269	0.089	0.089
	योग :–	5	3.135	3.135

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
66	अमरसिंह,बद्री, जगदीश द्रोपती, कला पिता भगा जाति बंजारा नि.ग्राम	242	0.569	0.569
	योग :–	1	0.569	0.569
67	नानू बेवा बापूलाल रतिराम पिता बापूलाल जाति रूवाला नि.ग्राम	244	1.733	1.733
	योग :–	1	1.733	1.733
68	मोहनसिंह पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्राम	246/1	0.202	0.202
		248/1	0.045	0.045
		254/1	0.835	0.835
	योग :–	3	1.082	1.082
69	रामनरेश पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्राम	246/2	0.203	0.203
		248/2	0.044	0.044
		254/2	0.835	0.835
	योग :–	3	1.082	1.082
70	हेमराज पिता बद्रीलाल मु0 सौरमबाई बैवा बद्रीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम	249/1/1	0.620	0.620
	योग :–	1	0.620	0.620
71	अमृतलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्राम	249/2	0.202	0.202
	योग :–	1	0.202	0.202
72	बहूलाल, जगन्नाथ, चैनसिंह पिता किशनलाल मु0 अमरू बेवा किशनलाल जाति रूवाला नि.ग्राम पनाली	250/282	0.696	0.556
	योग :–	1	0.696	0.556
73	शम्भूलाल पिता मेहताब जाति रूवाला नि.ग्राम पनाली	255	0.089	0.089
		256	0.316	0.316
		257	0.354	0.354
	योग :–	3	0.759	0.759
74	छोगमल, विजयसिंह, हेमराज पिता मुन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्राम पनाली	258	0.228	0.228
	योग :–	1	0.228	0.228
75	चंदरसिंह पिता रेवाराम जाति रूवाला नि. ग्राम पनाली	263/1/1	0.142	0.142
		264/1/1	0.199	0.199
	योग :–	2	0.341	0.341
76	कालूराम पिता रेवाराम जाति रूवाला नि. ग्राम पनाली	263/1/2	0.142	0.142
		264/1/2	0.200	0.200
	योग :–	2	0.342	0.342
77	लक्ष्मीचंद पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि. ग्राम पनाली	263/2	0.285	0.285
		264/2	0.398	0.398
	योग :–	2	0.683	0.683
78	रामबाबू, बलराम, श्यामबाई कौश्ल्याबाई पिता अमृतलाल मु0 कमलाबाई बेवा अमृतलाल जगदीश पिता भागमल जाति रूवाला नि.ग्राम पनाली	265/1	0.709	0.709
		283	1.138	1.138
		284	0.177	0.177
	योग :–	3	2.024	2.024

स.क.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
79	सीताराम, बनेसिंह, करणसिंह पिता गंगाधर, मायाबाई बेवा गंगाधर जाति गुर्जर	271	0.164	0.164
		272	1.833	1.833
		273	0.304	0.304
		270/2/1	0.172	0.172
	योग :–	4	2.473	2.473
80	बापूलाल पिता भंवरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	285	0.051	0.030
		287/1	0.290	0.140
		286	0.405	0.100
	योग :–	3	0.746	0.270
81	बद्रीलाल पिता भंवरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	287/2	0.444	0.300
		295/1	0.025	0.025
		296/1	0.108	0.050
	योग :–	3	0.577	0.375
82	रमेश पिता किशनलाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	288/1	0.790	0.790
		289/1	0.285	0.285
	योग :–	2	1.075	1.075
83	गोरीलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	288/2	0.766	0.766
		289/2	0.102	0.102
		293/1	0.030	0.030
		294	0.177	0.177
	योग :–	4	1.075	1.075
84	बापूलाल पिता घीसालाल जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	289/3	0.144	0.144
		292/1	0.986	0.946
		293/2	0.109	0.109
	योग :–	3	1.239	1.199

85	रमेश पिता भवंरजी जाति रूवाला नि. ग्राम आशापुरा	295/2	0.013	0.013
		296/2	0.485	0.285
	योग :–	2	0.498	0.298
86	रामसिंह पिता बद्रीलाल जाति गुर्जर नि. ग्राम	209/2/2	0.696	0.696
		209/2/3	0.632	0.632
	योग :–	2	1.328	1.328
87	रामलाल पिता नन्दराम, प्रभुबाई बेवा नन्दराम जाति चमार नि. ग्राम बर्गिया	291/1/1	0.740	0.740
	योग :–	1	0.740	0.740
88	चरणसिंह पिता कालूराम जाति नट नि.ग्राम भू–स्वामी	208/1/3/2/1	0.253	0.253
	योग :–	1	0.253	0.253
89	अशोक पिता रूपसिंह जाति नट नि.ग्राम भू–स्वामी	208/1/3/3/1	0.253	0.253
	योग :–	1	0.253	0.253
90	जगन्नाथ पिता नन्दराम जाति रूवाला नि.ग्राम भू–स्वामी	109/2	1.056	1.056
	योग :–	1	1.056	1.056
	कुल योग :–	**228**	**73.338**	**70.229**

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू–अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

निर्वाचन आयोग भारत की अधिसूचनाएं

मध्यप्रदेश शासन, विधि (निर्वाचन) कार्य, विभाग

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2018

फा. क्र. ई. पी. 34-2014-चार-186.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-MP-LA(34-2014)-2018 (अभय सिंह विरुद्ध श्री राकेश सिंह) दिनांक 10 सितम्बर 2018 सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

राकेश कुशरे, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड़,
नई दिल्ली–110001
दिनांक :– 10 सितम्बर, 2018
19 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/म.प्र.–वि.स./(34/2014)/2018 :– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, श्री अभय सिंह द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 34 (अभय सिंह विरूद्ध श्री राकेश सिंह) में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ के दिनांक 27.07.2018 के निर्णय/आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है ।

(संलग्न निर्णय यहाँ मुद्रित करें)

आदेश से,
अनुज जयपुरियार
(अनुज जयपुरियार)
प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan
Ashoka Road,
New Delhi-110001
Dated:- 10th September, 2018
19 Bhadrapada, 1940 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 82/MP-LA/(34/2014)/2018 :- In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order dated 27.07.2018 of the Jabalpur Bench of Honb'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 34 of 2014 (Abhay Singh Vs. Shri Rakesh Singh) filed by Shri Abhay Singh.

(HERE PRINT THE JUDGEMENT ATTACHED)

By Order,

Jaipuriar

(ANUJ JAIPURIAR)
PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR

ELECTION PETITION NO. 34/2014

Petitioner : Abhay Singh son of late Shri Ashok Singh , aged about 31 years resident of village and post Belkheda , Tahsil Shahpur Dist. Jabalpur

Versus

Respondent: Shri Rakesh Singh @ Ghanshyam Singh, son of Late Shri Surendra Singh Thakur, aged about 53 years, resident of 578, South Civil Lines, Jablapur. Jabalpur

ELECTION PETITION UNDER SECTION 81 OF THE REPRESENTATION OF PEOPLES ACT, 1951

The petitioner named above begs to submit as under :-

Facts of the case

1. That, the petitioner is elector from Jabalpur Parliamentary Constituency no. 13. His name is recorded in Assembly Constituency no.96 Bargi, Jabalpur, Tahsil and District Jabalpur. The petitioner is recorded in part No. 19 serial no. 454.

2. That, the petitioner is challenging the election of respondent no. 1 from Member of Parliamentary Constituency No 13, Jabalpur under section 101-B, 101-D (2), (4), 123 (2), 123 (3), 123 (4) and 123 (7) of Representation of People Act, 1959.

3. That, the respondent was declared as elected from Jabalpur Constituency no. 13 as Member of Parliament by majority of votes on 16.05.2014. That, there were 15 candidates to contest the election.

4. That, the respondent submitted his nomination form for the post of Member of Parliament, 13 Lok Sabha Jabalpur Constituency before the District Returning Officer, Jabalpur..

5. That, the polling took place on 10.04.2014 and counting took place on 16.05.2014 and on the same date the election result was declared and

29 JUN 2014

Registrar (J-II) High Court of Madhya Pradesh JABALPUR (M.P.)

NOTARY GOVT. OF INDIA

Verification

I Abhay Singh, son of Late Shri Ashok Singh, aged about 31 years, resident of Belkheda, Tahsil Shahpur, Distt. Jabalpur do hereby verify that the contents of this para are true to my personal knowledge and belief and the documents are the true copy of the original documents. Hence signed and verified at Jabalpur on 28-6-2014

Abhay Singh

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : AT JABALPUR

Election Petition No: 34/2014

Abhay Singh S/o Late Ashok Singh,
Aged about 31 years, resident of Village
and Post- Belkheda, Tehsil-Shahpur
District-Jabalpur (M.P.).

.....Petitioner

V/s

Rakesh Singh @ Ghanshyam Singh
S/o Late Surendra Singh Thakur, aged
about 53 years, resident of 578, South Civil
Lines, Jabalpur (M.P.).

.....Respondent

Present: **Hon'ble Shri Justice C.V. Sirpurkar**

Shri P.D.Gupta, counsel for the petitioner.

Shri R.N. Singh, Senior counsel with Shri Arpan J Pawar, Shri Akshay Pawar, Sushri Aishwarya Singh and Sushri Nidhi Padam, Advocates for the respondent.

JUDGMENT
(27/07/2018)

1. This election petition under Section 81 read with Section 80 of The Representation of the People Act, 1951, (hereinafter referred to in this judgment as "the Act") has been preferred by an elector from the Jabalpur Parliamentary Constituency No.13 challenging the election of respondent Rakesh Singh on the ground that he adopted corrupt practices during election campaign.

2. The following facts in this election petition are either admitted or are not specifically denied. In all 15 candidates contested the election for membership of Lok-Sabha from Parliamentary Constituency No.13-Jabalpur, including present

respondent Rakesh Singh. The polling took place on 10.04.2014. Counting was held on 16.05.2014. On the same date, election result was declared and respondent Rakesh Singh was declared as the returned candidate on the ticket of Bhartiya Janta Party by simple majority of votes poled. Petitioner Abhay Singh was an elector from Jabalpur Parliamentary Constituency. His name was recorded in the electoral roll at Serial no.454 of Part no.19 of Assembly Constituency No.96-Bargi, Jabalpur.

3 (a). Apart from aforesaid undisputed facts, the case of the petitioner may be summarized as hereunder: The election of the respondent is bad and void and it is liable to be declared to be so by reason of the corrupt practices adopted by the respondent and/or his election agent and/or by other persons with his or his election agent's consent. There has been callous non-compliance with the provisions of the Act, Conduct of the Election Rules, 1961 and the orders made thereunder by the Election Commission. Thus, the conduct of respondent squarely falls under the ambit of corrupt practices as described under Section 123 (2) (a) (i) and (7) (d) of the Act.

3 (b). The particulars of the corrupt practices allegedly adopted by the respondent were as follows: The respondent was guilty of corrupt practice of exercising undue influence by threatening the electors and intimidating the voters of at least 2 out of 8 Assembly Constituencies forming Parliamentary Constituency No.13-Jabalpur, not to vote or to vote for him or to vote in a manner other than that provided by the law. Those 2 assembly Constituencies were Bargi Assembly Constituency No.96 and Jabalpur-Rsdy (SC) Assembly Constituency No.97. At about 07:00 p.m. on 03.04.2014 at Village-Mankhedi (Tehsil-Shahpur, District-Jabalpur), respondent was seen and heard asking Smt. Pratibha Singh (BJP M.L.A. from Bargi Assembly Constituency), her sons Golu Singh and Neeraj

Singh to let loose a reign terror in Bargi Assembly Constituency. He asked them to use all means including unfair to do so. They were assured by the respondent that he will see to it that no action is taken against them and their associates by the Police Authorities or the District Administration, so that they would have free hand in terrorizing the voters. Thus, at the behest of the respondent, Golu Singh and Neeraj Singh were seen roaming with their associates armed with guns and other arms terrorizing the Congress workers and voters in the entire Bargi Assembly Constituency. Despite complaints to the police officers and District Administration, nothing was done due to pressure from the respondent. This attitude of the Administration ultimately resulted in firing by Golu Singh and Neeraj Singh and others at Village-Mankhedi; wherein, 5-6 workers of Congress Party were grievously injured. In aforesaid villages, electors were not able to exercise their constitutional right to vote freely and fairly due to undue pressure, intimidation, threats and perils caused by the workers/supporters of BJP, at the behest of the respondent.

3 (c). At about 03:30 p.m. on 07.04.2014, Golu Singh opened fire upon the Congress workers at Village-Mankhedi, P.S.-Belkheda. He was accompanied by Neeraj Singh, Pushpraj Singh, Yashpal Choudhary and Ramgopal Choudhary. The Congress workers namely Abhay Singh (Petitioner), Rakesh Patel, Durjan Patel, Roopsingh Patel and Dhan Singh Thakur sustained serious injuries and were rushed to Medical College, Jabalpur. At about 04:30 p.m. on 07.04.2014, the FIR was lodged against the aforesaid persons. At about 06:30 on 07.04.2014, the victims were admitted to Metro Hospital, Jabalpur for gun-shot injuries.

3(d). It has further been pleaded that the respondent was also guilty of corrupt practice of seeking assistance from the Police Officers, which was beyond the purview of what their

official duties entailed. Respondent Rakesh Singh accompanied by Shri Sharad Jain, Cabinet Minister in Government of M.P. and BJP M.L.A. from Bargi Assembly Constituency, Smt. Pratibha Singh, along with other supporters staged a protest at P.S.-Belkheda on 8.4.2014. During aforesaid protest, Additional S.P., Mahesh Jain was pressurized by respondent Rakesh Singh, Cabinet Minister Sharad Jain and M.L.A. Smt. Pratibha Singh to delete the name of accused Neeraj Singh from the FIR and also to lodge a counter FIR against the victims including the present petitioner. Under threat from the respondent, the Additional S.P., Mahesh Jain decided that name of Neeraj Singh will be deleted from the FIR and a counter FIR would be lodged against the victims. The respondent also made the Addl. S.P. to talk with Neeraj Singh on mobile phone and assure him that his name would be deleted from the FIR and a counter FIR would be lodged against the victims. The entire incident relating to the protest staged by the respondent and his supporters was video-graphed by one Ajeet Tiwari. On the next day, Ajeet Tiwari was called by Additional S.P., Mahesh Jain to his office. Additional S.P. insisted that Ajeet Tiwari handover the memory card; wherein, the incident was recorded, to the Additional S.P.. In spite of resistance by Ajeet Tiwari, memory card containing the video of the incident, which has taken place on 08.4.2014, was taken away by the Additional S.P. and was replaced by a blank memory card in the camera of Ajeet Tiwari. However, Ajeet Tiwari had prepared a compact disc of the incident before parting with the memory card but this fact was not within the knowledge of Additional S.P., Mahesh Jain. The petitioner has filed unedited compact disc prepared by Shri Ajeet Tiwari with the election petition and also gave transcript of aforesaid conversation in the petition. Thus, the respondent had sought illegal assistance from the police officers for furtherance of his

prospects in the election. As such, he had indulged in corrupt practice; therefore, it has been prayed that the election of the respondent Rakesh Singh from Parliamentary Constituency No.13, Jabalpur be declared void on the ground of aforesaid corrupt practices adopted by him.

4. In his reply, the respondent had objected to the admissibility of the compact disc filed along with the election petition purportedly containing the video of the incident involving Additional S.P., Mahesh Jain on the ground that the petitioner had not complied with the provisions of Section 65-B (4) of the Evidence Act, 1872. It has been specifically denied that the respondent and/or his election agent resorted to any corrupt practices in the election. It has been stated that the respondent was elected Member of Lok-Sabha from Parliamentary Constituency No.13, Jabalpur for the 3rd consecutive term by defeating his nearest rival Shri Vivek Tankha, the Congress candidate, by a huge margin. It has further been averred that the petitioner has not stated a single instance of non-compliance with the provisions of the Act of 1951 or the Conduct of Election Rules, 1961 or the orders made thereunder by the Election Commission. It was specifically denied that the respondent visited Village-Mankhedi on 03.04.2014 and met Smt. Pratibha Singh and her sons Neeraj Singh and Golu Singh or at any other place in Bargi Assembly Constituency. It was also specifically denied that he asked aforesaid persons to let loose their terror in Bargi Assembly Constituency in order to have a favourable result in the election. As per the schedule of the respondent, he was in Bhedaghat area, which was approximately 40-45 kms. away from Village-Mankhedi, on the relevant date. He never visited Mankhedi or any other village falling under the Bargi Assembly Constituency on 03.04.2014, 04.04.2014, 05.04.2014 or 06.04.2014. It has been specifically denied that

at the behest of the respondent, Golu Singh and Neeraj Singh and their associates roamed free with guns and other arms terrorizing the Congress workers in Village-Mankhedi. In fact, during election campaign, respondent had no business with Neeraj Singh and Golu Singh. They were neither instructed nor told by the respondent even to campaign for him or for his political party. It has further been specifically denied that the alleged incident of firing by Golu Singh and Neeraj Singh and their associates, which is said to have taken place at Mankhedi on 07.4.2014, was at the behest or instance of the respondent. It has also been denied that the respondent pressurized the District Administration and Police Authorities in any manner whatsoever, to remain inactive in respect of the alleged incident of firing. It has also been denied that respondent interfered with free and fair exercise of the constitutional right of the voters of Bargi and Jabalpur Assembly Constituencies, to vote. No such complaint was made by any voter, candidate or election agents to Election Commission, any authority or the police. It has also been denied that on 08.04.2014, respondent along with Shri Sharad Jain, Smt. Pratibha Singh and their supporters staged a protest at P.S.-Belkheda, where they pressurized the Additional S.P., Mahesh Jain to delete the name of Neeraj Singh from the FIR and register a counter FIR against alleged victims of the incident. It has also been denied that any compact discs of any such incident was prepared by one Ajeet Tiwari. The transcript of the conversation, which is alleged to have taken place between the respondent, Shri Sharad Jain and Smt. Pratibha Singh on one hand and Additional S.P., Mahesh Jain on the other, has been specifically denied. It has also been denied that for want of knowledge that the memory card containing the video of such incident was taken away from Shri Ajeet Tiwari by Additional S.P., Mahesh Jain; as such, the respondent never indulged in

any corrupt practices. The election petition is false and frivolous; therefore, it has been prayed that the petition be dismissed.

5. On the basis of pleadings of the parties and documents filed by them, following issues were framed. The conclusions of the Court are recorded against each of them.

Issues

Issues	Findings
(1) (a) Whether on 7-4-2014, at the behest, instigation and assurance of protection from the respondent, Golu Singh and Neeraj, sons of Bargi M.L.A. Pratibha Singh and others roamed around in Village-Mankhedi, Badcheri, Chargawan and Chatiaghat of the Constituency and opened fire on workers of Indian National Congress and grievously injured them, resulting in denial of constitutional right of voters of that party to vote freely and fairly?	Not proved.
(b) Whether the respondent, M.L.A. Sushree Pratibha Singh and Minister in the State Cabinet, Shri Sharad Jain had pressurized or illegally influenced Additional S.P., Shri Mahesh Chandra Jain to delete the name of aforesaid Neeraj and register counter F.I.R. against victims including the petitioner?	Not proved.
(c) Whether at the behest of the respondent, Shri Mahesh Chandra Jain had illegally obtained memory card containing video-recording of conversation between Shri Mahesh Chandra Jain, Shri Sharad Jain and the respondent from Shri Ajeet Tiwari?	Not proved.
(2) Whether all or any of the aforesaid acts and conducts on the part of the respondent or other persons with the consent of respondent, falls under the purview of corrupt practices?	Acts and conduct not proved.
(3) Relief and costs?	Petition dismissed with costs.

6. **Issue No.(1) (a)** - *Whether on 07-04-2014 at the behest, instigation and assurance of protection from the respondent, Golu Singh and Neeraj, sons of Bargi M.L.A., Pratibha Singh and other roamed around in Village-Mankhedi, Badcheri, Chargawan and Chatighat of the Constituency and opened fire on workers of Indian National Congress and grievously injured them, resulting in denial of constitutional right of voters of that party to vote freely and fairly?*

7. The burden of proving this issue was upon the petitioner.

Before adverting to evidence, adduced by the parties on this issue, it would be appropriate to refer to relevant part of Section 123 of the Act, which reads as hereunder:

Corrupt Practices

123. Corrupt practices.—The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act:—

*(1)******
*(A)******
*(a)******
*(b)******
*(i)******
*(ii)******
*(B)******
*(a)******
*(b)******

(2) Undue influence, that is to say, any direct or indirect interference or attempt to interfere on the part of the candidate or his agent, or of any other person with the consent of the candidate or his election agent, with the free exercise of any electoral right:

Provided that—

(a) without prejudice to the generality of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who—

(i) threatens any candidate or any elector, or any person in whom a candidate or an elector interested, with injury of any kind including social ostracism and ex-communication or expulsion from any caste or community; or

*(ii)******
*(b)******
*3A ******
*3B******
*(4)******
*(5)******
*(6)******

(7) The obtaining or procuring or abetting or attempting to obtain or procure by a candidate or his agent or, by any other person with the consent of a candidate or his election agent, any assistance (other than the giving of vote) for the furtherance of the prospects of that candidate's election, from any person in the service of the Government and belonging to any of the following classes, namely:—

*(a)******
*(b)******
*(c)******
(d) members of the police forces;
*(e) ******
*(f) ******
*(g)******
*(h)******
*(8) ******

8. The pleadings of the petitioner with regard to issue no.1 (a) is in two parts. In the first part, there is incident, which is alleged to have taken place at about 07:00 p.m. on 03.04.2014,

at Village-Mankhedi where the respondent is said to have asked Smt. Pratibha Singh and her sons Neeraj Singh and Golu Singh to let loose their reign of terror in Bargi Assembly Constituency and to use all means to that end including unfair means. We may note that there is only oral evidence of the petitioner's witnesses to support the aforesaid incident. Petitioner Abhay Singh has stated in this regard that at about 07:00 p.m. on 03.04.2014, he was at the bus-stand in Village-Mankhedi and were canvassing for the Indian National Congress. He was accompanied by other workers namely Durjan Patel, Rakesh Patel, Vimal Vishwakarma, Neelesh Patel and other persons. At that time, respondent Rakesh Singh reached the spot. He was accompanied by Smt. Pratibha Singh and her sons Golu Singh and Neeraj Singh. Other workers of their party namely Yashpal Singh, Ramgopal Choudhary and Pushpraj Singh etc. were also present with them. Neeraj Singh was the Chairman of Shahpura Mandi. At that place, respondent Rakesh Singh said that these Congress workers are canvassing. They must somehow be stopped, no matter how. He would manage whatever happens in future. Respondent Rakesh Singh told sons of Smt. Pratibha Singh that you let loose your terror. See that this election is not spoilt. These people must somehow be stopped. He would manage the police. Abhay Singh (PW-1) has further stated that they overlooked aforesaid extortation by the respondent. This dialogue was delivered in such a manner, so that Congress workers would hear that. The statement of Abhay Singh (PW-1) in this regard is corroborated by Durjan Patel (PW-2). He has stated that at aforesaid time, date and place and in the presence of aforesaid persons, respondent Rakesh Singh asked sons of Smt. Pratibha Singh as to what are they doing ? These Congress men are spoiling their game. Stop them at any cost? He will manage whatever happens. Stop them, no matter what

is required to be done, spend money, beat them up but stop them. Durjan Patel (PW-2) has also stated that respondent Rakesh Singh said that he would speak to the police, they are their people. After delivering aforesaid dialogue, the respondent went away.

9. Respondent Rakesh Singh (DW-1) has stated that all his public meetings were peaceful and no untoward situation arose in any of his public meetings and programmes. He cannot state anything with regard to any dialogue that is said to have taken place on 03.04.2014, without any context. He does not remember whether he had gone to Village-Mankhedi on 03.04.2014 or not. He was not acquainted with Neeraj Singh and Golu Singh since before the election. Petitioner Abhay Singh (PW-1) has further stated that for next 2-3 days, Golu and Neeraj Singh etc. roamed about in the villages armed with weapons. They used to terrorize the workers and used to stop the Congress workers from campaigning. They used to pressurize public so that the public would vote for BJP. They used to terrorize and intimidate the voters by saying that they have the government and they have the power. He complained about the matter to Town Inspector of P.S.-Belkheda. He assured that he would look into the matter but he did nothing. In this regard, Durjan Patel (PW-2) has stated that they had complained about the matter to Town Inspector of P.S.-Belkheda; however, he made light of the matter and said that this is nothing, this is election and such things do happen in elections.

10. Second part of the incident is alleged to have taken place on 07.04.2014. Petitioner Abhay Singh (PW-1) states in this regard that at about 01:00 p.m. on 07.04.2014, he was campaigning in Village-Baseri along with other party workers. At that time, Golu Singh and Neeraj Singh accompanied by other B.J.P. workers arrived. Golu Singh etc. blocked their

vehicles; whereon, he informed the Congress candidate Shri Vivek Tankha, who assured him that he will speak to S.P.. Shri Tankha asked his workers to wait. About 20-25 minutes later, Belkheda police reached the spot. The police separated the vehicles of Golu Singh and Neeraj Singh etc. from those of Congress workers. Thereafter, the Congress workers left the spot and reached Mankhedi via Sunderdehi. Durjan Patel (PW-2) has stated in this regard that at aforesaid time, date and place, they were sitting in the house of former Sarpanch. They were told by people that Golu Singh and Neeraj Singh and others have blocked their vehicles in such a manner that there was no way left. Abhay Singh informed regarding the matter to Shri Vivek Tankha, who assured that he would speak to S.P. About half an hour later, Belkheda police reached the spot and separated the vehicles of two sides.

11. Abhay Singh (PW-1) submits that at about 03:30 p.m., the same day, he was with Durjan Patel, Rakesh Patel, Neelesh Patel, Vinod Nayak and other persons. No sooner they got down from their vehicles, Golu Singh, Neeraj Singh and Pushpraj Singh came from behind armed with guns. They were accompanied by Yashpal Choudhary and Ramgopal Choudhary. Golu Singh fired from behind. Only one gun shot was fired, which contained pellets. He, Durjan Patel, Rakesh Patel, Dhansingh, and Neelesh Patel received pellet injuries. The situation turned chaotic. Aforesaid part of the statements of Abhay Singh (PW-1) has been corroborated by Durjan Patel (PW-2). He has further stated that he was hit by 9 pellets. Rakesh Singh was hit by 12 pellets and Abhay Singh was hit by 2 pellets. In addition thereto, Neelesh and Dhansingh also sustained pellet injuries. He had sustained pellet injuries to his mouth. As a result, his clothes were stained with blood. Golu Singh had fired upon them due to electoral enmity. They did not want that anyone should campaign for Congress in that

area. In this regard Sarvesh Singh (PW-3) has stated that a about 2-3 p.m. on 7.4.2014 he was at Mankhedi. At that time Golu Singh and Niraj Singh, sons of MLA Pratibha Singh had fired upon Congress men including Abhay Singh. Thereafter they had taken Abhay Singh to Medical College.

12. Abhay Singh (PW-1) and Durjan Patel (PW-2) have further stated that they were taken by their companions to Medical College, Jabalpur where they were admitted. The police had reached the Medical College, Jabalpur. He had lodged FIR (Ex.P/3). (The original FIR has been placed on the record of S.T. No.600/2014 pending in the Court of V ASJ, Jabalpur). Durjan Patel (PW-2) has further stated that the effect of aforesaid incident was that all voters were terrified and respondent Rakesh Singh won the election

13. Now, the question that arises for consideration is, how much credence should be attached to the statements of petitioner Abhay Singh (PW-1) and Durjan Patel (PW-2) and Sarvesh Singh (PW-). In this regard, learned counsel for the petitioner submits that there is no rule of law or prudence that oral evidence has to be discarded in all cases involving corrupt practices in election matters. To buttress aforesaid contention he has invited attention of the Court to the judgment rendered by the Supreme Court in the case of **Pratap Singh Vs. Rajinder Singh and anr.** AIR 1975 SC 1045; wherein, it has been held that:

10. The fifth ground of objection set out above seems to proceed on the erroneous assumption that oral testimony cannot be accepted when a corrupt practice is set up to assail an election unless it is corroborated by other kinds of evidence in material particulars. We are not aware of any such general inflexible rule of law or practice which could justify a wholesale condemnation or rejection of a species of evidence which is legally admissible and can be acted upon under the provisions of Evidence Act in every type of case if it is, after proper scrutiny, found to be reliable or worthy of acceptance. There is no presumption, either in this country or anywhere else, that a witness, deposing on oath in the witness box, is untruthful unless he is shown to be, indubitably, speaking the truth. On the other hand, the ordinary presumption is that a witness deposing solemnly on oath before a judicial tribunal is a witness of truth unless the contrary is shown.

11. It is not required by our law of evidence that a witness must be proved to be a perjurer before his evidence is discarded. It may be enough if his evidence appears to be

quite improbable or to spring from such tainted or biased or dubious a source as to be unsafe to be acted upon without corroboration from evidence other than that of the witness himself. The evidence of every witness in an election case cannot be dubbed as intrinsically suspect or defective. It cannot be equated with that of an accomplice in a criminal case whose testimony has. according to a rule of practice though not of law to be corroborated in material particulars before it is relied upon.

14. Per contra, learned senior counsel for the respondent has placed reliance upon the judgment rendered by the Supreme Court in the cases of **M.J.Zakharia Sait Vs. T.M. Mohammed** (1990) 3 SCC 396, **Thakur Sen Negi Vs. Dev Raj Negi,** 1993 (suppl.) 3 SCC 645 and **Narender Singh Vs. Mala Ram** (1999) 8 SCC 198. Learned senior counsel for the respondent has contended that the Supreme Court has repeatedly cautioned against acceptance of uncorroborated oral evidence in election matters, especially those involving corrupt practices. In the case of M.J.Zakharia Sait (supra), the Supreme Court has held as follows:

***70. Time and again, the courts have uttered a warning against the acceptance of a non-corroborated oral testimony in an election matter** because it Is not only difficult to get a non-partisan witness but is also easy to procure partisan witnesses in such disputes. The courts have, therefore, insisted upon some contemporaneous documentary evidence to corroborate the oral testimony when in particular such evidence could have been maintained. The dangers of accepting only the oral testimony are illustrated by this witness.*

15. It has been held by the Supreme Court in the case of Thakur Sen Negi (supra) that:

How an election court should evaluate the evidence in such a situation has been stated time and again by this Court. It would be sufficient if we extract a passage from this Court's decision in Rahim Khan v. Khurshid Ahmed which reads thus;

*"**We must emphasize the danger of believing at its face value oral evidence in an election case without the backing of sure circumstances or indubitable documents.** It must be remembered that corrupt practices may perhaps be proved by hiring half-a-dozen witnesses apparently respectable and disinterested, to speak to short and simple episodes such as that a small village meeting took place where the candidate accused his rival of personal vices. There is no X-ray whereby the dishonesty of the story can be established and, if the court were gullible enough to gulp such oral versions and invalidate elections, a new menace to our electoral system would have been invented through the judicial apparatus. We regard it as extremely unsafe, in the present climate of Kilkenny-cat election competitions and partisan witnesses wearing robes of veracity, to upturn a hard won electoral victory merely because lip service to a corrupt practice has been rendered by some sanctimonious witnesses. The court must look for serious assurance,*

un-lying circumstances or unimpeachable documents to uphold grave charges of corrupt practices which might not merely cancel the election result, but extinguish many a man's public life."

4. Since allegations in regard to corrupt practice are quasi-criminal in nature and entail the penalty of disqualification, the court would be justified in looking for strong and dependable evidence and its refusal to base its decision on oral evidence alone would not be unjustified if the said evidence is not supported by strong, reliable and trustworthy corroboration.

16. Likewise, in the case of Narender Singh (supra), the Supreme Court has held as follows:

15. In the matter of appreciation of evidence in election disputes certain principles have been stated by this Court. The general principle is that the onus to prove the essential facts which constitute the cause of action in an election petition is upon the person making it, namely, the election petitioner. What evidence would be sufficient to prove a particular fact depends upon the circumstances of each case. When the evidence adduced is capable of drawing an inference either way, the view that is favourable to the returned candidate will have to be preferred. In Ram Singh v. Col. Ram Singh[1] the principle set out by this Court, by majority, is as follows: (SCC p. 616, para 3)

"[I]n borderline cases the courts have to undertake the onerous task of, 'disengaging the truth from falsehood, to separate the chaff from the grain'. In our opinion, all said and done, if two views are reasonably possible — one in favour of the elected candidate and the other against him — courts should not interfere with the expensive electoral process and instead of setting at naught the election of the winning candidate should uphold his election giving him the benefit of doubt. This is more so where allegations of fraud or undue influence are made."

16. In election disputes emotions of the public are raised and opinions are sharply divided between groups. In such circumstances oral testimony in favour of one or the other party is easy to be adduced but the same will have to be critically examined and, therefore, oral evidence is to be assessed with a great deal of care.

17. From aforesaid pronouncements following legal position may be culled out. There is no general inflexible rule of law or practice which permits wholesale rejection of oral evidence which is otherwise legally admissible under the provisions of the Evidence Act. However, as a matter of caution, the Court should look for contemporaneous documentary evidence or sure circumstances to lend assurance to its findings. Such oral evidence must be closely scrutinized to see whether it springs from partisan sources? Such testimony has to be scrutinized with utmost care and caution.

18. Learned counsel for the petitioner has also submitted in

this regard that the respondent has not specifically denied the incident that is said to have taken place at about 7:00 p.m. on 3.04.2014; wherein, he is said to have exhorted Golu Singh and Neeraj Singh and their cohorts to let loose their reign of terror in Bargi Assembly Constituency. He submits that all that respondent has stated in rebuttal is that he does not remember whether he had gone to Mankhedi on 03.04.2014. He has also meekly stated that without any context, he cannot tell about any conversation involving him at Mankhedi on 03.04.2014; therefore, it has been prayed that the oral testimony of witnesses Abhay Singh (PW-1) and Durjan Patel (PW-2) should be accepted. In support of this contention, learned counsel for the petitioner has placed reliance upon the judgment rendered by the Supreme Court in the cases of **Kalamata Mohan Rao v. Narayana Rao Dharmana and others, AIR 1996 SC 535**; wherein it has been observed that :

Moreover, there is no evidence in rebuttal thereof, inasmuch as even the appellant did not enter the witness box to deny the allegations made against him. The unrebutted evidence led in support of the election petition is sufficient to prove that the act of putting up these posters at different places in the constituency as alleged has been duly proved.

19. He has also invited attention of the Court to the judgment rendered by this High Court in the case of **M.P. Badalkar vs. Smt. Shamta Sarojini Badalkar and another, AIR 1988 MP 319**. Paragraph No.4 of the judgment reads as hereunder:

4. After having heard the learned counsel for the petitioner and on examination of the record, we are satisfied that the decree nisi for dissolution of marriage has been rightly passed by the trial Court. There is no reason why the statements of the petitioner and his son should not be accepted. The evidence so recorded on behalf of the petitioner has gone unrebutted and there is no evidence to the contrary. We are also satisfied that there is no collusion between the parties. As has been held in Lalit v. Lavina, AIR 1979 Madh Pra 70 (FB) the only requirement to prove the case by the petitioner is by preponderance of probabilities and the degree of probability depends on the gravity of the offence. We are satisfied that the petitioner has been able to prove his case.

20. In this regard, learned counsel for the respondent

submits that the alleged exhortation by the respondent at Mankhedi on 03.04.2014, has been specifically denied in the written statement of the respondent. He further contends that the Supreme Court in the cases of **F.A. Sapa vs Singora and others, AIR 1991 SC 1557, Pratap Singh (supra)** and a catena of other has held that allegation of corrupt practice being quasi-criminal in nature, has to be proved beyond reasonable doubt and not merely by a preponderance of probabilities. Inviting attention of the Court to the judgment rendered by the Supreme Court in the cases of **Ram Singh Vs. Col. Ram Singh 1985 Supp. SCC 611 and Narendra Singh (supra)**, it has been contended by learned counsel for the respondent that when evidence adduced is capable of drawing an inference either-way, the view that is favourable to the returned candidate, will have to be preferred.

21. When we examine the evidence available on record in respect of Issue No.1(a), we find that there is no documentary evidence to support the incident that is said to have taken place on 03.04.2014 at village Mankhedi. Only testimony of petitioner's witnesses Abhay Singh (PW-1) and Durjan Patel (PW-2) is available. Abhay Singh is petitioner himself. He has admitted in paragraph no.2 of the deposition that he is a worker of the Congress Party and on 03.04.2014 he was campaigning for Indian National Congress at Mankhedi bus stand on the directions of the Congress candidate, with others. Durjan Patel (PW-2) has stated that he is acquainted with petitioner Abhay Singh because he is social and political worker of Congress Party. He has also admitted in paragraph no.7 that he was also a Congress worker. Thus, both of these witnesses, who are said to have witnessed the incident involving exhortation by respondent, spring from the partisan, if not tainted source. Abhay Singh (PW-1) admits in paragraph no. 11 that he did not lodge a written report of the incident

dated 3.4.2014. either with Congress candidate or Election Authorities or to the police. It is very easy to procure oral evidence of such witnesses to allege a corrupt practice. Moreover, it appears highly improbable that in this age of easily available video-recording equipment like mobile phones, an experienced campaigner like the respondent, who had already won two Lok Sabha Elections, would openly indulge in such talk so as to create evidence against himself and provide a ready-made tool to his adversaries to assail him. It may be also be noted that no written report of any such incident made to any of the authorities has been proved by the petitioner. In these circumstances, oral testimony of petitioner's witnesses Abhay Singh (PW-1) and Durjan Patel (PW-2) is not worthy of credence. Thus, the petitioner has failed to prove that the respondent had exhorted Golu Singh and Neeraj Singh and their supporters to terrorize the Congress workers and voters of Bargi Assembly Constituency to vote for Bharatiya Janta Party candidate.

22. The second part relates to firing of a gun-shot by Golu Singh upon Congress workers Abhay Singh, Durjan Patel etc. In aforesaid incident, apart from petitioner Abhay Singh, Congress workers Durjan Patel, Rakesh Patel, Dhan Singh and Neelesh Patel were said to have sustained pellet injuries. The injured were taken to Medical College and first information report (Ex.P/3) was lodged by petitioner Abhay Singh, which was registered in respect of aforesaid incident. A Sessions Trial arising from the incident being S.T. No.600/2014, is pending in the Court of V Additional Sessions Judge, Jabalpur. However, Durjan Patel (PW-2) has admitted in his cross-examination that there is a counter-case also pending in the matter in which one Tehsildar Singh is said to have suffered bullet injury. He is also an accused in aforesaid case and has been released on bail. Thus, from the evidence available on

record, it is clear that an incident involving firing had taken place on 07.04.2014 in village Mankhedi. In respect of aforesaid incident, two counter cases are pending before the Court of Session lodged by rival parties. However, respondent Rakesh Singh was not said to have been present on the spot; therefore, this by itself, is not sufficient to establish complicity of the respondent in the incident of firing. The respondent is sought to be implicated in the aforesaid incident on the basis of undue influence he is said to have exercised along with Shri Sharad Jain, Cabinet Minister and Sushri Pratibha Singh, Bargi MLA upon Additional SP Shri Mahesh Chandra Jain. Therefore, this incident would be considered along with Issue No.1(b).

23. Issue No.1(b)

Whether the respondent, M.L.A. Sushri Pratibha Singh and Minister in the State Cabinet Shri Sharad Jain had pressurized or illegally influenced Addl. S.P. Shri Mahesh Chandra Jain to delete the name of aforesaid Neeraj and register counter F.I.R. against victims including the petitioner ?

The burden of proving this issue was also upon the petitioner. In this regard, Sarvesh Singh Thakur (PW-3) has submitted that he is a student. On 08.04.2014, police station at Belkheda was gheraoed (surrounded) by the supporters of Bhartiya Janta Party. Ajeet Tiwari (PW-5) submitted that he is an independent videographer. He learnt at about 3:00 p.m. on 07.04.2014 that P.S. Belkheda is proposed to be gheraoed; therefore, he reached the spot. Both of aforesaid witnesses have stated that respondent Rakesh Singh, Minister Sharad Jain and MLA Sushri Pratibha Singh were present and participated in aforesaid gherao. Sarvesh Singh Thakur (PW-3) has stated that at that time respondent Rakesh Singh was asking Minister Sharad Jain as to what kind of policemen were these? They had registered cases against their own people.

Rakesh Singh had asked Sharad Jain to tell the policemen to remove certain sections from the case. About an hour later, one Superintendent of Police Jain arrived. He heard Minister Sharad Jain telling Superintendent of Police Shri Jain to remove the names of Golu Singh and Neeraj Singh; whereon, Minister Sharad Jain asked Superintendent of Police Shri Jain to assure Golu Singh that he would delete sections. The Minister also asked Shri Jain to register a case against the Congressmen. Ajeet Tiwari (PW-5) has stated in this regard that respondent Rakesh Singh had asked Minister Sharad Jain to tell Additional SP to hush up, whatever the matter was (Mamle jo bhi ho, rafa-dafa karo). Respondent Rakesh Singh called Neeraj Singh on phone. Thereafter, respondent Rakesh Singh told Additional SP that Neeraj Singh is afraid. After that respondent Rakesh Singh handed over mobile phone to the Additional SP, who spoke on phone and said that whatever be the case, the staff would manage. The matter would be hushed up. Pratibha Singh asked Additional SP to register a case against petitioner Abhay Singh of the other party as well. Ajeet Tiwari (PW-5) has further stated that he was equipped with a video camera and had recorded the entire incident that had taken place at 3:00 p.m. on 08.04.2014. After returning from the police station, he prepared a compact disc of the recording. Thereafter, at about 8:00 or 9:00 p.m. on 08.04.2014, he received a phone call from petitioner Abhay Singh asking about the CD. Abhay Singh told Ajeet Tiwari that he wanted to see the CD. Thereafter, he went to Abhay Singh with the CD and gave it to him.

24. Respondent Abhay Singh has denied that he ever pressurized the police to delete the names of Golu and Neeraj from the first information report. He has also denied the fact that election results were materially altered because he had pressurized the police authorities.

25. At the outset, it may be noted that the compact disc allegedly prepared by Ajeet Tiwari (PW-5) recording the incident that had taken place at P.S. Belkheda on 08.04.2014, was not admitted in evidence because it did not comply with the provisions of Section 65-B (4) of the Evidence Act; therefore, only oral evidence with regard to aforesaid incident is available. It consists of the statements of aforesaid two witnesses namely Sarvesh Singh (PW-3) and Ajeet Tiwari (PW-5). As has been observed in preceding paragraphs, the testimony of aforesaid two witnesses is required to be meticulously scrutinized before placing reliance thereon. Both of the witnesses claimed that they were present on the spot and heard the conversation between respondent Rakesh Singh, Cabinet Minister Sharad Jain and Bargi MLA Pratibha Singh on onc hand and Additional SP Mahesh Chandra Jain on the other. A comparative reading of the deposition of aforesaid two witnesses reveals that their statements with regard to the actual conversation that had taken place differ materially. They are said to have heard the conversation clearly in spite of presence of 400-500 people, who were shouting slogans on the spot. As per Sarvesh Singh (PW-3) the conversation related to lament by respondent Rakesh Singh that policemen had registered cases against thcir own people; therefore, at least some sections should be delcted; whereas, Ajeet Tiwari (PW-5) has stated that the respondent had asked the Additional SP to assure Neeraj Singh that the matter would be sorted out. Though, both have claimed that Additional SP was pressurized to register casc against petitioner Abhay Singh as well but Sarvesh Singh has maintained that this pressure was exerted by Minister Sharad Jain whereas Ajeet Tiwari has stated that this pressure was exerted by MLA Pratibha Singh. Pleadings of the petitioner in this regard tell a different story. In paragraph no.13 the transcript of conversation between aforesaid persons

at village Belkheda has been reproduced which reads as hereunder:

राकेश सिंह : वारंट कटवा दिया।

अति एस पी : नही पता कोर्ट मे गया था उसमे नीरज का नाम नही है। उसको रोका गया मेरे फोन पर ये मैने नाम चूंकि लिखा गया है FIR में वैसे किसी का भी लिखा सकते है मगर वो आदमी without doubt घटनास्थल पर नही था। हमारा T.I. उस बात का गवाह है।

शरद जैन : तो उन दोनो बात से आप सहमत है। एक तो जे कि FIR हो रही है।

अति एस पी : बिल्कुल हो रही है।

शरद जैन : और दूसरी कि नीरज का नाम नही है।

राकेश सिंह : हो गई है आप बता रहे है।

अति एस पी : हो गई है। अब तो Zero पर आयेगी यहां पर।

शरद जैन : नीरज का नाम नही हैं

अति एस पी : नीरज का नाम उन्होने लिखाया लेकिन नीरज का इस घटना मे शामिल होना हमारी

राकेश सिंह : उन्होने लिखाया है।

अति एस पी : F.I.R. में लिखाया है। लेकिन नीरज का शामिल होना जो प्रारम्भिक रूप से चूंकि हमारा थाना प्रभारी वहां मौजूद था।

शरद जैन : आप जो प्रकरण बना रहे है उसमे नीरज मुजरिम नही है

अति एस पी : नही

शरद जैन : खत्म बात

राकेश सिंह मोबाईल पर नीरज सिंह से बात नीरज ये Add. S.P. आ गये है। इन्होंने नाम तुम्हारा लिखाया है लेकिन यह कह रहे है कि जिम्मेदारीपूर्वक मै इस बात कि नीरज नाम लिखाया नही है। लेकिन F.I.R. है मुकदमा नही मामला दूसरा वो वाली F.I.R. हो गई है कायमी हो गई है वहां से यहां आयेगी वहां कापी मिल जायेगा की F.I.R. एक मिनट जरा समझा लो इनसे।

अति एस पी : हां पार्टनर। यहां जैसे आयेगी यहां थाने का

नम्बर चढ़ाया नम्बर चढने के बाद उसकी कापी सुबह मिल जायेगी जरूरत पढेगी तो हमारा staff बयान देगा कि तुम यहां पर नही हो।"

26. It has been alleged in the pleadings that Additional SP has said that though Neeraj Singh has been implicated in the case, the Town Inspector was present on the spot and he has asserted that Neeraj Singh was not present; therefore, they would not register a case against Neeraj Singh. Thereafter, at the instance of Rakesh Singh, Additional SP spoke on mobile phone with Neeraj Singh and assured him that policemen would depose that Neeraj Singh was not present on the spot. In aforesaid transcript, there is nothing which suggests that either of three persons namely Rakesh Singh, Sharad Jain and Pratibha Singh pressurized the Additional SP to also register counter-case against Congressmen.

27. In aforesaid circumstances, it is obvious that the statement of neither Ajeet Tiwari (PW-5) nor the statement of Sarvesh Singh (PW-3) are reliable. Even if it is assumed for the sake of arguments that the conversation as alleged in paragraph no.13 of the pleadings took place, it is clear that no undue pressure was exerted upon the Additional SP. He merely apprised the respondent regarding the factual situation as seen on the spot by the Town Inspector. He also reassured a person on mobile phone, who he thought to be innocent, at the instance of the respondent. Thus, the incident that is said to have taken place at P.S. Belkheda at 3:00 p.m. on 08.04.2014 has also not been proved beyond reasonable doubt, in the manner alleged in the pleadings of the petitioner.

28. Issue No.1(c)

Whether at the behest of the respondent, Shri Mahesh Chandra Jain had illegally obtained memory card containing video-recording of conversation between Shri Mahesh Chandra Jain, Shri Sharad Jain and the respondent, from Shri Ajeet Tiwari ?

The burden of proving this issue was also on the petitioner. The only witness that has been produced in this regard is videographer Ajeet Tiwari (PW-5). He stated that on 09.04.2015, a police constable came to him and told him that Additional SP has called him; whereon, he went to Additional SP with his camera. The Additional SP asked him whether he had videographed the incident of gherao of police station on eighth? He replied in affirmative. The Additional SP again asked whether he had videographed the incident by the same camera? He again replied in affirmative. Thereafter, the Additional SP took the camera from him and took out the memory card which contained video recording of the incident and replaced it with a new one. Thereafter, he returned.

29. Now the question that arises for consideration is whether oral statement of Ajeet Tiwari (PW-5) is reliable ?

30. It may be noted that he is a professional independent videographer who did video recording for Congress candidate Shri Tankha as well as BJP candidate respondent Rakesh Singh, yet he allowed the Additional SP to remove such important memory card from the camera without any protest or resistance. He neither reported the incident to police nor to the Election Commission. He did not complain to media either. He did not give the CD of the incident he had prepared to anyone other than the present petitioner. Therefore, his statement cannot be relied upon. Even if it is assumed for the sake of arguments that Additional SP Mahesh Jain had indeed replaced memory card in aforesaid manner, there is nothing on record to indicate that he did so at the instance of, at the behest of or with the consent of respondent Rakesh Singh or his election agent. It is quite probable that he did so in order to protect himself against any legal action or departmental proceedings. At any rate, complicity of respondent Rakesh Singh in the alleged incident relating to replacement of memory card, has

also not been established beyond reasonable doubt. Thus, the petitioner has also failed to prove Issue No.1(b)(c).

31. Issue No.2

Whether all or any of aforesaid acts and conduct on the part of the respondent or other persons with the consent of respondent, falls under the purview of corrupt practices ?

Since, this issue has been considered along with Issue Nos.1(a)(b)(c), no separate discussion on this issue is necessary.

32. As such, the petitioner has failed to prove any of the issues involved in this election petitioner; therefore, this election petition deserves to be dismissed.

33. *Relief and costs*

(1) Consequently, this election petition preferred by Elector Abhay Singh challenging election of returned candidate respondent Rakesh Singh as a member of Parliament from Parliamentary Constituency No.13-Jabalpur is hereby **dismissed.**

(2) The Election petitioner shall bear his own costs and that of the respondent of this election petition.

(3) The petitioner's fee shall be payable as per Schedule, if precertified.

The office is directed to transmit a certified copy of this judgment to the Election Commission and Speaker of Lok Sabha forthwith, as per Section 103 of the Act.

Sd/-

(C.V. Sirpurkar)
Judge

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 2018

फा. क्र. ई.पी.-04-2014-चार-190.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-MP-LA-(04/2014) 2018 (डा. विवेक तिवारी विरुद्ध श्री दिव्यराज सिंह एवं अन्य) दिनांक 10 सितम्बर 2018 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

राकेश कुशरे, उपसचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर, 2018—19 भाद्रपद, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं0 82/म.प्र.–वि.स./(34/2014)/2018 :– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, डा0 विवेक तिवारी द्वारा दायर निर्वाचन याचिका 2014 की संख्या 04 (डा0 विवेक तिवारी विरूद्ध श्री दिव्यराज सिंह एवं अन्य) में मध्य प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ के दिनांक 12.07.2018 के निर्णय/आदेश को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है ।

आदेश से,
हस्ता./-
(अनुज जयपुरियार)
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 10th September, 2018—19 Bhadrapada, 1940 (Saka)

NOTIFICATION

No. 82/MP-LA/(04/2014)/2018 :- In pursuance of Section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the judgment/order dated 12.07.2018 of the Jabalpur Bench of Honb'le High Court of Madhya Pradesh in Election Petition No. 04 of 2014 (Dr. Vivek Tiwari Vs. Divyaraj Singh & Ors.) filed by Dr. Vivek Tiwari.

By order,

Sd./-
(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary
Election Commission of India.

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH

PRINCIPAL SEAT AT JABALPUR.

ELECTION PETITION NO. 4 /2014

PETITIONER : Dr. Vivek Tiwari
S/o Late Arun Kumar Tiwari,
Aged about 40 years,
R/o. Amahiya Mohalla,
Rewa, M.P.

Versus

RESPONDENTS :

1. Divyaraj Singh,
S/o Shri Pushpraj Singh,
Aged about 27 years,
R/o Fort Rewa, District Rewa

2. Election Commission of India,
Nirwachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001
Through the Secretary

3. The State Election Commission
through its Secretary, Madhya
Pradesh Nirvachan Sadan, 17 Arera
Hills, Bhopal, M.P.

4. Smt. Vimlesh Singh,
SDM/SDO, Sirmour,
Returning Officer of
68, Sirmour Vidhan Sabha
State of M.P.,

Presented by Shri Dr. Vivek Tiwari, Petitioner who is identified by Shri Sanjay Dubey Adv. at 3.45PM on 20-1-14. It is properly drawn up; apparently within time and properly stamped. It is accompanied by requisite number of spare copies/list of addresses; PF & documents & security deposit of Rs 2000/-

Registrar (J) High Court of Madhya Pradesh JABALPUR (M.P.) 20 JAN 2014

Election Petition under Sections 80, 80-A, 81 and Section 100, 101 (d) (iv) of the Representation of People Act, 1951.

The petitioner seeks to call in question the election of the respondent no.1 as a member of the M.P. State Legislative Assembly from 68, Sirmour Vidhan Sabha Constituency, District M.P. inter-alia on the following facts:-

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

ELECTION PETITION NO. 4/2014

Dr. Vivek Tiwari

Vs.

Divyaraj Singh & Ors.,

Present: **Hon'ble Mr. Justice Atul Sreedharan**

Mr. R.P Agarwal Sr. Advocate with Mr. Anuj Agarwal Ld. Counsel for the Petitioner.

Mr. Sanjay K. Agarwal Ld. Counsel for the Respondent No. 1.

ORDER
12/07/2018

The election petition under judgement has been filed by the Petitioner Dr. Vivek Tiwari against the Respondent Mr. Divyaraj Singh and three others. The contesting Respondent is the Respondent No.1 Mr. Divyaraj Singh. The Respondent No.2 is the Election Commission of India, Respondent No.3 is the State Election Commission and the Respondent No. 4 is the Returning Officer of Constituency No. 68, Sirmour. I.A No. 49/2016 was moved by the Respondent No.2, 3 and 4 for striking off their names from the array of Respondents. This Court by its order dated 18/02/12, allowed I.A No. 49/2016 and the names of the Respondent Nos. 2, 3 and 4 were stuck off from the array of Respondents. Thus, the Respondent No.1 is the sole

Respondent in this case. The Respondent No.1 is the returned candidate having being declared elected from the 68, Sirmour Vidhan Sabha Constituency, District Rewa of the State of Madhya Pradesh (hereinafter referred to as "Constituency 68"). The Respondent No.1 secured 40, 018 (forty thousand and eighteen) votes, defeating his nearest rival candidate, i.e., the Petitioner, by a margin of 5288 (five thousand two hundred and eighty-eight) votes. The Petitioner had secured 34, 730 (thirty four thousand seven hundred and thirty) votes. The Petitioner was the candidate of the political party the Indian National Congress and the Respondent No.1 was a candidate from the political party the Bhartiya Janata Party. The Petitioner is a voter of village Tiwni in 73 Mangawan constituency and his name is registered against serial no.85. The Governor of Madhya Pradesh by a notification published in the official gazette of the State on 1st November 2013 under Sub-section (2) of section 15 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as "the Act"). By the said notification elections were to be held to all Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh for the election of members of the legislative assembly for the State of Madhya Pradesh. 8.11.2013 was set as a last date for filing nomination set by the Election Commission of India. 9.11.2013 was the last date for the

scrutiny of the nomination, 11.112013 was the last date for the withdrawal of the candidature. 25.11.2013 was the date fixed for filing and 11.12.2013 was the date by which the elections shall be completed.

2. The election of the Respondent No.1 as the successful candidate has been challenged under section 100 (1) (d) (iv) of the Representation of Peoples Act, 1950 (hereinafter referred to as the "Act") which reads as hereunder;

> **100. Grounds for declaring election to be void.**- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), if [the High Court] is of opinion-
> **(a)** .....
> **(b)** .....
> **(c)** .....
> **(d)** that the result of the election, insofar as it concerns a returned candidate, has been materially affected –
> **(i)** .....
> **(ii)** .....
> **(iii)** .....
> **(iv)** by any non-compliance with the provisions of the Constitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act.
> [the High Court] shall declare the election of the returned candidate to be void.]

3. The crux of the Petitioner's case is centred around Rule 49-S and 49-T of the Conduct of Election Rules, 1961 (hereinafter referred to as the "Rules of 1961"). Rule 49-S of the Rules of 1961, reads as under;

> **49-S. Account of votes recorded.**- (1) The presiding officer shall at the close of the poll prepare an account of votes recorded in Form 17C and enclose it in a separate cover with the words "Account of Votes Recorded" superscribed thereon.

(2) The presiding officer shall furnish to every polling agent present at the close of the poll a true copy of the entries made in Form 17-C after obtaining a receipt from the said polling agent therefor and shall attest it as a true copy.

4. In paragraph 10 of the petition, the Petitioner states that the Returning Officer (hereinafter referred to as the "RO"), who is the Respondent No.4 to this petition, issued a document on 06/11/13 titled *"Assembly wise CU and BU list with the polling stations after RO level randomisation at District Rewa"*. The Petitioner has filed the copy of the list dated 06/11/13 in respect of Constituency 68 as Annexure P/6 to the petition. In paragraph 11 of the petition, the Petitioner has elaborated that the acronyms CU and BU mean "Control Unit" and "Balloting Unit" respectively. The CU remains with the Presiding Officer of the polling booth. It used for monitoring and regulating the casting of vote through the BU. In the same paragraph, the Petitioner explains that one BU can be used for up to sixteen candidates and if there are more than sixteens candidates in the fray per constituency, then each polling booth would require more than one BU. It is further stated by the Petitioner that as there were twenty seven candidates contesting from Constituency 68, two BU's were used for polling.

5. In paragraph 12 of the petition, the Petitioner has averred that he had made a complaint in writing to the Chief State

Election Officer, Rewa on 05/12/13 that the signature of the Petitioner's polling agent was not taken in statement of the Account of Vote Recorded in Form 17-C as mandated under rule 49-S of the Rules of 1961. Secondly, it was also averred that the information regarding the votes polled in the prescribed format in Form 17-C was not furnished and instead some information was supplied in scraps of plain paper, which according to the Petitioner was totally incomplete and of doubtful authenticity. The objection dated 05/12/13 is annexed to the petition as Annexure P/7 and a copy of that is stated to have been faxed to the Chief Election Commissioner. The Petitioner states that he did not receive any reply to the complaint dated 05/12/13 from either the State Election Commissioner o the Election Commission of India. Subsequently, the record of the election was summoned by this Court and it was submitted by the Returning Officer. The Form 17-C's, which were a part of that record was admittedly filled in properly. This the Ld. Counsel for the Petitioner alleges has been filled up after the elections in order to cover up their mistake. This position is apparent from paragraph 12 of the order of this Court dated 13/03/16 passed by disposing off I.A No. 13223/15.

6. In paragraph 14 of the petition, the Petitioner has alleged that the CU's and the BU's which were sent to nineteen

polling booths did not match or correspond with the details of the CU's and the BU's given in the document dated 06/11/13 (Annexure P/6) issued by the Election Commission. These nineteen booths were booth Nos. 3, 5, 15, 20, 21, 26, 38, 46, 54, 65, 91, 100, 107, 117, 134, 139, 146, 154 and 161. The Petitioner has elaborated the alleged discrepancy in relation to each of the booths mentioned above and has alleged that the effect of using of CU's and BU's different from those notified in Annexure P/6 had led to false and fabricated voting at the instance of the Respondent No.1 and that there remained no checks and balances in place to ascertain that the correct CU and BU were actually used as set put in Annexure P/6. However, as per the pleadings in the EP, the discrepancy does not relate to the non-compliance of either Rule 49S or 49T of the Rules of 1961. It is also relevant to state here that no separate issue has been drawn up by this Court to require a finding whether discrepancies mentioned in paragraph 14 of the EP, had any role in materially affecting the outcome of the election in favour of the Respondent No.1.

7. In paragraph 16 of the petition, the Petitioner has alleged that information in respect of twelve polling booths which was required to be furnished in Form 17-C as provided under Rule 49-S of the Rules of 1961, was not so provided

and instead, information was given on blank papers which were incomplete in many respects resulting in non-compliance of rule 49-S of the Rules of 1961. These twelve polling booths were 13, 17, 62, 67, 108, 109, 116, 133, 153, 158, 165 and 169. According to the Petitioner, the only information with regard to these polling booths were provided on plain paper which gave details only of the total number of voters, the total number of votes polled and the distribution of votes polled between males and females individually. The Petitioner has lamented that apart from this, other information as mandatorily required under Form 17-C was not provided. Information with regard to the polling in the abovesaid booths, supplied to the Petitioner, did not contain information as against items at serial no. 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 of Form 17-C. Thus, according to the Petitioner, the authenticity, integrity and credibility of the information given to the Petitioner through his agent, was highly suspect. Similar allegations were levelled with regard to seven other polling booths bearing Nos. 44, 64, 78, 90, 98, 117 and 143, that the only information provided was the total number of voters, the total number of votes polled, the individual breakup of the number of male and female voters and the numbers of the BU's and the CU's. Identical is the situation with regard to polling booths Nos. 36, 38, 58, 61, 88, 111, 119, 123, 124,

127, 129, 136, 139, 156 and 174. The Petitioner's concern is that it cannot be ascertained as to which machines were used and what seals were used for securing the machines after the polling, Under the circumstances, according to the Petitioner, the results received from the polling booths mentioned above were amenable to manipulation, which according to the Petitioner has been done, thus affecting the result of the returned candidate.

8. In paragraph 17of the petition, the Petitioner has averred that Rule 49-T of the Rules of 1961 have not been complied with. Rule 49-T reads as hereunder;

> **49-T. sealing of voting machine after poll.-** (1) As soon as practicable after the closing of the poll, the presiding officer shall close the control unit to ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit [and from the printer, where printer is also used, so however, that the paper slips contained in the drop box of the printer shall remain intact.]
> (2) [The control unit, the balloting unit and the printer, where it is used, shall] thereafter be sealed, and secured separately in such manner as the Election Commission may direct and the seal used for securing them shall be so affixed that it will not be possible to open the units without breaking the seals.
> (3) The polling agents present at the polling station, who desire to affix their seals, shall also be permitted to do so.

In paragraph 20 of the petition, the Petitioner has alleged that the information supplied to him on plain paper, in contravention of the prescribed format under Form 17-C, there is no mention of the use of seals put on the CU's at

the end of polling. The Petitioner has said that the non-mention of this fact in the information given to the Petitioner by way of plain paper entries at the end of polling is suggestive of the inescapable fact that the machines were not sealed at all as the seal paper numbers were not supplied to the Petitioner despite his demand in writing. Under the circumstances, the Petitioner has stated that all the Electronic Voting Machines (hereinafter referred to as "EVM's"), in respect of which the seal numbers were not provided to the Petitioner, were suspect and their use has materially affected the outcome of the election in favour of the Respondent No.1

9. Paragraph 21 of the election petition speaks at large about the purported unreliability of EVM's. The Petitioner has alleged that the voter is never certain if his vote has been actually counted in favour of the person he has voted by pressing the button against the candidate's name/image/symbol. However, this paragraph has been struck out from the petition by the order of this Court dated 12/09/14. This Court, while allowing in part the I.A No. 31/2014, filed by the Respondent No.1, held ***"So far as the accuracy and fairness of the EVM's is concerned, all doubts and queries regarding EVMs have already been answered in FAQs on the website of the Election Commission of India where it has been***

specifically shown that there is no possibility to vote more than once by pressing button again and again. Since the Petitioner has raised doubts in regard to fairness or impartiality of the officials engaged in the counting process, he is under an obligation to demonstrate as to how the EVMs could be tampered with to get the desired result. However, no expert opinion has been placed on record regarding the chances of misalignment of EVMs. On the other hand, correctness of all the technical aspects of the matter, as reflected in FAQs and the Press Note issued and uploaded on its website by the Election Commission of India, has already been verified on the judicial site (sic) in Michael B. Fernandes Vs. C.K. Jaffer Sharief, AIR 2004 Karnataka 289. Thus, the EVMs are full (sic) proof device for counting, therefore, the allegation made in Paragraph 21 in regard to EVMs are absolutely unnecessary and baseless, same are liable to be struck-off". Thus, the allegations levelled by the Petitioner with regard to the unreliability of the EVMs was gone into and struck off from the pleadings by the order of this Court dated 12/09/14. It is also necessary to record, that the order dated 12/09/14 was never challenged and therefore attained finality.

10. Finally, the Petitioner has prayed *inter alia* for a declaration from this Court that the election of the Respondent No.1 from Constituency 68 as void.

11. The Respondent No.1 filed his written statement to the petition and has denied the allegations in the petition. The admitted facts in this case which need not be proved, are (a) that the notification for election to the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh was on 01/11/13. (b) Pursuant to the notification, the Election Commission of India set 08/11/13 (Friday) as the last date for filing nominations. (c) The last date for scrutiny of the nominations was 09/11/13. (d) The last date for withdrawal of candidature was 11/11/13. (d) The polling shall take place on 25/11/13 if need be and (e) the election shall be completed by 11/12/13. It was also admitted as averred in Paragraph 5 of the petition that the Respondent No.1 filed his nomination paper on a ticket of the Bharatiya Janata Party (hereinafter referred to as the "BJP") along with twenty-five other candidates for the office of the M.P State Legislative Assembly from Constituency 68. The contents of paragraph 6 and 7 of the petition also have been admitted by the Respondent No.1 as the same appears to be a matter of record. Besides these, there are no other admitted facts in this case.

12. On 18/09/14, issues were framed by this Court which are as under:

S.No.	Issues Framed on 18/09/14	Finding of the Court
1	Whether Presiding Officer has failed to comply the Rule 49-S of the Conduct of Election Rules, 1961? (if yes), Effect.	**NO**
2	Whether Presiding Officer has failed to comply with Rule 49-T of the Conduct of Election Rules, 1961? Effect?	**NO**
3	Whether the Petitioner has levelled insignificant, inconsequential and baseless allegations against the officials of the Election Commission?	**YES**
4	Relief and Costs?	**Petition is dismissed, parties to bear their own costs.**
S.No	**Additional Issue framed on 05/10/15**	**Finding of the Court**
5	Whether the result of the election, in so far as it concerns the Respondent No.1, has been materially affected by; (i) improper reception, refusal or rejection of any vote; or (ii) any non-compliance with provisions of rules 49-S and 49-T of the Conduct of Election Rules, 1961.	**NO**

13. This Court now embarks on a detailed examination of the election petition, the written statement and the evidence adduced so as to conclude whether the Petitioner has established his case or not.

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION ON BEHALF OF PETITIONER:-

14. The statement of the PW1, the Petitioner Dr. Vivek Tiwari was recorded before this Court on 21/01/15 and 12/04/16. The long delay of almost one year and three months to complete the deposition of PW 1 was on account of the adjudication of several I.A's filed by the parties and the delay caused in the production of the original record pertaining to the election which was in the custody of the Returning Officer. Paragraphs 1 and 2 of the deposition are introductory in nature. In paragraph 3, the witness says that the election commission released a notification on 06/11/13 giving the description of the CU's and the BU's to be used in the constituency. The details were given to all the candidates. He further states, that after polling, he was given form 17-C in which details relating to the use of BU's and CU's did not match the description given to the candidates before the polls.

15. The witness has prepared and filed a comparative chart of the CU's and BU's which showed the polling booth wise allocation of the CU's and the BU's. The witness states that

there is a mismatch in the information given to the candidates before the polls and the details of the CU's and BU's used in certain polling booths. The witness has got this document proved as Ex-P/4. Upon the discrepancy coming to the notice of the Petitioner, he is stated to have complained to the District Election Officer, Rewa, Chief Election Officer, Madhya Pradesh at Bhopal and the Election Commission at New Delhi and also to the returning officer of Constituency 68. As regards the complaint made to the Election Commission by fax, the Petitioner has proved the fax report as Ex-P/5. In paragraph 7 of his deposition, this witness states that the polling officer at the booth level had given his election agent the entries made in Form 17-C which were not true copies of Form 17-C. He further states that the polling officer gave receipts of the seals placed on the CU and the BU, to the polling agent of the Petitioner, but did not take his signature on the seals and so contends that the polling officer did not comply with the provisions of Rule 49-T of the Rules of 1961. The crux of the Petitioner's evidence is that there was a difference with regard to some CU's and BU's whose details given to the candidates before the election and some CU's and BU's that were actually used in the polls. That the information with regard to votes polled were given to the Petitioner's polling agent in Form

17-C with regard to some polling booths and even in those forms, not all the requisite information was given and there were several places where information ought to have been given, but which were left blank. With regard to some of the polling booths, only information relating to the votes polled was given to the election agent of the Petitioner and a true copy of Form 17-C, with the information, was not given. It is also alleged that the polling officer did not take the signature of the polling agents of the Petitioner on the sealing slips used to seal the CU's and the BU's after the polling process.

16. In cross examination, PW 1 has stated that the copies of Form-17C that were given to him by the polling officer were incomplete. The witness has got these forms exhibited as Ex-P/7 to P/22. In paragraph 13, the witness states that the entries of some of the Form-17C were given to the polling agent of the Petitioner, written on plain paper and that all the details which ought to have been given in Form-17C were not given in the plain paper slips. He further states that the identification slips of all the voting machines were not given to the Petitioner but the ones that were given to him, he has exhibited the same as Ex-P/38 to P/43. The witness has also stated that the number on the CU's and the BU's that were given to the Petitioner on

Form-17C, did not match the numbers of the machines given before the polling.

17. In paragraph 22 of his deposition, PW 1 says that he lost the election on account of the green paper seal not being given to him. He also says that he had repeatedly objected to the green paper seals not being given to him during the course of the election through representations, which he says were not accepted from him. Counsel for the Respondent argued that no document has been produced by the witness to establish that he had ever made a representation to the authorities or raised the objections before the counting of the votes. The witness also does not say as to how the refusal to give the green paper slips to the Petitioner materially affected the outcome of the election.

18. In paragraph 23 of his deposition, the witness states that as per intelligence reports, the Respondent No.1 had won the elections on account of the irregularities in the electoral process. In cross examination by the Counsel for the Respondent No.1, to a specific query that the Petitioner has not levelled any specific allegation in the election petition against the Respondent No.1 of having indulged in any electoral malpractice, the Petitioner has replied that the election commission has committed the irregularities

so that the Respondent No.1 could win. In paragraph 28 of the deposition, the Petitioner says that it is correct to suggest that it was his polling agent who was engaged for receiving the documents from the election officers at the polling booth. The witness gives a voluntary statement that the signature of his polling agent was never taken on any of the green paper seals. The witness does not say that that his poling agent had demanded that he be allowed to sign the green paper seals and that the same was refused by the officers at the polling booth.

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION OF PW 2 SANTOSH KUMAR DWIVEDI:-

19. PW 2 is Santosh Kumar Dwivedi. He says that he is a supporter and worker of the Congress Party. He is the polling agent of the Petitioner. He was at the polling station from 7am. He says that besides him at the polling station, there were polling agents from other political parties like the Bahujan Samaj Party and the Samajwadi Party. The process of polling was explained to all of them by the Presiding Officer of the polling station. The voting went on till 5 pm at the polling station as stated by this witness. In paragraph 2 of his statement, this witness states that after the polling came to an end, he was given the details relating to the votes polled on a plain slip of paper. He refers to Ex.P/61 and says that the said document only

gave details of the total number of votes polled. He says that the said slip of paper had the description of the 717 votes polled and the slip was signed by the presiding officer. He says that the slip of paper did not provide the other information that was to be provided as per the printed format of Form 17-C. He further says that he and the other polling agents asked the presiding officer for the details relating to the polling as per format to which, the polling officer is stated to have informed them that it would be given to them later, but never was.

20. In paragraph 7 of his deposition, PW 2 states that he had himself maintained a record of the total votes polled, which was 717. He further admits that number of votes polled which were given to him by the presiding officer in Ex-P/61 were also 717. There is an admission that there is no conflict in the number of voters who had voted as per the private voters list maintained by PW 2 and in the Ex-P/61 which was given to the witness.

21. In paragraph 10 of his deposition, this witness states that he had made a written representation that he be given the details of Ex-P/61 in the appropriate format. He further expresses ignorance whether the copy of such representation has been annexed to the election petition or not. It is relevant to note here that this witness does not

say that he had ever demanded from the presiding officer that he be allowed to sign on the green slip used to seal the voting machines and that such permission was denied to him. This witness also does not say that there was any irregularity in the process of sealing of the BU and the CU and that he had protested about it to the presiding officer.

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION ON BEHALF OF RESPONDENT NO.1:-

22. DW 1 is Divya Raj Singh, the Respondent No.1. He states that he had stood for elections to the State Assembly from the Sirmour Assembly Seat No. 68 as a candidate of the Bharatiya Janata Party and he had polled 40018 votes in his favour with his closest rival, being the Petitioner, having polled 34730 votes in his favour and so the witness says that he was elected with a margin of 5288 votes. In paragraph 3 of his examination in chief, this witness states that all the requirements under Rule 49-S was complied with and that the information relating to the votes polled as per form 17-C was given to the candidates or their polling agents. In paragraph 4, this witness says that the procedure followed after the polling is that the BU and CU are disconnected and they are sealed in the presence of the candidates or their agents. He further says that there were no complaints by the candidates or their agents with regard to the procedure followed in sealing the BU's and

CU's. In paragraph 7 the witness denies that there was any collusion between him and the election authorities or that they had worked in such a manner in order to benefit him.

23. In cross examination, in paragraph 10, the witness states that in his reply to paragraph 14 of the election petition, he had averred that the kind of errors pointed out by the Petitioner are common. He volunteers a statement saying that some errors are clerical in nature. The witness has stated that he has not seen form 17-C that was given to his election agent and that all the 17-C forms or the plain paper slips were handed over by the witness to his lawyer. The witness states that he is unable to state as to when he went to a specific polling booth on the date of the election. He also states that he had gone to some polling booths for as short a time as two minutes and that he was not personally present when the CU's and the BU's were being sealed after polling. He further states that he has no personal knowledge that there were any objections taken with regard to the sealing of the CU's and BU's.

24. In paragraph 18 of his cross examination, this witness has stated that he is unable to say as to how many EVM machines were changed in the course of voting on account of them malfunctioning. He was asked whether he was aware that the six EVM machines that were changed

during the electoral process, were changed between 1 and 2 pm to which, the witness has answered that though he knows that machines were changed, he does not know the time at which the said machines were changed. He has also stated that he doesn't know that at the time when the machines were changed about 50% of the voting had already taken place. Ld. Counsel for the Respondent No.1 submits that this part of the witness's statement cannot be taken into reckoning as there is no specific pleading in the election petition to this effect. A specific suggestion was given to this witness that the polling booths in which the machine has malfunctioned, there two machines were used but at the time of counting, votes polled only in one machines were taken into account and that, the same was done with the intention of giving a benefit to the Respondent No.1. The suggestion has been denied by the witness. **The Ld. Counsel for the Respondent No.1 has taken an objection at this stage that the question ought not to be taken into consideration as there were no pleading in support of the same in the election petition. This Court had reserved a decision on the abovementioned objection at the time of final hearing.**

19. In paragraph 19 of his deposition, the witness, in cross examination says that documents annexed to his reply as R1 from page 133 to 144, were collated by his election

agent and handed over to his counsel. The Ld. Counsel for the Petitioner has argued that this is an admission on the part of the Respondent No.1 that such documents were in his knowledge and that he admits to the contents of the same. Ld. Counsel for the Respondent No.1 on the other hand has submitted that the documents, though filed by the Respondent No.1 along with his reply is not an admission of any fact on the part of the Respondent No.1, he further says that the case of the Petitioner ought to be proved on the basis of the evidence led by the Petitioner and not on the basis of unadmitted documents filed by the Respondent No.1.

EVIDENCE BY WAY OF DEPOSITION OF DW2 VIMLESH SINGH:-

26. D.W.2 is Vimlesh Singh. The witness was posted as Sub-Divisional Magistrate, Sirmour, District Rewa, during the Vidhan Sabha election in December 2015. The witness was the Returning Officer. The witness has testified that the Electronic Voting Machines (EVMs) were used in the election and that 175 polling booths were set up. Before the EVMs were allocated to the different polling booths, they were subjected to prior randomization. During the randomization, the observer, the Collector and the candidates or their representatives of all major political parties were present. In paragraph 3 of the examination-

in-chief, this witness has explained that the randomization process involved the maintenance of the records in which details relating to the EVMs allocated to particular polling booths were noted. The numbers of such machines, which were being used in specific polling booths, were noted. Thereafter, through an online method, the machines used to be distributed to their respective polling booths. The record of randomization has been produced before this court as Ex.P1 (which is the same as Ex-P/95). Before the polling, the Presiding Officers in the presence of the candidates or their representatives used to conduct a mock-poll. During the mock-poll if there was any error/malfunctioning noted in any machine, the Returning Officer would be informed and the machine would be changed. After the election, Form-17C and the entries in the diary were to be collated and handed over to the Presiding Officers. The Presiding Officers were given Form 17C's and they were directed to inform the candidates or their agents about it. *During the course of arguments, the Ld. Senior Counsel appearing on behalf of the Petitioner has raised a question that if Form 17C's were given to the Presiding Officer, why were the details relating to part 1 of the form given to the candidates on plain paper?* It is pertinent to mention here that none of the Petitioner's witnesses have stated that they have ever brought the fact

to the notice of the Returning Officer that they were not provided information relating to the polling in the prescribed format.

27. In paragraph 6, this witness has stated that the Presiding Officers, after the conclusion of the polling process, would submit the records at the Office of the Returning Officer. The witness further states that the said records have been produced before this court by her successor in office after the witness's transfer. After seeing the records, the witness has admitted that it is the same records that have been submitted by the various Presiding Officers and the same have been marked as Exhibits. D2 to D176. The witness further states that the witness never received any kind of complaint that the Presiding Officers have not given the information in the appropriate format. The witness further states that as per Rule 49 (s) of the Election Rules, the Presiding Officers were to give the information in the prescribed format which the witness assumes was done by them. Thereafter, the witness states that Rule 49T of the Election Rules provides for the sealing of the EVMs which, according to the witness, was scrupulously followed by the Presiding Officers. The sealing procedure is done at the polling booth itself by the Presiding Officers in the presence of the candidates or their agents as per the witness.

28. In cross-examination, this witness has stated that the witness's responsibility during the elections was to ensure that the elections took place in accordance with law and the officers acted in a manner in accordance with the training that was imparted to them. The witness states that the witness has not given latitude to any of the officers associated with the electoral process to act in derogation of the rules. The witness states that the witness had seen the Form 17-C but is unable to recall as to how many pages the said form consisted of. The witness states that the said 17-C forms were filled by the Presiding Officers. The same are filled up immediately after the polling process. Upon being asked whether the witness had enquired if the 17-C forms were given completely filled up in the format prescribed to the candidates or their agents, the witness replied that such instructions were given to the Polling Officers and they might have acted accordingly. The witness admits that the witness did not enquire whether the 17-C Forms were given to the candidates or their agents in the prescribed format completely filled up. The witness volunteers a statement to the effect that this duty was that of the Presiding Officers. The witness lastly states in paragraph 12 that the witness did not carry out a random check of the Presiding Officers with regard to the distribution of Form 17-C. In paragraph 13 the witness

has stated that Part II of Form 17-C is filled up after the counting process is complete. The witness has further clarified this aspect in paragraph 14 of her statement that the first part of Form 17-C is filled up before the polling process commences and the second part of Form 17-C is filled up after the polling process. The witness further states that it is correct to suggest that it is the duty of the Presiding Officer to fill up all columns of Form 17-C. The witness has also admitted as correct the suggestion that after the Form 17-C is filled up by the Presiding Officer, he affixes his signature to Form 17-C and then gives the same to the candidates. The witness further admits as correct that the witness did not go to enquire, after the conclusion of the polling process, to find out whether the polling process has been done in accordance with law. The witness volunteers a statement to the effect that in every polling booth, it is the duty of the Presiding Officer along with five or six Polling Officers, who in conjunction with the Sector Magistrate who is an Executive Magistrate, tour every polling booth and keep a watch on the polling process. In paragraph 15, this witness states that it is the witness's duty to be present in the election office and look after the overall conduct of the election and if the witness receives any kind of complaint then the witness would go to the site.

29. The witness was shown the copies of Form 17-C annexed to the petition, upon which she has stated that that it has not been filled up completely. She volunteers that the said documents are to be filled up by the Presiding Officer. In paragraph 18, this witness was confronted with Ex-D/2 to Ex. D/177, which are the original Form 17-C's produced by this witness and proved by her before this Court. She has admitted after seeing the said exhibits that most of the Form 17-C's were not filled up completely and that most of them did not bear the signature of the election agent. In paragraph 18, this witness has stated that she does not have knowledge whether there is any provision in form 17-C for entering the numbers given to the green paper seal (which are used to seal the ballot machine after the polling process). In paragraph 19, this witness has specifically denied that the absence of the number given to the green paper seal has materially affected the outcome of the election. In paragraph 20 of her cross-examination this witness says that it is correct to suggest that Ex-D/2 to Ex-D/177, which are Form 17-C's, there Part-II, which is filled up after the electoral process have not been filled up and neither they have been signed by the electoral officer or any other officials. She also states that she has not signed the Part-II of Form 17-C's. She has volunteered her statement that the election team, after its return and

before the counting of the votes, secures the Form 17-C in a strong room and thereafter without the designated officers permission or the courts direction they are not taken out. **The learned counsel for the Petitioner has referred to this part of the statement in the course of the submission in order to establish that the details relating to the votes polled, which ought to have been entered in Part-II of Form 17-C, by its omission in the said Part-II of Form 17-C, has materially affected the election process. The said point has been countered by the learned counsel for the Respondent who has argued that there is no legal sanctity to this part of the witness's statement in the cross-examination as facts relating to the absence of details relating to the votes polled in Part-II of the Form 17-C and how they have materially affected the election process are not averred in the election petition.**

30. In paragraph 22, this witness has admitted that Part-II of Form 17-C should have been filled up. In paragraph 25 of her cross-examination she states that Ex. D/179 to Ex-D/355, which were produced by this witness before this Court were filled up after the electoral process. In paragraph 34, this witness has stated that the green paper seal is used for saving the EVM from manipulation and to ensure transparency in the electoral process. She says

that it is corrected to suggest that the numbers which are given to the green paper seal are to be entered in Form 17-C. In paragraphs 35 and 36 she has stated that it is correct to suggest that the green paper seal is used to seal the balloting unit and the control unit after the end of the polling process. She further states that it is correct to suggest that in 68 Sirmour constituency about 7-8 EVM machines had malfunctioned.

31. **Issue No.1 Whether the Presiding Officer has failed to comply with the Rule 49-S of the Conduct of Election Rules, 1961? If yes, its Effect?**:-

P.W.1, the Petitioner Dr. Vivek Tiwari, deposed before this Court on 21.1.2015 and 12.4.2016. He stated that the Election Commission had released a notification on 6.11.2013 giving the description of CU's and BU's to be used in the constituency. This notification was given to all the candidates. He has further stated that after the polling, he was given Form 17-C in which details relating to the CU's and BU's did not match the description given in the notification. A comparative chart of the CU's and BU's showing the polling booth wise allocation of the CU's and BU's given to the candidates before the polls, and the details of the CU's and BU's used in certain polling booths, where the numbers did not match with the list given earlier, has been filed. The documents giving the

comparison between CU's and BU's proposed to be used in the said constituency and the CU's and BU's actually used during the poll, is Ex-P/4. This witness is stated to have complained to the District Election Officer, Rewa, the Chief Election Officer, Madhya Pradesh at Bhopal, the Election Commission at New Delhi and also to the Returning Officer of constituency No. 68. The said discrepancy, at the risk of repetition, was not framed as an issue by this Court and the same does not have any direct bearing on Rule 49(s) or 49(d) of the Rules of 1961. Based upon this, the Petitioner has questioned the election of Respondent No.1. As the same was never an issue before this Court and no objection was ever raised by the Petitioner with regard to the same not having being framed as an issue, this Court considers it unnecessary to go into the controversy in depth. However, upon bare perusal of Ex-P/4, some of the discrepancies are clerical in nature. This aspect has also been stated by the Respondent No.1 in his evidence before this Court at paragraph 10 of his deposition before the Court. The Petitioner has also not led any evidence to establish as to how the discrepancies raised a suspicion with regard to the sanctity and accuracy of the control unit or the ballot unit which were actually used in the electoral process. Bald allegations in the petition, to the effect that the said changes in the ballot

units and the control units were made, to surreptitiously assist the Respondent No.1, is only an allegation without substantiation. The Petitioner has not led any evidence from his side by calling an officer of the election commission as a witness and asking for an explanation from him as to how the said discrepancies arose in the control units and ballot units which were proposed to be used in the Constituency No.68 and the ones that were actually used. The variation in the numbers on the CU's and the BU's, which were earlier proposed to be used and the ones that were ultimately used for polling, could be for several bonafide reasons ranging from the proposed CU's and BU's found to be malfunctioning or simply on account of clerical error in noting down the numbers of CU's and BU's. It is also relevant to mention here that the Petitioner has not cross-examined D.W.2 Vimlesh Singh, who was the Returning Officer on this aspect. No explanation has been sought by the Petitioner from D.W.2 with regard to the discrepancies in the numbers given in the CU's and BU's prior to the election and those which were actually used in polling process. No suggestion has also been given to this witness that the discrepancies in the CU's and BU's proposed to be used and the ones which were actually used in polling was done with the intent of assisting the Respondent No.1. Under the circumstances, the cloud of

doubt sought to be raised by the Petitioner in paragraph 14 of this petition with regard to the CU's and BU's which were sent to 19 polling booths cannot be said to have materially affect the outcome of the election.

32. As regards the violation of Rule 49(s) on account of the improper preparation of Form 17-C and on account of the votes recorded not been handed over to the polling agents of the candidate in the format prescribed, having materially affected the outcome of the election, the Petitioner has stated that the copies of the Form 17-C that was given to him by the polling officer was incomplete. The Petitioner has got these forms exhibited as exhibits P7 to P17. In paragraph 13 of his deposition, the Petitioner states that the entries of some of the Form 17-C's were given to the polling agent of the Petitioner written on plain paper. It was also stated that all details which ought to have been given in Form 17-C were not on the plain paper slips. In paragraph 22 of his deposition, the Petitioner states that he lost the election on account of the green paper seal not been given to him. In paragraph 23 of his deposition the Petitioner states that the Respondent No.1 had won the elections on account of the irregularities in the electoral process. He states that the election commission had committed the irregularities so that the Respondent No.1 could win.

33. P.W.2 Santosh Kumar Dwivedi, was the polling agent of the Petitioner. He states that after the polling concluded, he was given the details of votes polled on a plain slip of paper. He refers to Ex-P/61 to show that the documents gave details of the total number of votes polled and that the same was not in the prescribed format. This witness states that he had maintained a record personally of the total votes polled, which according to him was 717. He admits that the details of the number of votes polled, as given to him by the Presiding Officer in Ex-P/61, were also 717. There is an admission by this witness that there is no conflict in the number of votes polled as per the list maintained by him and Ex-P/61, which was the slip giving the details of the votes polled which was given to the witness by the polling officer after the poll. This witness also states that he had given a request in writing to the Presiding Officer that the details of Form 17-C be given to him in the prescribed format. However, he says that he does not know whether such a copy of the request has been annexed to the election petition.

34. As regards the question whether there was any failure to comply with Rule 49(s) of the Rules of 1961, it is essential to appreciate the purpose sought to be achieved by Rule 49(s). The rule relates to the accounting of votes recorded. As per the rule, the Presiding Officer, at the close of the

poll, was to prepare an account of votes recorded in Form 17-C and furnish every polling agent present at the close of the poll **a true copy of the entries** made in Form 17-C after obtaining a receipt from the polling agent and shall attest it as a true copy. Form 17-C has been exhibited by the Petitioner. In all there are details to be filled up for ten queries in Part-I of Form 17-C. The question that arises for consideration is whether it is mandatory that each and every query in serial number 1 to 10 ought to be filled up by the Presiding Officer, so that it may be said to be compliant of Rule 49(s)?. Sub-rule (1) of Rule 49(s) mandates that the Presiding Officer shall prepare **an account of the votes recorded** in Form 17-C at the close of the polls. The mandatory requirement of Rule 49(s) is to prepare an account of the votes recorded in Form 17-C. In part-I of Form 17-C the total number of votes polled is to be entered at serial no.6. Thus, for compliance with Rule 49(s), there should be an entry of the votes polled, recorded at serial no.6 of Form 17-C. If the total votes polled is not recorded in serial no.6 of Part-I of Form 17-C, then it can be said without any doubt that there has been non-compliance of Rule 49(s). As regards the contention of the Petitioner that the Presiding Officer ought to have provided an exact copy of Form 17-C to every polling agent at the close of the poll, this court begs to differ. Sub-Rule (2) of

Rule 49(s) only mandates that the Presiding Officer shall **furnish to every polling agent present at the close of poll**, a true copy of the **entries** made in Form 17-C. The said rule does not lay down as an indelible proposition that a facsimile of Form 17-C is to be given to every polling agent present. It only provides for the entries made in the said form to be given to the polling agent. Thus, if those entries relating to total votes polled which is mandated under Rule 49(s) (1), is provided to the polling agent present, the same would effectively satisfy the requirement of Sub-Rule (2) of Rule 49(s).

35. The learned counsel for the Petitioner has relied upon the judgments of the Supreme Court reported in (2001) 4 SCC 9 Dhananjay Reddy Vs. State of Karnataka, (2014) 3 SCC 502 Deepak Babaria and another Vs. State of Gujarat and others, in support of his proposition on a principle of statutory interpretation that where under the Statute, the law requires a thing to be done in a certain manner, it has to be done in that manner only or not at all. In other words, a power must be exercised only in the manner provided by the statute. There can be no grievance with the said proposition of law. Undoubtedly, a power must be exercised in the manner provided by the statute. A plain reading of Rule 49(s) discloses the intent and purpose of the said rule. The rule is limited to providing an account

of votes recorded in Form 17-C. The manner in which the account of votes recorded is to be supplied to the polling agent of the candidate is by giving a copy of the entries as per the format of Form 17-C. Sub-Rule (1) of Rule 49(s) as stated hereinabove, relates only to the supply of accounts of votes recorded in Form 17-C and not the other details which are also recorded in Form 17-C in addition to the accounts of votes recorded. Thus, as per Rule 49(s), all that the Presiding Officer has to provide to the polling agent of the candidate is the account of votes recorded or polled as entered in serial no. 6 of Part-I of Form 17-C. The manner in which the said information can be provided need not only be by providing an exact copy of Form 17-C, but it can also be done by providing the entry at serial no.6 of Form 17-C, related to the account of votes recorded. Besides, this information also is to be given to the polling agent of the candidate provided, he is present before the Presiding Officer. D.W.2 has stated in her deposition that there was compliance with Rule 49(s) as accounts of votes recorded was handed over to the polling agents of the candidates. Thus, this Court holds with regard to issue No.1, that there was no failure on the part of the Presiding Officer to comply with Rule 49(s) of the Rules of 1961 and, therefore, **Issue No. 1** is answered in the negative.

36. Issue No.2: Whether the Presiding Officer has failed to comply with Rule 49(D) of the Rules of 1961, if yes, its effect. Rule 49(D) of the rules of 1961 provide for the sealing of the voting machine after poll.

The rule requires that as soon as practicable, after the closing of the poll, the Presiding Officer shall close the control unit and ensure that no further votes can be recorded and shall detach the balloting unit from the control unit and also from the printer, where a printer is used. Sub-Rule (2) of Rule 49(D) provides for the control unit and the balloting unit and the printer (where it is used), to be sealed and secured separately in such a manner as the election commission may direct. The seal used in securing them shall be so affixed that it would not be possible to open the units without breaking the seal. Sub-rule (3) of Rule 49(D) provides that the polling agents present at the polling station who desire to affix their seal also, be permitted to do so. The said rule postulates **(a)** that the Presiding Officer after the close of the polls to ensure that no further votes can be recorded would detach the balloting unit from the control unit. Thereafter, **(b)** the control unit and the balloting unit would be sealed and secured separately by affixing seals in such a manner that the units cannot be opened without breaking the seals and **(c)** where the polling agents are present at the polling

station, they shall be allowed to affix their seals if they so desire. The Petitioner has stated in his evidence that the seal numbers not being mentioned in some of the Form 17-C only goes to show that such sealing was not done at all. In paragraph 22 of his deposition, the Petitioner says that he lost the election on account of the green paper seal not being given to him. He also states that he had repeatedly objected to the green paper seal not being given to him through representations, which were not accepted from him by the Commission. No such evidence has been brought on recorded by the Petitioner to show that he had preferred such a complaint and that the same was not accepted from him. Even otherwise, Rule 49(D) does not require the green paper seal being given to any candidate or the election agent. The limited role that the candidate has through his election agent with regard to sealing of the control unit and ballot unit, is as provided under Sub-Rule (3) of Rule 49(D) where the election agent, if present and if so desirous, may be allowed to put the candidates seal on the green paper seal used to secure the control unit and the ballot unit. In this regard, it would also be relevant to refer to the statement of P.W.2, who is the election agent of the Petitioner states in paragraph 2 "वोटिंग ख़तम होने के बाद प्रेसिडिंग अफसर ने पेटियों को सील करना चालू कर दिया और जब

हमने वोटिंग का विवरण माँगा तो उन्होंने कहा की सील होने के बाद देंगे ।"

It is the contention of the Petitioner's witness itself, who is also his election agent, that immediately after the polling concluded the Presiding Officer commenced the sealing of the control unit and the balloting unit. There is no reason to doubt the veracity of this witness as he being the election agent of the Petitioner, was present at the office of the Presiding Officer and was privy to the sealing of the control unit and the balloting unit as so stated by this witness in his examination-in-chief itself. Only because certain 17-C forms did not have the seal numbers of the green paper seal used to seal the control unit and the balloting unit is inadequate to infer that there was any tampering or that any additional votes were recorded after the polling concluded, such a conclusion cannot be inferred without specific evidence being led to that effect. Such has not been alleged and neither has it been established. The apprehension of the Petitioner to that effect is purely conjectural and is devoid of any material to establish the same. D.W.2 in paragraph 19 of her deposition before this Court has categorically stated to a suggestion "यह कहना गलत है की 17 -C फॉर्म में ग्रीन पेपर सील के नंबर नहीं दिए जाने के कारण 68 विधान सभा क्षेत्र में मटेरियल इफ़ेक्ट पिटीशनर के चुनाव में पड़ा ।".

37. It is also relevant to refer to Ex.P.6, which is a letter written by the Petitioner to the Chief Election Commissioner Madhya Pradesh received by the office of the Collector and the District Election Officer District Rewa on 5.12.2013. In this letter in which the Petitioner has raised a grievance that the Presiding Officer is not taking the signature of the election agent on the record of votes polled and that the record of votes polled with regard to certain polling booths were not in the format prescribed under Form 17-C and that the same was given on plain paper. The only relief prayed for in the said letter was that in the annexed list, the Presiding Officer be directed to give a clear description with regard to the votes recorded in the polling booths mentioned in the list and the same be provided to the Petitioner. In this letter to the election commission there is no grievance made to the effect that there was no sealing of some of the CU's and BU's or that there was improper sealing or that the details of those seals were not entered in Form 17-C. The Petitioner itself stands contradicted by its own witness P.W.2, his election agent, who has stated that the Presiding Officer commenced sealing process of the CU's and BU's immediately after the polling was over. Under the circumstances, the Petitioner has failed to bring any material on record to demonstrate that the Presiding Officer had failed to comply with the provisions of Rule

49(D) of the Rules of 1961 and, therefore, the **Issue No.2** is also answered in the negative.

38. **Issue no.5 (additional issue): The result of the election, in so far as it concerns the Respondent No.1, has been material effected by (i) improper reception, refusal or rejection of any vote or (ii) any non-compliance of the provisions of Rules 49(S) and 49(D).**

39. As regards issue no.5(i), it has never been the case of the Petitioner that there was any improper reception, refusal or rejection of any vote. No averment has been made to the effect in the petition and no evidence has been led by the Petitioner to establish improper reception, refusal or rejection of any vote and neither has that been brought out in the cross examination of either D.W.1 or D.W.2. It has be held by the Hon'ble Supreme Court in a catena of decisions that where a pleading has not been taken in the plaint, evidence with regard to that point cannot be lead as the same would take the opposite side by surprise. Further, if evidence is even led with regard to a point not raised in the pleadings, the same cannot be looked into and appreciated by the Court. Thus, the objection raised by the Ld. Counsel for the Respondent, enumerated in paragraph 24 *supra*, that in the course of evidence, those statements of the Petitioner, which are not supported by

pleadings, ought not to be looked into and appreciated by this Court, stands answered accordingly in favour of the Respondent No.1.

40. The Petitioner has in paragraph 14 at page 13 of his petition alleged that, "the effect of using the control units and balloting units different from those notified in Annexure P5 has led to false and fabricated voting at the instance of the Respondent No.1 which took the Petitioner by great surprise and there remains no check and balance to ascertain the correct control and balloting units as already mentioned and informed to the Petitioner were actually sent and used". The Petitioner has made a bald allegation to the effect that use of some control units and balloting units being different from those notified before the polls had led to fake and fabricated voting. But for stating thus, the Petitioner has miserably failed to adduce any evidence to establish the same. An inference whether false and fabricated voting has taken place can only be based upon evidence and the same cannot be drawn in vacuum. The Petitioner himself does not state in his evidence as to how the false and fabricated voting had taken place and his own election agent examined as P.W.2 is completely silent about any kind of false and fabricated voting. Under the circumstances **Issue No. 5(i)** has to be answered in the negative.

41. Issue No. 5(ii): any non-compliance with provisions of rules 49-S and 49-T of the Conduct of Election Rules, 1961.

As regards Issue no.5 (ii), the same stands answered in the negative in view of the findings given by this Court regard to issue nos. 1 and 3.

42. Issue no.3: Whether the Petitioner has levelled insignificant, inconsequential and baseless allegations against the officials of the election commission.

In his deposition before the Court, the Petitioner who has examined himself as P.W.1, has stated in paragraph 21 that the election commission gave him blank Form 17-C's and incomplete information on plain paper and most importantly, concealing the paper seal number from the Petitioner with a deliberate intent of ensuring his defeat in the election. In paragraph 22, this witness has stated that he lost the election on account of the green paper seal not given to him. He has also repeatedly objected to the green paper seal not being given to him during the course of the election through representations, which were not accepted from him by the election commission. The same allegation is unsubstantiated as no such representation raising the above issue, has been placed on record and proved by the Petitioner. The only representation that he ever made to the election commission was Ex-P/6, which D.W.2 also

admits having received from the Petitioner. In paragraph 23 of his deposition, the witness states that as per intelligence report, the Respondent No.1 had won the elections on account of the irregularities in the election process. In cross-examination by the counsel for the Respondent no.1, to a specific query after paragraph No.25 that the Petitioner in his entire petition has not alleged any kind of corrupt practice or irregularities against the Respondent No.1, the Petitioner has answered that the election commission has committed the irregularities in order to ensure the victory of Respondent No.1. Another question that was asked to the Petitioner was whether the Petitioner in his petition has anywhere alleged that the election commission has committed all the irregularities in order to ensure the victory of the Respondent No.1, the Petitioner replied that the entire petition has been drawn up in such a manner which would reflect that the election commission had ensured the victory of Respondent No.1.

5. In view of the evidence that has come on record which has been reiterated hereinabove, **Issue No.3** has to be answered in the positive that the Petitioner has levelled insignificant, inconsequential and baseless allegations against the officials of the election commission.

44. **Issue No. 4: Relief and Costs**: In view of the aforesaid findings of this Court, based upon the pleadings and evidence on record, **the election petition fails and is dismissed. The parties shall bear their own costs as even though the election petition does not succeed, it cannot be said that the petition filed by the Petitioner was frivolous, vexatious and an abuse of the process of the court.**

45. The office is requested to return the original records to departments concerned.

46. A copy of this order be sent to the Election Commission and the State Election Commission.

Atul Sreedharan
Judge

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2018

फा. क्र. ई.पी.-28-2014-चार-वि.निर्वा.-191.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 82-MP-LA-(28/2014)/2018 (लक्ष्मीकांत शर्मा विरुद्ध गोवर्धन उपाध्याय एवं अन्य) दिनांक 2 अगस्त 2018 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

राकेश कुशरे, उपसचिव.

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT GWALIOR
(SB : VIVEK AGARWAL, J.)

Election Petition No.28/2014
Laxmikant Sharma
Vs.
Govardhan Upadhyaya & Others.

Shri J.P. Mishra, learned senior counsel with Shri R.S. Bansal, counsel for the petitioner.
Shri K. N. Gupta, learned senior counsel with Shri R. K. Shakya, counsel for respondent no.1.
Shri K. L. Tiwari, learned counsel for respondent no.9.
Shri Sanjay Dwivedi, learned counsel for respondent no.10.
Date of hearing : 26.03.2018.

ORDER

(Passed on 29th June, 2018)

This election petition has been filed by petitioner Laxmikant Sharma under the provisions of Sections 80 and 81 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter for short 'Act of 1951') being aggrieved by result of the election for the Legislative Assembly Constituency Sironj (General) No.147, to which the elections were held on 25.11.2013 and in which respondent no.1-Govardhan Upadhyay has been declared as a winning candidate.

2. It is petitioner's contention that the petitioner was a sitting MLA and Minister of the State of Madhya Pradesh at the time when nominations were filled, for which last date was 08.11.2013. The last date for withdrawal of the nomination was 13.11.2013 and after such last date of withdrawal, there were 12 candidates in the fray who contested the elections for the Legislative Assembly Constituency No.147 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha. Out of these 12 contesting candidates, 11 have been arrayed as respondents and besides them, the petitioner was also a candidate.

3. It is submitted that the petitioner was given a ticket to contest the election on the party symbol of Bhartiya Janata Party, whereas respondent no.1-Govardhan Upadhyay contested the election on the symbol and ticket of Indian National Congress. Similarly, respondent no.2-Mubaraq Ali contested the election on ticket of Bahujan Samaj Party, respondent no.3-Mohammad Nazir Khan contested the election as a candidate of Hindustan Janta Party, respondent no.4-Sameena Bai contested the election as a candidate of Bahujan Sangharsh Dal, respondent no.5-Smt. Shobna Yadav was a candidate of Samajwadi Party and the other respondents contested the election as independent candidates.

4. It is petitioner's contention that there were about 182000 voters in the Sironj (General) Legislative Assembly Constituency No.147 and the total number of votes polled as per Form 20 of the Conduct of Election Rules were 142173.

5. According to the petitioner, when the results were declared, the petitioner had secured 63713 votes whereas respondent no.1-Govardhan Upadhyay had secured 65297 votes, therefore, the total difference of votes between the two main contesting candidates was only 1584 votes, i.e., the margin of win of respondent no.1-Govardhan Upadhyay was a very slender; that was only 1584 votes.

6. It is petitioner's allegation that the petitioner was having a clear edge in the Constituency because of the composition of the voters and also because of his past association with the Constituency, which he had nurtured very hard with all his efforts both as a Member of Legislative Assembly and as a Minister holding important portfolio in the Ministry of State of Madhya Pradesh. He submits that just few days before the election, a *mala fide* campaign was lodged against him so as to tarnish his

image and this campaign was suspectedly launched by respondent no.1 and his supporters, which resulted in his defeat and such campaign was in violation of the provisions of the Model Code of Conduct and Constituted Corrupt Practices as mentioned in Section 100 (1) (b) (d) (iv), Section 123 (3-A) and Section 123 (4) of the Act of 1951.

7. It is submitted that on 23.11.2013 at about 1.00-1.30 PM at Village Lateri, a newspaper in the form of pamphlet was circulated in the name and style 'Karara Jawab' (Ex.P/28), which does not bear the names of Editor, Printer and Publisher. This pamphlet only makes a location of place and date and it was circulated by one Toran Ahirwar son of Dev Chand Ahirwar resident of Ward No.5, Lateri, District Vidisha with consent and under directions of respondent no.1 so also his election agent and supporters. It is submitted that this newspaper published in the form of pamphlet, as was circulated on 23.11.2013, was followed by another pamphlet under the title 'Batao Main Kaun Hoon'. This was followed by a third handbill under the title 'Jo Moda To Bigad Gayo'.

8. It is submitted that 'Karara Jawab' was circulated to various residents of Village Lateri and was read by several persons including PW6 Vinod Kumar Jain son of Chandmal Jain, resident of Muraiya, Tahsil Lateri, District Vidisha and PW5 Vinod Kumar Baghel son of Sardar Singh Baghel, resident of Village Lateri, District Vidisha. It is also averred that subsequently PW6 Vinod Kumar Jain and PW5 Vinod Kumar Baghel had informed the petitioner about circulation of the alleged newspaper on the very same day and thereafter on behalf of the petitioner, one Suresh Kumar Jain, President of Bhartiya Janata Party, Village Lateri, had lodged a complaint about the alleged circulation of newspaper

before the Sub-Divisional Magistrate, Lateri, District Vidisha. It is submitted that on the same day on 23.11.2013, this newspaper was also circulated in Sironj, District Vidisha by one Shri Vishal Rawal son of Shri Surendra Narayan Rawal, resident of Patwa Tola, Sironj at about 11.00 AM to 12.00 AM with consent and under direction of respondent no.1. At Sironj, it was read by PW2 Munim Gourie son of Shri Kallu Khan, resident of Ward No.4 Rakab Ganj and PW1 Pappu Sahu son of Shri K.L. Sahu, resident of Ward No.1, Govardhan Sahu Wali Gali, Sironj, District Vidisha. It is further submitted that they had conveyed such information to Shri Ramesh Yadav, President of Bhartiya Janata Party, Sironj, who had lodged a complaint about alleged circulation to the Returning Officer.

9. On 24.11.2013, one Sunil son of Rajendra Yadav, resident of Nishad Talkies, Sironj and Mukesh son of Shri Nandkishore Sen, resident of Patwa Tola, Sironj circulated pamphlet 'Batao Mein Kaun Hoon' and 'Jo Moda To Bigad Gayo'. Immediately information was furnished by the petitioner's agent PW7 Om Prakash Sharma to the concerned Police Station, the aforesaid two persons Sunil and Mukesh were arrested and the proceedings were initiated against them under the provisions of Section 127 of the Act of 1951. It is submitted that all these exercise were undertaken to lower the image of the petitioner and divert the mindset of the voters of the Constituency. The said act done by respondent no.1 or at his behest is contrary to the provisions contained in Section 123 (3-A) and 4 of the Act of 1951.

10. It is submitted that since the petitioner lost the election by a thin margin, respondent no.1 was declared as elected on 08.12.2013, therefore, the present election petition has been

filed.

11. In the election petition, relief has been sought that the election of respondent no.1 from Sironj (General) Legislative Assembly Constituency No.147 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha be declared as void and the same be set aside. It is also prayed that the petitioner be declared as a returned candidate from Sironj (General) Legislative Assembly Constituency No.147 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha. It is also prayed that suitable punishment be awarded to those found to be involved in corrupt practices and in addition suitable costs be also awarded in favour of the petitioner.

12. Respondent no.1 had filed a written statement so also respondent no.10-Mahendra Pratap Singh through their respective counsel. Reply was also filed on behalf of respondent no.6. As far as reply is concerned, respondent no.1 is the main contesting candidate and he in his reply raised preliminary objection that the petition does not contain material facts and particulars for constituting the ground of corrupt practices. He also took objection that the petition should be dismissed as affidavit annexed with the petition is not in terms of the requirements under Rule 94-A of the Conduct of Election Rules in Form No.25. Further objection was taken that the petition is not properly verified as required under Order 6 Rule 15 of the Code of Civil Procedure and prayed for dismissal.

13. He admitted the loss of election by the petitioner in the hands of respondent no.1, but denied that respondent no.1 vitiated any of the provisions contained in Section 123 (3-A) and 123 (4) of the RP Act. He denied the allegation that respondent no.1 was grossly involved in corrupt practices enumerated under Section 100 (1) (b) (d) (vv) of the Act of 1951. He denied

distribution of newspaper in the form of pamphlet, i.e., 'Karara Jawab' on 23.11.2013 between 1.00 to 1.30 PM at Village Lateri and submitted that this pamphlet does not bear the names of the Editor, Printer and Publisher. He further denied distribution of such pamphlet in the hands of Toran Ahirwar. He denied their being any consent of respondent no.1 behind such distribution of pamphlet or that of his election agent or his supporters. He denied that pamphlet was received by Vinod Kumar Jain and Vinod Kumar Baghel. He further denied that they had informed the petitioner about circulation on the very same day and also denied another complaint being lodged by Sudesh Kumar Jain, President Bhartiya Janta Party, Lateri before SDM Lateri.

14. He denied the contents of paragraph 7 of the petition.

15. Respondent no.1 similarly denied the allegation of circulation of 'Karara Jawab' in Village Sironj by Vishal Rawal at about 11.00 AM to 12.00 AM with consent of respondent no.1 or his election agent or his supporters. He also denied reading over of such newspaper by Munim Gourie son of Shri Kallu Khan and Pappu Sahu resident of Sironj. He denied any information being conveyed to Shri Ramesh Yadav President of Bhartiya Janta Party, Sironj, District Vidisha. He also denied any complaint being lodged by such Ramesh Yadav before the Returning Officer on the same day. He, however, mentioned that the complaint was found meritless.

16. In paragraph 9, he denied distribution of pamphlets 'Batao Main Kaun Hoon' and 'Jo Moda To Bigad Gayo' on 24.11.2013 between 10.00 AM to 12.00 AM. He also denied their circulation by Sunil son of Rajendra Yadav and Mukesh son of Nandkishore Sen. He submitted that no such pamphlets were printed and circulated by them and he also denied arrest of Sunil and

Mukesh. He also denied any act being done by Sunil and Mukesh at his instance or at the instance of his agent or supporters. He denied any attempt on his own part or his agent or supporters in abetting and attempting to procure assistance to defeat the petitioner, a sitting Minister of the ruling party. He further submitted that the documents are not duly verified and, therefore, made a prayer that the petitioner is not entitled to the relief prayed for in the petition.

17. Respondent no.6 also denied circulation or publication of any such newspaper or pamphlets in the Constituency and almost similar stand was taken by respondent no.10.

18. In this backdrop, the following issues were framed :-

(1)Whether respondent no.1 adopted corrupt practice as enumerated in Section 100 (1) (b), (d) (iv), 123 (3-A) and Section 123 (4) of the Representation of People Act, 1951 in the election in question?

(2)Whether the contents of the newspaper/pamphlet Karara Jawab attempted to assassinate the character of the petitioner by projecting him to be involved in killing of cows and amassing black money and other socially not acceptable activities directly effecting the result of the election by circulating the said newspaper/pamphlet in Tahsil Sironj on 23.11.2013 on the directions of respondent no.1?

(3)Whether the petition is filed within the prescribed period of limitation?

(4)Whether the petitioner has deposited appropriate Court fee and if not its effect?

(5)Whether the election petition is liable to be dismissed on any of the following reasons :-

(i) That, the complaint filed on behalf of the petitioner was found meritless.

(ii) That, the documents/pamphlet annexed with petition are not admissible in evidence.

(iii) That, the petition was not duly verified as per Order 6 Rule 15 CPC?

(iv) That, the affidavit dated 22.1.14 as per Form 25 of Rule 94-A is not valid and also not duly verified.

(6)Whether the petition is frivolous and vexatious and hence the same can be dismissed imposing exemplary cost under Section 35-A CPC?

(7)Relief and costs?

19. For the sake of convenience, issues no.3 and 4, namely, whether the petition is filed within the prescribed period of limitation and whether the petitioner has deposited appropriate Court fee and if not its effect, are being dealt with first as they will have material bearing as to whether the other issues are to be decided on merits or not.

20. This election petition was presented before the Registrar (J-II), High Court of Madhya Pradesh Jabalpur on 22.01.2014.

21. Section 81 (1) of the Act of 1951 provides that an election petition calling in question any election may be presented to on one or more of the grounds specified in sub-Section (1) of Section 100 and Section 101 of the Act of 1951 to the High Court by any candidate at such election or any elector within 45 days, but not earlier than the date of election of the returned candidate or if there are more than one returned candidate at the election and the dates of their election are different, the later of those two dates.

22. Reliance has been placed on the judgment of the Hon'ble

Supreme Court in the case of **Tarun Prasad Chatterjee v. Dinanath Sharma as reported in (2001) AIR (SC) 36,** wherein it is said that the day of declaration of the result is to be excluded for the purpose of computing 45 days' limitation. Therefore, the petition is within limitation.

23. In the present case, it is an admitted position that counting had taken place on 08.12.2013 and the result was declared on 08.12.2013, therefore, the election petition filed on 22.01.2014 will be deemed to be within the prescribed period of limitation and, therefore, this issue of limitation is to be answered in affirmative that the election petition has been filed within the prescribed period of limitation.

24. Similarly, Section 117 (1) of the Act of 1951 provides that at the time of presenting an election petition, the petitioner shall deposit in the High Court in accordance with the Rules of the High Court a sum of two thousand rupees as security for the costs of the petition. In view of such provisions contained in Section 117 (1) of the Act of 1951, it is apparent from the petition itself that the petitioner had deposited a sum of Rs.2,000/-, it cannot be said that the petitioner had not deposited appropriate fee as security at the time of filing of the election petition. Therefore, issue no.4 is also required to be decided in affirmative and is decided as such that the petitioner has deposited appropriate Court fee and, therefore, the election petition cannot be thrown out on such premise.

25. **Issue No.5** : As far as the pleading of respondent no.1 that the petition is liable to be dismissed for being not duly verified as per Order 6 Rule 15, CPC is concerned, the petitioner has placed reliance on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **G.M. Siddeshwar v. Prasanna Kumar as**

reported in (2013) AIR (SC) 1549, wherein it has been held that Section 83 (1) (c) of the Act of 1951 does not require an affidavit in support of the pleadings in an election petition. There is no requirement of election petitioner also of filing an affidavit in support of averments made in election petition except when the allegations of corrupt practice made.

26. Learned counsel for the petitioner has also placed reliance on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Chandrakant Uttam Chodankar v. Shri Dayanand Rayu Mandrakar & Others as reported in (2005) AIR (SC) 547**, wherein the ratio is that a defective affidavit would not entail in le-mine dismissal of election petition. Reliance has also been placed on the judgments of the Hon'ble Supreme Court in the cases of **Dr. Vijay Laxmi Sadho v. Jagdish as reported in (2001) 2 SCC 247; G. Mallikarjunappa & Another v. Shamanur Shivashankarappa & Others as reported in AIR 2001 SC 1829 and Kamalnath v. Sudesh Verma as reported in AIR 2002 SC 599.**

27. In view of such judgments of the Hon'ble Supreme Court, the election petition cannot be dismissed for technical objections like it being not duly verified or available being not as per Form 25 of Rule 94-A or for the reason that the complaint filed by the petitioner was found to be meritless by the administrative authorities. In fact, such material requires exhaustive appreciation of evidence and that could have been done only by an Election Tribunal after giving opportunity of hearing to rival parties. All these matters have been brought to the notice of the Court and rival parties have led their evidence.

28. After appreciating the evidence led by the rival parties, this Court is of the opinion that the election petition cannot be

dismissed on technicalities and the Court is obliged to advert to the merits of the case, look into the gravity of the allegations of corrupt practice, swift the evidence led by the rival parties to come to a conclusion as to whether such practices as have been alleged were found to be attributable to the rival party or not and whether there is evidence to hold that rival party is guilty of adopting such corrupt practices as are enumerated and alleged as per the provisions contained in the Act of 1951. Therefore, this Court is of the opinion that issue no.5 needs to be answered in negative to the effect that the election petition is not liable to be dismissed on any of the reasons mentioned in issue no.5.

29. Now, **issues no.1 and 2** are taken up simultaneously. Issue no.1 deals with adoption of corrupt practices as enumerated in Sections 100 (1) (b) and (d) (iv), 123 (3-A) and 123 (4) of the Act of 1951. Before adverting to the records and evidence, which have been produced by the rival parties, it will be appropriate to reproduce the relevant provisions :-

> **"100. Grounds for declaring election to be void.—**
>
> (1) Subject to the provisions of sub-section (2) if the High court is of opinion—
>
> (a) xxx
>
> (b) that any corrupt practice has been committed by a returned candidate or his election agent or by any other person with the consent of a returned candidate or his election agent; or
>
> (c) xxxx
>
> (d) that the result of the election, in so far as it concerns a returned candidate, has been materially affected—
>
> (i) xxx
>
> (ii) xxx
>
> (iii) xxx

(iv) by any non-compliance with the provisions of the Constitution or of this Act or of any rules or orders made under this Act, the High Court shall declare the election of the returned candidate to be void.

123. Corrupt Practice : The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act :-

(3A) The promotion of, or attempt to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community, or language, by a candidate or his agent or any other person with the consent of a candidate or his election agent for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate.

(4) The publication by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent, of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate or in relation to the candidature, or withdrawal, of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate's election."

30. It is the contention of the learned counsel for the petitioner that circulation of pamphlets 'karara Jawab', 'Batao Main Kaun Hun' and 'Jo moda to Bigad Gayo' amounted to character assassination of the petitioner and they were published to otherwise tarnish brilliant image of the petitioner. In support of these charges, the petitioner examined PW1 Pappu Sahu, PW2 Muneem Khan, PW3 Dr. Rakesh Sharma, PW4 Vijay Sharma, PW5 Vinod Baghel, PW6 Vinod Jain, PW7 O.P. Sharma, PW8 Ramesh Yadav, PW9 Swadesh Jain and PW10 petitioner himself.

31. PW1 Pappu Sahu deposed that the pamphlet 'Yeh moda Bigad Gayo' was distributed by Prakash and Vishal Rawal. He had

read material 2-3 days prior to the date of voting. However, in cross-examination, he admitted that he is not aware as to whether Vishal Rawal is a BJP worker or not. Ashok Rawal is uncle of Vishal Rawal and Ashok Rawal is distributing mid-day meals through self-help groups. He also admitted that he is not aware that as to which party, Vishal Rawal belongs. He further admitted that he had not seen Govind Upadhyay in his colony on the date of distribution of pamphlet. His brother Suresh Upadhyay was also not present at the time of distribution of the pamphlet. He further admitted that his wife was a Councilor for the local body.

32. Similarly, PW2 Muneem Khan in his examination-in-chief admitted that he is not adequately educated, therefore, he had not read the pamphlet, however, he alleged that such pamphlets were distributed by Sunil and Mukesh at the instance of Congress Party. However, in cross-examination, he admitted that his wife contested the election for Councilor on the ticket of BJP. He further admitted in his cross-examination that Ashok Rawal is uncle of Vishal Rawal and Ashok Rawal is a senior worker of BJP. He also admitted that he is not aware as to what was written in the pamphlet. He also admitted that despite knowing the contents of the pamphlet, he had not changed his mind and had casted his vote in favour of the petitioner. He could not read any cogent evidence to point out that the persons, who allegedly distributed the pamphlets, have any nexus or relationship with respondent no.1.

33. PW3 Dr. Rakesh Sharma and PW4 Vijay Sharma are officials, who were called with the original records. PW3 Dr. Rakesh Sharma categorically deposed that Om Prakash Sharma had lodged a complaint on 27.11.2013 and that complaint was

found to be baseless. He further deposed that another complaint was made by Swadesh Kumar Jain of BJP Mandal Lateri, which too was investigated and it was found that no cognizable offence was committed.

34. Similarly, so far as PW4 Vijay Sharma, SDM Sironj is concerned, he only deposed about available record.

35. PW5 Vinod Baghel deposed that he is a worker of BJP for last 06 years. He is Vice-President of Youth Wing of BJP and further deposed that Toran had distributed pamphlets, but he has not been able to identify said Toran because though he submitted in his affidavit under Order 18 Rule 8, CPC that the said material was distributed by Toran Singh son of Deo Chand Ahirwar, who is a worker of respondent no.1, but in cross-examination, he admitted that he does not know the name of father of Toran and at the time of preparation of affidavit under Order 18 Rule 4, CPC, he had not given the name of father of Toran to the counsel who prepared the affidavit.

36. PW6 Vinod Jain has admitted in para 15 of his cross-examination that he had not asked Toran as to who got this material distributed; whereas in the affidavit under Order 18 Rule 4, CPC, it is mentioned that Toran had distributed such pamphlets at the instance of respondent no.1-Govardhan Upadhyay and his agent. In para 6 of the affidavit, it is mentioned that such illegal material was distributed in Sironj by Vishal Rawal and other workers of the Congress Party at the instance of respondent no.1, but in cross-examination in para 14, this witness has admitted that Vikas Rawal and Vishal Rawal are two different persons and he had given the name of Vikas Rawal in his affidavit and the same has been mentioned in the affidavit; whereas in para 6 of the affidavit, the name of Vishal Rawal is mentioned

and not that of Vikas Rawal.

37. PW7 O.P. Sharma has admitted that on 24.11.2013, he had made a complaint at the instance of his workers and prior to making of such complaint, he had seen Ashish Bhrugu, Ashok Jain son of Nathulal Jain, Kanhaiyaram Yadav and Rakesh Sharma distributing the pamphlets. However, when he was asked whether such names were mentioned in the election petition or not, then after going through the election petition, he admitted that such names were not mentioned in the election petition. In para 20, he admitted that respondent no.1-Govardhan Upadhyay won election because he had a good image and there were no allegations or charges on him. In para 17, he admitted that in Ex.P/25 he did not make any mention about effect of such material on election because the election was far away; whereas the fact is that the election took place only a day after the date on which Ex.P/25 complaint was lodged.

38. PW8 Ramesh Yadav admitted that at the time of incidence of distribution of pamphlets, Govardhan Upadhyay was not present. He admitted that he is not aware as to who was the election agent of respondent no.1; whereas in his affidavit in para 7, he has made an allegation against respondent no.1-Govardhan Upadhyay that he had distributed such pamphlets and material.

39. PW9 Swadesh Jain admitted that on 08.01.2014, a complaint was made to the SDM. He admitted in his cross-examination that he had not made any complaint as to collusion between respondent no.1 and Mahendra Singh Pawar. He also admitted that in Ex.D/1, no person was named in the complaint. He also admitted that alongwith his complaint (Ex.D/1), no pamphlet or newspaper was attached.

40. PW10 Laxmikant Sharma has though in para 6 mentioned

that such illegal material to effect election was distributed between 20.11.2013 and 24.11.2013 by Toran Singh, Vishal Rawal, Ashok Jain, Kanhalyalal Yadav, Rakesh Sharma, Ashish Bhrugu and other Congress workers at the instance of Govardhan Upadhyay, but admitted in his cross-examination that he is aware of the fact that registration of newspapers takes place with Publicity Department. He was Minister of Publicity Department. He had not made any complaint to the Publicity Department in regard to a newspaper being distributed without any registration number. He also admitted that the Police had found his complaint to be baseless, but such information was received by him after getting reply to the election petition. He also admitted that Govardhan Upadhyay was not present at the time of distribution of such pamphlets.

41. In this backdrop, the learned counsel for the respondents submits that the consent of candidate or election agent is material and mere distribution of some material is not sufficient to form corrupt practice in terms of the provisions contained in Section 100 (1) (d) (ii) of the Act of 1951. Similarly, requirement of Section 123 (4) of the Act of 1951 provides for publication by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to constitute a corrupt practice has not been proved. It is submitted that adverse inference should be drawn when petitioner's two cited witnesses, namely, Sunil son of Rajendra Yadav and Mukesh son of Nandkishore Sen against whom there was allegation in regard to distribution of pamphlets were given up on 08.05.2017 by the learned counsel for the election petitioner. Once the witnesses were cited and they have been given up, then adverse inference is to be drawn in the light of the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in

the case of **Vidyadhar v. Manikrao & Another as reported in AIR 1999 SC 1441,** wherein the law is that where a party to the suit does not step into the witness-box and states his own case on oath and does not offer himself to be cross-examined by other side, a presumption would arise that the case set up by him is not correct.

42. Similarly, in the case of **M.J. Jacob v. A. Narayanan & Others as reported in (2009) 14 SCC 318** in para 26, it has been held as under :-

> "**26.** It is now well settled that the five ingredients required to establish a corrupt practice under Section 123(4) of the Act are:
>
> (*i*) there should be a publication by the candidate or his agent, or by any other person, with the consent of a candidate or his election agent;
>
> (*ii*) the said publication should contain a statement of fact which is false;
>
> (*iii*) the person making such publication should either believe such statement to be false or not believe it to be true;
>
> (*iv*) such false statement should be in relation to the personal character or conduct of any candidate; and
>
> (*v*) such false statement should reasonably be calculated to prejudice the prospects of that candidate's election.
>
> There is thus no doubt that any false accusation relating to the personal character or conduct of any candidate calculated to prejudice the prospect of his election would amount to a corrupt practice. But what is crucial is that the false statement should relate to the personal character or conduct of a defeated *candidate.* Where the false statement was about someone other than the candidate, this Court has refused to consider the publication to be a corrupt practice under Section 123(4).
>
> **40.** As already stated above, election results

> should not be lightly set aside and the will of the electorate should ordinarily be respected. Setting aside an election is a serious matter, and should not have been done lightly. We regret to say that in this case the election of the returned candidate has been set aside by the High Court, though no doubt by a rather elaborate judgment, by observing, according to us unwarrantedly, that Para 2 in Ext. P-1 amounts to a false statement affecting the personal character and conduct of Shri T.M. Jacob."

43. Therefore, the onus was on the petitioner to have pointed out that such publication was by the candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent. It has been admitted that Vishal Rawal is nephew of Ashok Rawal, who is a senior BJP leader. Petitioner gave up two of his witnesses against whom allegations were made that they distributed pamphlets at the instance of respondent no.1. PW3 Dr. Rakesh Sharma, SDM deposed that the complaint was examined and was found to be frivolous. PW7 Om Prakash Sharma admitted that he had not made any follow up action after making the complaint. PW10 Laxmikant Sharma election petitioner admitted that he had discovered the outcome of the complaint only from the written statement filed in the election petition. No appeal or revision was filed against dismissal of the complaint. PW6 Vinod Jain in para 12 admitted that Toran did not disclose the source of original newspaper. Similarly, affidavit of PW5 Vinod Baghel and PW6 Vinod Jain are identical from para 3 to para 8. PW5 Vinod Baghel in para 7 alleged that respondent no.1 had distributed the pamphlets, which is contrary to the pleadings in the petition. PW5 Vinod Baghel has been cited as a witness for the incident, which took place in Lateri. He is resident of Tahsil Lateri. In para 6 of the election petition, it is mentioned that 'Karara Jawab' was distributed on 23.11.2013 between 1.00

to 1.30 PM and election petitioner cites Toran Ahirwar as a distributor; whereas contrary to this, PW5 Vinod Baghel has narrated that it was Vishal Rawal and Govardhan Upadhyay who distributed such pamphlets. Similarly, there is another material omission that though in the affidavit Vinod Baghel has given name of father of Toran Ahirwar, but in para 14 of his cross-examination, he admits that he had not given the name of father of Toran Ahirwar to his lawyer, which demonstrates that the affidavit under Order 18 Rule 4, CPC was not prepared as per his instructions, but was a brain child of the lawyer and such evidence is not sufficient to set aside the election. He is also an interested witness being a worker of Bhartiya Janata Party.

44. PW5 Vinod Baghel admitted that Toran had distributed the pamphlets between 1.00 to 1.30 PM whereas PW6 Vinod Jain deposed that such pamphlets were distributed at night. There is also contradiction inasmuch as in the affidavit, the name of Vishal Rawal is mentioned whereas in cross-examination, he admits that he had given name of Vikas and not of Vishal. It has also come on record that Toran had not disclosed the name of any person at whose instance he had distributed such pamphlets. In fact, it has come in the deposition that he is not aware of the fact that such pamphlets were distributed at the instance of respondent no.6. He also admitted that he is a BJP worker and had come to depose at the instance of the election petitioner.

45. PW8 Ramesh Yadav has given certain names in paragraphs 10 and 15, which are not mentioned in the election petition though they are mentioned in Ex.P/25. Affidavits of PW8 Ramesh Yadav and PW9 Swadesh Jain are verbatim identical from para 3 to para 8. Reasons for such omissions are not explained as to when names of perpetrators of alleged mischief were known to

them why they were not mentioned in the election petition. In para 9 of the election petition, there is a mention that papers were distributed between 10.00 AM to 12.00 Noon on 24.11.2013 and such intimation was given to PW8 Ramesh Yadav, who in para 16 has given timing of distribution of phamplets as 12.00 and 1.00 PM. In para 19, he admits that such news will impact or influence the election if it is correct. He also admitted in para 20 of his cross-examination that respondent no.1 won the election as he had a better image. PW9 Swadesh Jain admitted that he had only made one complaint (Ex.D/1) and there are no names mentioned in Ex.D/1 as to who distributed the pamphlets. There were admittedly no enclosures and the word used in Ex.D/1 is 'candidates' and there is no specific allegation in regard to respondent no.1, the returned candidate.

46. Referring to all such decisions and the judgment of the case of **M.J. Jacob (supra)**, attention is invited to para 40 of the judgment, which says that election results should not be lightly set aside and the will of the electorate should ordinarily be respected. Setting aside the election is a serious matter and should not have been done lightly.

47. Similarly, reliance has been placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **R.P. Moidutty v. P.T. Kunju Mohammad & Another as reported in AIR 2000 SC 388**, wherein in para 14, the Hon'ble Supreme Court has observed that it is basic to the law of elections and election petitions that in a democracy, the mandate of the people as expressed at the hustings must prevail and be respected by the Courts and that is why the election of a successful candidate is not to be set aside lightly. Heavy onus lies on the election petitioner seeking setting aside of the election of a successful

candidate to make out a clear case for such relief both in the pleadings and at the trial.

48. Reliance has also been placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Ravinder Kumar Sharma v. State of Assam & Others as reported in AIR 1999 SC 3571**, wherein the ratio of the judgment in para 25 is that the presumption of genuineness attached under Section 81 of the Evidence Act to newspaper reports cannot be treated as proof of the facts stated therein.

49. Reliance has also been placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Laxmi Raj Shetty & Another v. State of Tamil Nadu as reported in AIR 1988 SC 1274**, wherein the ratio is that in terms of the provisions contained in Sections 57, 78(2) and 81 of the Evidence Act, facts stated in a newspaper are hearsay in nature and inadmissible unless maker of statement is examined. Judicial notice of facts stated in the newspaper cannot also be taken.

50. Reliance has also been placed on the judgment of this Court in the case of **Radheshyam Dhakad v. Jaiwardhan Singh & Others E.P.No.05/2014** decided on 12.09.2017, wherein in para 44, it has been held that a newspaper report without any further proof of what had actually happened to witnesses is of no value. It is at best second in secondary evidence.

51. Reliance has been placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **P.C. Thomas v. P.M. Ismail & Others as reported in (2009) 10 SCC 239**, wherein in para 42 it has been held that it is well settled that if after balancing the evidence adduced, there still remains little doubt in proving the charge, its benefit must go to the returned candidate.

However, it is equally well settled that while insisting upon the standard of proof beyond a reasonable doubt, the Courts are not required to extend or stretch the doctrine to such an extreme extent as to make it well-nigh impossible to prove any allegation of corrupt practice.

52. It is also well settled law that evidence beyond pleadings needs to be ignored as has been held by the Hon'ble Supreme Court in para 24 in the case of **Kattinokkula Murali Krishna v. Veeramalla Koteswara Rao & Others_as reported in (2010) 1 SCC 466.**

53. Learned counsel for the petitioner, on the other hand, has placed reliance on the judgment of Delhi High Court in the case of M/s. Rudnap Export-Import v. Eastern Associates Co. & Others as reported in AIR (1984) Delhi 20, wherein relying on Section 61 of the Evidence Act, it has been held that the document filed by one party, other party can rely upon it without any proof. Where a document is filed by one party, it can be looked into at the instance of opposition party. In such a case, there is no need of proof of such a document.

54. Reliance has been placed on the judgment of the Hon'ble Supreme Court in the case of **Prabhu Narayan v. A. K. Srivastava as reported in (1975) AIR (SC) 968**, wherein in para 13, the Hon'ble Supreme Court has held that relying on the evidence of PW66 and PW67 about the part played by the respondent with regard to the pamphlets printed in Chhabi Printing Press and of Kailash Chandra Nakra with regard to the pamphlets printed in Kailash Press holding that the Supreme Court was convinced beyond reasonable doubt that the respondent was the guiding brain and hand behind all of them.

55. Placing reliance on such judgments, the learned counsel for

the petitioner has tried to emphasis that in the present case guiding hand behind the pamphlets, namely, 'Karara Jawab', 'Batao Mein Kau Hoon' and 'Jo Moda To Bigad Gayo', was of respondent no.1 alone and, therefore, his election should be set aside as it amounted to correct practice.

56. As far as the corrupt practice as narrated in Section 100 (1) (b), (d) (iv), 123 (3-A) and 123 (4) of the Act of 1951 is concerned, the onus was on the petitioner to have shown direct nexus between publications and respondent no.1. After going through the evidence of the rival parties, which has been discussed above and for the sake of brevity, is not being repeated again, the petitioner has failed to discharge the burden that such material was either published or distributed at the instance of respondent no.1.

57. As far as the law laid down in the case of **M/s. Rudnap Export-Import (supra)** is concerned, Section 61 of the Evidence Act only provides for proving of contents of documents either by primary or by secondary evidence. Production of document in the hands of the respondents only proves that such document exists. Learned counsel for the respondents has submitted that such documents were obtained by him under the Right to Information Act and they are not of his own making. Therefore, the onus to prove such documents was still on the petitioner by examining the concerned editor, publisher or author of such publication. PW7 Om Prakash Sharma has categorically admitted that public accepts only what is perceived to be correct. Witnesses from the petitioner's side have admitted that despite publication of such material, they had casted their vote in favour or the petitioner. Coupled with this fact that the petitioner at the relevant point of time was Minister for Publicity Department and

did not make any complaint or did not take any pains to verify whether such newspaper is registered with the Department or the Registrar of Newspapers and who are the persons behind such newspaper and from where such newspaper was published, has utterly failed to discharge the burden that such newspaper/pamphlet was published and circulated at the instance of respondent no.1. In fact, in the light of the law laid down in the case of Laxmi Raj Shetty (supra), it was incumbent upon the petitioner to have examined maker of statement.

58. In fact, the allegations were initially against Toran Ahirwar and the petitioner's witnesses, namely, PW5 Vinod Baghel and PW6 Vinod Jain have mechanically mentioned the name of the father of Toran Ahirwar in their affidavits. In cross-examination, they both have admitted of not disclosing the name of father of Toran Ahirwar to their counsel. Such kind of mechanical drafting of affidavits demonstrates that the affidavits in lieu of oral evidence under Order 18 Rule 4, CPC were prepared not under the instructions of the deponents, but the deponents were made to sign on it.

59. It has also come on record that two of the persons, namely, Sunil and Mukesh, against whom allegations were made, were cited as petitioner's witnesses,but were given up vide order dated 08.05.2017. It has also come on record that Vishal Rawal's uncle is senior worker of BJP. Allegations have been made against Vishal Rawal of distributing certain pamphlets at the instance of respondent no.1. One of the witnesses has categorically admitted that he had given name of Vikas Rawal and not of Vishal Rawal. This again demonstrates that there is lack of coherence in the allegations, pleadings and evidence which has been brought on record. Petitioner cannot be permitted to take the advantage of

his own shortcomings and mistakes and, therefore, the evidence of his witnesses, which is contrary to the pleadings, contradictory and admittedly not as per their instructions, cannot be made a basis to hold that corrupt practice was performed by respondent no.1. Therefore, it is apparent that there is inadequacy of evidence produced by the election petitioner in order to discharge the onus to prove the corrupt practice alleged. In fact, the Hon'ble Supreme Court in the case of **M. J. Jacob (supra)** in para 40 has laid down that the election result should not be lightly set aside and the will of the electorate should ordinarily be respected. Setting aside the election is a serious matter and should not have been done lightly. Even five ingredients mentioned in the case of **M.J. Jacob (supra)** have not been proved. Merely, the margin of victory between the petitioner and respondent no.1 being thin is not sufficient ground to hold that certain material brought on record was published and circulated at the instance of respondent no.1. In absence of any such nexus between the material published and distributed and respondent no.1, the onus of which was on the petitioner to establish, it cannot be held that respondent no.1 adopted corrupt practice as narrated in Section 100 (1) (b) (d) (iv), Section 123 (3-A) and Section 123 (4) of the Act of 1951. Similarly, since this Court has held that such petitioner has since failed to show that such material was circulated in Tahsil Sironj on 23.11.2013 on the directions of respondent no.1, it cannot be held that such material amounted to character assassination of the petitioner. In fact in the light of the judgment in the case of **P.C. Thomas (supra)**, the benefit is to be given to the Returned Candidate. Therefore, issues no. 1 and 2 are to be decided in negative and are decided as such.

60. **Issue no.6** is whether the petition is frivolous and vexatious and hence the same can be dismissed imposing exemplary cost under Section 35-A CPC. Section 35-A of CPC deals with compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences. It reads as under :-

> **"35-A. Compensatory costs in respect of false or vexatious claims or defences.-** (1) If in any suit or other proceeding, including an execution proceeding but excluding an appeal or a revision, any party objects to the claim or defence on the ground that the claim or dénce or any part of it is, as against the objector, false or vexatious to the knowledge of the party by whom it has been put forward, and if thereafter, as against the objector, such claim or defence is disallowed, abandoned or withdrawn in whole or in part, the Court, if it so thinks fit, may, after recording its reasons for holding such claim or defence to be false or vexatious, make an order for the payment to the objector by the party by whom such claim or defence has been put forward, of costs by way of compensation."

61. Reading of Section 35-A of CPC in consonance with the pleadings in the petition leads to a primary impression that though the petitioner has failed to prove corrupt practices as narrated under Section 100 (1) (b) (d) (iv), Section 123 (3-A) and Section 123 (4) of the Act of 1951, but at the same time, before awarding costs, the Court is to satisfy itself that the claim was false or vexatious to the knowledge of the party, the interest of justice require awarding of such costs; but where evidence on record is merely found insufficient to prove a corrupt practice, it cannot be said that the plea raised by the petitioner were false or vexatious in totality and did not provide initial impetus to contest on the basis of such material. Neither any vexatious motive has been proved nor the respondent has proved that the pleadings of

the petitioner were altogether groundless. Therefore, in view of such existing facts, grant of compensatory costs will not be within the domain of the provisions of Section 35-A, CPC. Therefore, this Court has decided issues no.1 and 2 against the election petitioner, but at the same time it is of the opinion that there is no sufficient material to hold the election petition to be frivolous and vexatious resulting in grant of compensatory costs as envisaged under Section 35-A, CPC, therefore, this issue is answered in negative and plea for payment of compensatory costs is negatived.

62. **Relief and costs :** In view of the aforesaid discussions, this election petition deserves to be dismissed for the reasons that the petitioner has failed to prove involvement of respondent no.1 in corrupt practices as defined in the Representation of the People Act, 1951. The petitioner has filed to prove consent of respondent no.1 as is envisaged under Section 100 (1) (b) or 100 (1) (d) (iv) of the Act of 1951. Similarly, no case is made out under Section 123 (3-A) of the Act of 1951 of attempting to promote, feelings of enmity or hatred between different classes of the citizens of India on grounds of religion, race, caste, community, or language. Even on the grounds under Section 123 (4) of the Act of 1951 showing that there was any publication by respondent no.1 or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent materially affecting the result of the election, the petitioner has failed to prove his case against respondent no.1 or any other respondents. Thus, the petition is dismissed. However, the parties shall bear their own costs.

Sd/-
(VIVEK AGRAWAL)
Judge
29-06-2018

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1–2/2017/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से राजगढ़ जिले की तहसील ब्यावरा की सीमाएं, उसमें से राजस्व निरीक्षक वृत सुठालिया के पटवारी हल्का क्रमांक 41 से 71 एवं राजस्व निरीक्षक वृत मलावर के पटवारी हल्का क्रमांक 72 से 75, 78 एवं 100 से 111 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और राजस्व निरीक्षक वृत सुठालिया के पटवारी हल्का क्रमांक 41 से 71 एवं राजस्व निरीक्षक वृत मलावर के पटवारी हल्का क्रमांक 72 से 75, 78 एवं 100 से 111 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील सुठालिया का सृजन करती है, जिसमें 48 पटवारी हल्के और 131 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय सुठालिया में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ–1–2–2017–सात–शा.–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–2–2017–सात–शा.–6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-2/2017/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Biaora of District Rajgarh from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 41 to 71 of Revenue Circle Suthaliya and 72 to 75, 78 and 100 to 111 of Revenue Circle Malawar and creates a new Tehsil Suthaliya by comprising of Patwari Halka No. 41 to 71 of Revenue Circle Suthaliya and 72 to 75, 78 and 100 to 111 of Revenue Circle Malawar, which shall be comprised of 48 Patwari Halkas and 131 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Suthaliya.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1–4/2017/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, राजगढ़ जिले की तहसील राजगढ़ की सीमाएं, उसमें से रा0नि0मं0 खुजनेर के प0ह0नं0 63 से 103 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और रा0नि0मं0 खुजनेर के प0ह0नं0 63 से 103 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील खुजनेर का सृजन करती है, जिसमें कुल 41 पटवारी हल्के और 97 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय खुजनेर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ–1–4–2017–सात–शा.–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–4–2017–सात–शा.–6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-4/2017/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Rajgarh of District Rajgarh from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 63 to 103 of Revenue Circle Khujner and creates a new Tehsil Khujner by comprising of Patwari Halka No. 63 to 103 of Revenue Circle Khujner, which shall be comprised of 41 Patwari Halkas and 97 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Khujner.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1–5/2018/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, उज्जैन जिले की तहसील तराना की सीमाएं, उसमें से प0ह0नं0 01 से 48 एवं 52 से 54 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और प0ह0नं0 01 से 48 एवं 52 से 54 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील माकडौन का सृजन करती है, जिसमें कुल 51 पटवारी हल्के और 102 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय माकडौन में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ–1–5–2018–सात–शा.–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–5–2018–सात–शा.–6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-5/2018/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Tarana of District Ujjain from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 48 and 52 to 54 and creates a new Tehsil Makdon by comprising of Patwari Halka No. 01 to 48 and 52 to 54 which shall be comprised of 51 Patwari Halkas and 102 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Makdon.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1–7/2013/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, कटनी जिले की तहसील बहोरीबंद एवं ढीमरखेड़ा की सीमाएं, उसमें से तहसील बहोरीबंद के रा0नि0मं0 स्लीमनाबाद के प0ह0नं0 55 से 79 तक कुल 25 तथा तहसील ढीमरखेड़ा के रा0नि0मं0 उमरियापान के प0ह0नं0 1 से 10 तक कुल 10, इस प्रकार कुल 35 पटवारी हल्के जिनमें 81 ग्राम होंगे, अपवर्जित होकर नवीन प्रस्तावित तहसील स्लीमनाबाद में सम्मिलित होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय स्लीमनाबाद में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ-1-7-2013-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-7-2013-सात-शा.-6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-7/2013/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Tehsil Bahoriband and Dhimarkheda of District Katni from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom 25 Patwari Halkas of Revenue Circle Sleemnabad and 10 Patwari Halkas of Revenue Circle Umariyapan and create a new Tehsil Sleemnabad by comprising of 1 to 10 total 10 Patwari Halkas of Revenue Cercle Umariyapan and total 35 and Village shall be 81. The headquarter of the said Tehsil shall be at Sleemnabad.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1–8/2017/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, रायसेन जिले की तहसील उदयपुरा की सीमाएं, उसमें से प0ह0नं0 40 से 42 एवं प0ह0नं0 45 से 69 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और प0ह0नं0 40 से 42 एवं प0ह0नं0 45 से 69 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील देवरी का सृजन करती है, जिसमें कुल 28 पटवारी हल्के और 73 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय देवरी में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

एफ–1–8–2017–सात–शा.–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–8–2017–सात–शा.–6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-8/2017/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Udaipura of District Raisen from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 40 to 42 and Patrari Halka No. 45 to 69 and creates a new Tehsil Deori by comprising of Patwari Halka No. 40 to 42 and Patrari Halka No. 45 to 69 which shall be comprised of 28 Patwari Halkas and 73 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Deori.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1–10/2016/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, धार जिले की तहसील धार की सीमाएं, उसमें से रा0नि0मं0 नालछा एवं सागौर के प0ह0नं0 46 से 49, 56 से 73 एवं 76 से 86 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और रा0नि0मं0 नालछा एवं सागौर के प0ह0नं0 46 से 49, 56 से 73 एवं 76 से 86 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील पीथमपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 33 पटवारी हल्के और 213 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय पीथमपुर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ–1–10–2016–सात–शा.–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–10–2016–सात–शा.–6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-10/2016/VII/6---- in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Dhar of District Dhar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 46 to 49, 56 to 73 and 76 to 86 of Revenue Circle Nalchha and Sagore and creates a new Tehsil Pithampur by comprising of Patwari Halka No. 46 to 49, 56 to 73 and 76 to 86 of Revenue Circle Nalchha and Sagore, which shall be comprised of 33 Patwari Halkas and 213 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Pithampur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1–12/2017/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली की सीमाएं, उसमें से प0ह0नं0 01 से 30, 33, 36 से 39 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और प0ह0नं0 01 से 30, 33, 36 से 39 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बहादुरपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 35 पटवारी हल्के और 90 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय बहादुरपुर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ–1–12–2017–सात–शा.–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–12–2017–सात–शा.–6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-12/2017/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Mungaoli of District Ashoknagar from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 01 to 30, 33, 36 to 39 and creates a new Tehsil Bahadurpur by comprising of Patwari Halka No. 01 to 30, 33, 36 to 39 which shall be comprised of 35 Patwari Halkas and 90 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Bahadurpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1–14/2017/सात/शा. 6 ------ मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर की सीमाएं, उसमें से पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 50, 52 से 68, 91 से 102 एवं 105 से 107 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और पटवारी हल्का क्रमांक 23 से 50, 52 से 68, 91 से 102 एवं 105 से 107 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील झार्डा का सृजन करती है, जिसमें 60 पटवारी हल्के और 113 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय झार्डा में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र एफ-1-14-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-14-2017-सात-शा.-6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-14/2017/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Mahidpur of District Ujjain from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 23 to 50, 52 to 68, 91 to 102 and 105 to 107 and creates a new Tehsil Jharda by comprising of Patwari Halka No. 23 to 50, 52 to 68, 91 to 102 and 105 to 107 which shall be comprised of 60 Patwari Halkas and 113 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Jharda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ. 1–2/2018/सात/शा. 6 ——— मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, शिवपुरी जिले की तहसील बदरवास की सीमाएं, उसमें से प0ह0नं0 34 से 67 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और प0ह0नं0 34 से 67 समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील रन्नौद का सृजन करती है, जिसमें कुल 34 पटवारी हल्के और 63 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय रन्नौद में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र. एफ–1–2–2018–सात–शा.–6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ–1–2–2018–सात–शा.–6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-2/2018/VII/6---- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Badarwas of District Shivpuri from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 34 to 67 and creates a new Tehsil Rannod by comprising of Patwari Halka No. 34 to 67 which shall be comprised of 34 Patwari Halkas and 63 villages.The headquarter of the said Tehsil shall be at Rannod.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
HARI RANJAN RAO, Principal Secy.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 3–84/18/18–5 :– मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 4459–वि.यो.–न.ग्रा.नि.–2017 भोपाल दिनांक 06.09.2017 द्वारा प्रकाशित भोपाल विकास योजना 2005 में उपातंरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2005 में उपांतरण नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात –

1. आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, भोपाल जिला भोपाल मध्यप्रदेश
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम भोपाल मध्यप्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय भोपाल मध्यप्रदेश

अनुसूची

1. भोपाल विकास योजना 2005 में वर्णित "क्षेत्राधिकार" की कंडिका 4.11 के पश्चात निम्न कंडिकाऐं प्रतिस्थापित की जाती है:–

   4.11–अ टी.डी.आर. (ट्रास्फरेबल डेवलपमेन्ट राइट) हस्तांतरणीय विकास अधिकार के सम्बंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होगें।

   4.11–ब टी.ओ.डी. (ट्रांजिट ओंरियण्टेड डेवलपमेंट) के सम्बंध में राज्य शासन द्वारा जो भी विधिक प्रावधान लागू किये जाते हैं, वह विकास योजना के भाग होगें।

2. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.22 की सारणी क्रमांक–4–सा–3 में उपनगरीय केन्द्र एवं सामुदायिक केन्द्र में "मल्टीप्लेक्स तथा शॉपिग माल" जोड़ा जाता है।

3. कंडिका क्रमांक–4.30 के पश्चात निम्न कंडिका स्थापित की जायें ।

   4.30–अ **शीतकेन्द्र/वेयर हाऊस के मानदण्ड**

   शीत केन्द्र/वेयर हाऊस के लिये निम्न नियमन रहेंगे ।

   - भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल–1000 वर्गमीटर
   - अधिकतम तलक्षेत्र अनुपात–1:0.40

- अधिकतम निर्मित क्षेत्र 40 प्रतिशत
- भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई– 12.0 मीटर
- सीमांत खुला क्षेत्र – 6.0 मीटर चारो ओर।

4. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.52 (2)(घ) को विलोपित किया जाता है, तथा सारणी 4–सा–2 में टीप 'ब' के पश्चात निम्नलिखित 'स' स्थापित किया जाता है ।

स: सारणी 4–सा–2 के कॉलम कमांक–1 के सरल कमांक–10 से 14 के आवासीय भूखण्डों में नर्सिंग होम एवं भोपाल विकास योजना 2005 के उपांतरण की अधिसूचना दिनांक 25.01.13 के राजपत्र अनुसार अधिसूचना की कण्डिका 14 एवं तालिका 4–सा–2 (अ) एवं 4–सा–2 (ब) के अनुसार गतिविधि निम्न उल्लेखित शर्तों के साथ स्वीकार्य होगी ।

(a) भूखण्ड का न्यूनतम आकार 372 वर्गमीटर (4000 वर्गफीट) होगा ।

(b) भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर होगी।

(c) अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात (F.A.R.) सीमांत खुला क्षेत्र (M.O.S.) एवं अधिकतम भू–आच्छादित क्षेत्र (Ground Coverage) – अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4–सा–2, 4–सा–2 (अ) एवं 4–सा–2 (ब) अनुसार होंगे।

(d) भवन की अधिकतम ऊँचाई (Maximum Height) – अंगीकृत भोपाल विकास योजना 2005 में आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य अनुसार मान्य होगी

(e) पार्किंग प्रति 75.0 वर्गमीटर निर्माण पर– 1 ई. सी. एस. (E.C.S.) यह पार्किंग व्यवस्था संस्था के प्रांगण/भवन में अथवा 1000 मीटर दायरे के अन्दर विकसित निजी/सार्वजनिक स्थल पर नगर निवेशक नगर निगम की संतुष्टि अनुसार होनी चाहिये। सार्वजनिक स्थल पर पार्किंग की व्यवस्था स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा किये जाने की दशा में प्रीमियम की राशि प्राप्त की जा सकेगी, जिसे जमा करने हेतु एक अलग मद स्थानीय संस्था द्वारा सृजित किया जायेगा। तथा इस मद में प्राप्त राशि केवल सार्वजनिक स्थल की पर्किंग व्यवस्था हेतु आहरण कर व्यय की जा सकेगी। भूखण्ड के सामने का सम्पूर्ण सीमान्त खुला क्षेत्र (M.O.S) बिना शर्त पब्लिक पार्किंग हेतु मार्ग लेवल पर पार्किंग हेतु विकसित कर उपलब्ध करना होगा। (पार्किंग हेतु गणना में इस समर्पित क्षेत्र पर विकास योजना की कंडिका 4.26 का प्रावधान लागू नहीं होगा

(f) क्लीनिक, एकल विशेज्ञता परिचर्या गृह, (Single Specialty Nursing), किसी भी आवासीय भूखण्ड पर केवल भूतल पर 25 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर जो भी कम हो तक ही स्वीकार्य होगी।

(g) यदि विद्यमान भवन उपरोक्त नियम में दिये गये मापदण्ड पूरा करता है, तो संबंधित प्राधिकारी भवन अधिभोग परिवर्तन के लिये स्थानीय निकाय द्वारा अधिसूचित एकमुश्त अधिभोग परिवर्तन शुल्क एवं वार्षिक परिवर्तन शुल्क लेकर चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की अनुमति दे सकेगा।

(h) उपरोक्त ये नियम राजपत्र में प्रकाशित तिथि पर विद्यमान नर्सिंग होम एवं क्लीनिक के नियमितिकरण हेतु लागू होंगे। इस दिनॉक के पश्चात स्थापित होने वाले नवीन नर्सिंग होम एवं क्लीनिक का नियमितिकरण नहीं हो सकेगा।

5. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.57 की सारणी 4–सा–17 के क्रमांक 29 के पश्चात क्रमांक–30 स्थापित किया जाता है।

30. विवाह पार्क (मेरिज गार्डन) उपरोक्त गतिविधि समस्त वाणिज्यिक उपयोग क्षेत्रों में मान्य होगी।	P	P	P	NP	NP

6. भोपाल विकास योजना 2005 के अध्याय–4 के पैरा 4.56 के अन्य नियंत्रण (2) के पश्चात कण्डिका 4.56 (क) स्थापित किया जाता है ।

4.56 (क) फार्म हाउस, कृषि पर्यटन सुविधा, विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), पटाखा दुकान/गोदाम, मल्टीप्लेक्स, शापिंग मॉल, खुला मॉल के नियमन :–

(i) वन आवास (फार्म हाऊस):–
वन आवास के नियमन मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के अनुरूप होंगे ।

(ii) कृषि पर्यटन सुविधा :–
कृषि पर्यटन सुविधा के नियमन मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 (क) के अनुरूप होंगे ।

(iii) विवाह पार्क (मेरिज गार्डन):–
विवाह पार्क (मेरिज गार्डन)के नियमन मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3) (तीन) के अनुरूप होंगे ।

(iv) पटाखा दुकान/गोदाम :–
(a) न्यूनतम भूमि का क्षेत्रफल– 100 वर्गमीटर
(b) भूतल कव्हरेज अधिकतम– 30 प्रतिशत
(c) एफ. ए. आर. : 1:0.30
(d) अधिकतम ऊँचाई– 4.5 मीटर
(e) न्यूनतम खुला क्षेत्र– सामने 3.0 मीटर एवं अन्य तीनों ओर 1.5 मीटर

टीप :– 1. अग्नि सुरक्षा/विस्फोटक नियमन हेतु लागु सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. ग्रामीण आबादी से पटाखा व्यवसाय की न्यूनतम दूरी 0.5 किलोमीटर होगी अथवा जिला प्रशासन द्वारा लागु नियमन मान्य होगें।

(v) मल्टीप्लेक्स– मल्टीप्लेक्स के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुरूप होगें। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4–सा–2 (अ) एवं सारणी 4–सा–2 (ब) से नियत्रित होगी।

(vi) शॉपिग माल– शॉपिग माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के अनुरूप होगें। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4–सा–2 (अ) एवं सारणी 4–सा–2 (ब) से नियत्रित होगी।

(vii) खुला माल– खुला माल के नियम (फर्शी क्षेत्रानुपात को छोड़कर) म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 96 के अनुरूप होगें। फर्शी क्षेत्रानुपात भोपाल विकास योजना की सारणी 4–सा–2 (अ) एवं सारणी 4–सा–2 (ब) से नियत्रित होगी।

7. भोपाल विकास योजना 2005 की कंडिका 4.35 की सारणी 4–सा–9 को विलोपित करते हुए इसके स्थान पर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप सारणी 6 लागू होगी । साथ ही भोपाल विकास योजना 2005 की सारणी 4–सा–8 जो मध्य प्रदेश राजपत्र भाग–1 दिनांक 25 जनवरी 2013 के सरल कमांक–19 में/के द्वारा विलोपित किया गया था उसे यथावत पुर्नस्थापित किया जाता है ।

8. **(i)** कंडिका कमांक–4.61, ए–3 कृषि परिक्षेत्र (ए–2 सहित) में "सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सेवाए" के स्थान पर "कण्डिका कमांक 4.35 सामाजिक अधोसरंचना के मानक की सारणी 4–सा–8 के कॉलम कमांक–2 में "प्रकार" के रूप में वार्णित है," को प्रतिस्थापित की जाती है।

(ii) कंडिका कमांक–4.61, ए–3 कृषि परिक्षेत्र (ए–2 सहित) में चारागाह एवं वृक्षारोपण के पश्चात फार्म हाउस (वन आवास) जोड़ा जाये तत्पश्चात निम्न नवीन कण्डिका जोड़ी जाती है :–

निम्न गतिविधियॉ कृषि भू उपयोग (निवेश क्षेत्र में बड़े तालाब के केचमेंट के ग्रामों को छोड़कर) में मान्य होगी–

कृषि पर्यटन सुविधा, पटाखा दुकान/गोदाम, खुला मॉल एवं विवाह पार्क (मैरिज गार्डन)।

विकास योजना में किया गया उपांतरण मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.